R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 07
01 से 15 जनवरी 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

मप्र में कालेधन के कुबेरों की खुली पोटली

नेता-अफसर-बिल्डर की जुगलबंदी...!

लोकायुक्त, आयकर, ईडी और डीआरआई खंगाल रहे खेल

काली कमाई के और कितने कुबेर... मप्र में मची रेलमपेल

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

विवाद

8 | एक और कॉर्पोरेशन पर लगेगा ताला

करीब 63 साल पहले गठित मप्र लघु उद्योग निगम पर ताला लगेगा। यानि तिलहन संघ, बुनकर सहकारी संघ, राज्य परिवहन निगम, भूमि विकास बैंक और कुक्कुट महासंघ की तरह यह कॉर्पोरेशन भी बंद होगा। एक हजार करोड़ के...

डायरी

10-11 | कोठारी-नरहरि...

मप्र के 82 आईएएस अफसरों को डॉ. मोहन यादव की सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। अलग-अलग बैच के आईएएस का प्रमोशन करते हुए बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रमोशन की...

योजना

13 | केन-बेतवा की नहर...

पानी की कमी से पलायन की मार झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों की मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली ऐतिहासिक परियोजना से यहां के 10 जिलों को इस समस्या से निजात मिलेगी। यहां के ज्यादातर किसान पानी के...

यादें

18 | इकोनॉमी के डॉक्टर...

देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से शोक में है। देश में सात दिन का राष्ट्रीय शोक है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्षी कांग्रेस और अन्य पार्टियों तक, तमाम शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर सिंह के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

वर्ष 2024 की विदाई बेला में यानि दिसंबर महीने में लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापों ने कालेधन के कुबेरों की पोटली खोल दी है। प्रदेश में कुछ साल पहले तक जिसके सामने जीवन-यापन की समस्या थी, आज काली कमाई से वे कुबेर बन बैठे हैं। प्रदेश में काली कमाई किस हद तक हो रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आयकर, लोकायुक्त, ईडी और केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) नेता-अफसर-बिल्डर की जुगलबंदी खंगालने में जुट गई हैं।

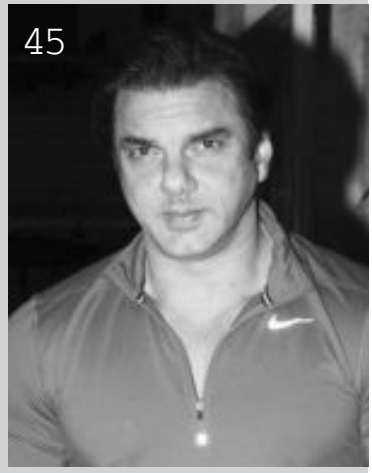

राजनीति

30-31 | नसीहत पर गौर करें...

इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस से अलगाव का रुझान और आगे बढ़ा है। अब नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन का नेता बने रहना चाहती है, तो उसे यह स्थान मेहनत से कमाना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने ईवीएम में हेरफेर को लेकर रोने की प्रवृत्ति से कांग्रेस को...

महाराष्ट्र

35 | मंत्री पद को तरसे भुजबल

छगन भुजबल एक वक्त में महाराष्ट्र के दूसरे नंबर के नेता थे। भुजबल महाराष्ट्र के दो बड़े नेता शरद पवार और बालासाहेब ठाकरे के साथ काम कर चुके हैं। 5 मुख्यमंत्री के साथ भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें फडणवीस कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है।

बिहार

38 | पलटी, एंट्री और धमकी

जब-जब देश में राजनीति की बात होती है, तब-तब लोगों को बिहार जरूर याद आता है। आखिर अपना बिहार है ही इतना खास। बिहार के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को राजनीति में खूब दिलचस्पी होती है। इसके कुछ कारण भी हैं, और वो हैं बिहार के राजनेता।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-07, पृष्ठ-48
1 से 15 जनवरी, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

मैं जहर हूं...जानलेवा कहर हूं...!

शा*यर नक्श लायलपुरी का एक शेर है....*

जहर देता है कोई... कोई दवा देता है
जो भी मिलता है, मिरा दर्द बढ़ा देता है...

कुछ इसी तरह की स्थिति भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के जहरीले कचरे की है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी और 5 लाख से अधिक लोग सेहत संबंधी समस्याओं और विकलांगताओं से ग्रसित हो गए थे। तब से अब तक फैक्ट्री बंद पड़ी है और कचरा भोपाल के सीने पर बोझ की तरह जमा है। हालांकि अब यूनियन कार्बाइड के विषैले कचरे को पीथमपुर में जलाया जाएगा। गौरतलब है कि गुपचुप तरीके से वर्ष 2015 में दस टन कचरा पीथमपुर में बतौर ट्रायर जलाया जा चुका है। जिस तरह यह कचरा जलाया गया था, उस समय वहां आसपास जहरीले कचरे का प्रभाव इस कदर पड़ा कि लोग आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं। यूनियन कार्बाइड के इस कचरे ने समय-समय पर यह दिखा दिया है कि मैं जहर हूं... और जानलेवा कहर हूं। यानि यह कचरा जहां भी रहेगा, वहां जहर फैलाएगा। इस आशंका के कारण पीथमपुर में फिर से कचरा नष्ट करने की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल ही नहीं, बल्कि इंदौर, पीथमपुर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी डाउ केमिकल्स ने भारत सरकार की कमजोर नीतियों के कारण इस कचरे से अपने को अलग कर लिया है। जबकि दिसंबर में ही अमेरिकी संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भोपाल गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा और वहां मौजूद जहरीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन जिम्मेदार कंपनी करे। लेकिन भारत सरकार और न ही मप्र सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और अब 337 टन कचरे को पीथमपुर की रामकी संयंत्र के भस्मक में जलाने के लिए भेजा जा रहा है। वर्ष 2015 से पहले पीथमपुर में वर्ष 2008 में भी 40 टन कचरा गुपचुप तरीके से विशेष कंटेनरों में पीथमपुर की रामकी कंपनी में लाया गया था और वहां उस कचरे का निपटान किया गया था। भोपाल से इंदौर होते हुए इस कचरे के लिए कर्फ्यू का समय चुना गया। तब इंदौर में दंगों के कारण कर्फ्यू लगा था। रात के समय भोपाल की फैक्ट्री से कचरा निकाला गया था। इसे मामले में तब तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने धार दौरे के दौरान लोगों से माफी भी मांगी थी और कहा था कि इस काम में पारदर्शिता होना चाहिए थी, लेकिन हम गुपचुप तरीके से कचरा लाए। यूनियन कार्बाइड कचरे को पीथमपुर में जलाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। वकील अभिनव धनोतकर ने याचिका में यह तर्क दिया है कि विषैले कचरे के आसपास आबादी क्षेत्र है। इंदौर, धार और पीथमपुर जैसे घनी बसाहट वाले शहर हैं। इसके बावजूद 337 टन कचरे को यहां जलाया जा रहा है। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी के बाद फैक्ट्री में 337 टन जहरीला कचरा है, उसको पीथमपुर में जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस जहरीले कचरे को नष्ट करने का काम आसान नहीं है। कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया पर आपत्ति है। उनका कहना है कि रामकी कंपनी के पास इतनी बड़ी मात्रा में जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। गौरतलब है कि भोपाल गैस त्रासदी का जख्म अभी भी लोगों में हरा है। कचरा जलाने की खबर के बाद एक बार फिर से लोगों की यादें ताजा हो गई हैं, जब उस इलाके की गलियां लाशों से पट गई थीं। आज भी गैस त्रासदी के कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक तरफ भोपाल के लोग खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात से भी सशंकित हैं कि यह जहर पीथमपुर के लोगों के लिए जानलेवा न बन जाए।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

सदन पर चिंतन जरूरी

मप्र की विधानसभा को सबसे अच्छी विधानसभा माना जाता था, क्योंकि प्रदेश के विधायक पूरे मनोयोग के साथ न केवल सवाल पूछते थे, बल्कि एक-एक मुद्दे पर चर्चा भी करते थे, लेकिन यह परंपरा धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। दोनों पक्षों को इस बारे में सोचना चाहिए।

● **गौरव गुप्ता,** भोपाल (म.प्र.)

जागरूक हो जनता

प्रजनन दर के मामले में मप्र की हालत बहुत खराब है। प्रदेश की टीएफआर 2.8 है जो देश (2.3) की तुलना में 0.5 ज्यादा है। बीते तीन साल में प्रदेश की टीएफआर में एक पॉइंट का भी बदलाव नहीं आया है। सरकार को इस विषय में कोई नीति लानी होगी, जिससे जनता जागरूक हो।

● **पंकज वर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

राशि की कमी

जल जीवन मिशन में केंद्र से भुगतान की देरी के कारण उप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे भाजपा शासित राज्य भी जूझ रहे हैं। राज्यों के खजानों में राशि की कमी है। और इस प्रोजेक्ट को जारी भी रखना है। इसकी अर्थव्यवस्था में राज्यों के वित्त विभाग भी गहन विमर्श कर रहे हैं।

● **राहुल साहू,** ब्यावरा (म.प्र.)

पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से होगा आर्थिक विकास

सातपानी टाइगर रिजर्व एकमात्र लैंडस्केप है, जहां 96 बाघ विचरण करते हैं। वन्यजीवों से भरपूर टाइगर रिजर्व और भोपाल शहर के मध्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। पुरापाषाण काल शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका और आस्था का केंद्र भोजपुर शिवमंदिर को विश्व पटल पर रखकर पर्यटन को बढ़ावा देने काम किया जाएगा। आस्था और संस्कृति के दर्शन के साथ पर्यटक अब राष्ट्रीय उद्यान सहित आठवां टाइगर रिजर्व भी घूम सकेंगे। इसके लिए वन विभाग, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सातपानी टाइगर रिजर्व के कारण पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से तीन जिलों का भी आर्थिक विकास होगा। सातपानी में तीन हजार से अधिक वन्यप्राणी है।

● **अभिनव त्रिपाठी,** राऊ (म.प्र.)

दिल्ली चुनाव पर सबकी नजर

भाजपा को हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी माना जाता है। इसमें व्यापारिक समुदाय इसके कट्टर समर्थक हैं। वहीं कांग्रेस गरीबों, दलितों और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती थी। इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों को छोड़कर, जब आप और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था और दोनों को मिलकर वोटर शेयर 43.1 प्रतिशत था। दोनों पार्टियों ने समान वोटबैंक होने के बावजूद हमेशा अलग-अलग विधानसभा चुनाव लड़ा है। लेकिन अब आने वाले दिल्ली चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं।

● **बेहा पाल,** ग्वालियर (म.प्र.)

अपराधियों पर नकेल

लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूं तो पहले भी कई क्राइम में सामने आ चुका है। लेकिन साल 2024 में तीन केस ऐसे रहे जिनके कारण वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ये केस हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग का, एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सांसद पप्पू यादव को धमकी। इस मामले में केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाते हुए अपराधियों पर शिकंजा कसने के और नए कानून लाने के बारे में जरूर विमर्श करना चाहिए।

● **मोहसिन खान,** बैतूल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

बिहार में शुरू हुई प्रेशर पॉलिटिक्स

बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने फायदे को लेकर अभी से रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर एक ओर जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की मांग कर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। इन दोनों बयानों को प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है और इनके कई मायने निकले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भले ही लालू राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हों लेकिन अब भी मानसिक तौर पर दबाव बनाने से नहीं चूकते हैं। हाल में ही जिस तरह चार विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी चारों खाने चित हुए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है उससे लालू को डर सता रहा है कि कांग्रेस उन पर दबाव बनाएगी। लालू राज्य की राजनीति और कांग्रेस की नब्ज पहचानते हैं और चुनाव को लेकर अभी से कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए आरजेडी कांग्रेस को राष्ट्रीय नेतृत्व के मुद्दे पर उलझाए रखना चाहती है नहीं तो ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही थी।

उद्धव का होगा उद्धार!

पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में कानाफूसी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही नया समीकरण देखने को मिल सकता है। इसके सियासी गलियारों में कई कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कारण विपक्षी महाविकास आघाडी के तीनों दलों में शिवसेना (यूबीटी) के पास ज्यादा विधायक हैं। नियम के मुताबिक तय 10 प्रतिशत सीटों से कम संख्या होते हुए भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी स्पीकर के पद पर भी उद्धव दावा कर रहे हैं। जिसमें उन्हें भाजपा की मेहरबानी की जरूरत है। यानी भाजपा के बिना उद्धव का उद्धार संभव नहीं है। उनकी इस मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। असल में शिवसेना (यूटीबी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पुत्र आदित्य ठाकरे के साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। दोनों पुराने साथियों ने लगभग पांच साल बाद बेहद गर्मजोशी से एक-दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान पिता-पुत्र ने फडणवीस के साथ ठहाके लगाए। सोशल मीडिया पर सामने आई मुलाकात की तस्वीरों को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि महाराष्ट्र के इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच कभी मनमुटाव भी रहा होगा।

दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे विजेंदर!

दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है लेकिन नेताओं का दल बदल और सीट को लेकर दावेदारी इन दिनों चरम पर है। इस बीच भाजपा नेता बॉक्सर विजेंदर सिंह का एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि मैदान बदला है, लेकिन हौंसले वही हैं। आपका बेटा, आपका साथी, आपका विजेंद्र जीतेगा। दिल्ली में इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि वे दिल्ली के चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह को पार्टी दक्षिण दिल्ली से मैदान में उतार सकती है। 2019 में उन्हें इस सीट से भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने हराया था। विजेंदर सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ ही दिनों के भीतर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है और फरवरी की शुरुआत में चुनाव होने की संभावना है।

वसुंधरा के चहेते को तवज्जो

राजस्थान में बीते साल दिसंबर में सरकार गठन के बाद से बने मंत्रिमंडल में राजे समर्थक विधायकों को सीनियर होने के बावजूद पद नहीं दिया गया था। उन दिनों बड़ी वजह यह बताई जा रही थी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजे को कमजोर करने में लगा है। लेकिन 2024 में अब राजे फिर से सक्रिय हो चुकी हैं। हाल ही में जयपुर में सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में वसुंधरा राजे को खास जगह दी गई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। वहीं जब राजे दिल्ली गईं तो वहां भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। अटकलें हैं कि आगामी दिनों में होने वाले भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार में राजे समर्थकों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं में जिनको मंत्री पद मिल सकता है उनमें कालीचरण सराफ, अनिता भदेल, श्रीचंद कृपलानी और पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम सबसे आगे चल रहा है।

फिर एक होंगे चाचा-भतीजे!

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार के गुट ने कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी महायुति में भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी थी। महायुति को राज्य में प्रचंड जीत मिली जबकि शरद पवार के गुट ने अपना अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। हाल ही में शरद पवार खेमे के विधायक रोहित पाटिल ने अजित पवार से मुलाकात की है। इससे पहले एनसीपी विधायक शशिकांत शिंदे ने डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की थी। एनसीपी के दोनों खेमों के नेताओं के बीच लगातार हो रहीं मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चाचा-भतीजे फिर एक होंगे? इन चर्चाओं को तब और बल मिला जब अजित पवार, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की थी। तब कहा ये गया था कि ये नेता शरद पवार को जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे थे।

आईजी ईमानदार, टीआई बेईमान

प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के एक थाना क्षेत्र में टीआई अन्य अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। यह स्थिति तब है, जब जोन के आईजी ईमानदार अफसरों में गिने जाते हैं। बताया जाता है कि आईजी साहब की अभी तक जहां भी पदस्थापना हुई है, उनके मातहत कायदे-कानून से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि व्यावसायिक राजधानी में साहब कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त रहते हैं और टीआई उनकी नाक के नीचे पकौड़े तल रहे हैं। यानि टीआई कायदे-कानून को दरकिनार कर जमकर माल पेल रहे हैं। अभी हाल ही में शहर में एफएमसीजी में एक बड़ी जालसाजी का मामला सामने आया था। फरियादी मामले को लेकर थाने पहुंचा तो टीआई साहब ने उसे चलता कर दिया। बड़ी जालसाजी का मामला होने के कारण फरियादी को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। कोई के निर्देश पर टीआई ने एफआईआर तो दर्ज की लेकिन धाराएं इतनी कमजोर कर दीं कि उससे जालसाजों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि टीआई साहब एक ऐसा तारा बन गए हैं, जिसकी रोशनी किसी के प्रभाव से कम होती नहीं दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि एक तरफ आईजी साहब अपनी ईमानदारी के दम पर क्षेत्र में सुशासन की अलख जगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक टीआई उनके सारे प्रयासों पर भारी पड़ रहे हैं।

धीरज रखो, नहीं तो...

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक मंत्रीजी के पीए इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंत्रीजी प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। वे अपने अनाप-शनाप बयानों के कारण पूर्ववर्ती सरकारों में चर्चा का केंद्र बने रहते थे। एक बार तो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी पर बयान देकर वे मंत्री पद भी गंवा चुके थे। हालांकि वर्तमान सरकार में मंत्रीजी के पास जहां बड़े विभाग नहीं हैं, वहीं वे धैर्य से काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्रीजी के पीए का धीरज उबाल मार रहा है। आलम यह है कि उन्होंने अपने विभाग में कमाई के लिए तरह-तरह के तरीके अपना लिए हैं। यह वे मंत्रीजी को विश्वास में लेकर कर रहे हैं या उन्हें अंधेरे में रखे हुए हैं, यह तो वे और मंत्रीजी ही जानते होंगे। लेकिन जिस तरह मंत्रीजी के पीए काली कमाई बटोरने में जुटे हुए हैं, उसको देखते हुए उन्हें लोग इशारों-इशारों में संकेत भी दे रहे हैं कि धीरज रखो, नहीं तो छापे का शिकार हो जाओगे। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेश की हर अवैध गतिविधियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर है। सूत्र बताते हैं कि अपनों से मिले संकेत के बाद भी मंत्रीजी के पीए धीरज नहीं रख रहे हैं। बताया जाता है कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों से शिकायत करने की भी तैयारी की जा रही है।

ठेके पर चल रहा विभाग

प्रदेश में एक मंत्री के इर्द-गिर्द जातिवाद का ऐसा ताना-बाना बुना गया है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। आलम यह है कि मंत्रीजी दिखावे के चक्कर में हमेशा आयोजनों और आयोजकों में फंसे रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि इसको देखते हुए मंत्रीजी ने अपने विभागों को ठेके पर दे दिया है। यानि मंत्रीजी के विभागों का सारा ऊपरी काम उनके सजातीय अधिकारी संभाल रहे हैं। विभागों में किसे कहां भेजना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसको उपकृत करना है, किससे वसूली करनी है, मंत्रीजी ने यह सारा ठेका अपने करीबी सजातीय अधिकारी को दे दिया है। साहब के ये सजातीय अधिकारी हैं तो चिकित्सा वाले विभाग के, लेकिन मंत्रीजी के दोनों विभागों में जमकर खेलकूद कर रहे हैं। मंत्रीजी के इस करीबी अधिकारी से विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी परेशान हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी के इस चहेते ने विभाग के अधिकारियों के नाक में भी दम कर रखा है। विभाग के अधिकारी जो भी नीति और रणनीति बनाते हैं उसमें भी यह हस्तक्षेप कर देते हैं। बताया जा रहा है कि विभागों में जो भी खरीदी होती है वह पूरी तरह मंत्रीजी के चहेते इस अधिकारी द्वारा ही की जाती है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी के ये करीबी लक्ष्मी बटोरने के लिए इस कदर आतुर हैं कि वे हर काम में टांग अड़ाते हैं। विभाग में कोई भी काम हो, टेंडर हो, उसमें वे मोटे कमीशन की मांग करने लगते हैं। इससे विभाग में उनसे हर कोई परेशान है।

मांगा आम, भेज दिया अनार

राज्यपाल और राजभवन का लोकतंत्र में सर्वोच्च महत्व होता है। लेकिन विडंबना यह है कि यहां कोई भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पदस्थ होना नहीं चाहता है। ऐसा ही नजारा मप्र के राजभवन में देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि जिस आईएएस अधिकारी को यहां पदस्थ किया जाता है, वह यहां से निकलने की फिराक में जुट जाता है। अभी हाल ही में राजभवन ने अपने यहां एक वरिष्ठ अधिकारी की विशेष रूप से मांग की। इसके लिए बकायदा नाम भी भेजा गया। लेकिन विडंबना यह है कि उक्त अधिकारी की जगह सरकार ने दूसरे अधिकारी को राजभवन भेज दिया। इसको देखकर लोग ताने कस रहे हैं कि मांगा आम, भेज दिया अनार...। सूत्रों का कहना है कि दरअसल, राजभवन में महामहिम के दो ओएसडी हैं। इन दोनों की ही राजभवन में चलती है। सूत्र बताते हैं कि किसको राजभवन में रखना है और किसको नहीं, ये यही दोनों तय करते हैं। सूत्रों का कहना है कि राजभवन की मांग को इन्हीं दोनों ओएसडी के दिशा-निर्देश पर पूरा नहीं किया गया।

तिवारी जी की सांसें फूलीं

प्रदेश के कमाऊ और काली कमाई के लिए कुख्यात विभाग इन दिनों सभी के निशाने पर है, क्योंकि इस विभाग का अदना सा कारिंदा अरबों का आसामी निकला। सरकारी तौर पर तो विभाग ने नाकों को खत्म कर वाहनों से अवैध वसूली को रोक दिया है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। आज भी अस्थायी नाके बनाकर वाहनों से अवैध वसूली हो रही है। इसके कर्ताधर्ता विभागीय मंत्रीजी के पीए तिवारी जी हैं। सूत्र बताते हैं कि जबसे लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई कर विभाग में होने वाली काली कमाई की पोल खोली है, तबसे तिवारी जी सांसें फूली हुई हैं। वहीं एक राजनीतिक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्रीजी और तिवारी जी पर सीधे-सीधे सांठगांठ कर काली कमाई करने का आरोप लगा दिया है। यही नहीं जब इस संदर्भ में मंत्रीजी से पूछा गया तो वे भी टका सा जवाब देकर चलते बने, कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन सूत्रों का कहना है कि भोले-भाले दिखने वाले तिवारी जी काली कमाई करने के लिए विभाग में अपना अलग नेटवर्क चला रहे हैं।

एक और कॉर्पोरेशन पर लगेगा ताला

करीब 63 साल पहले गठित मप्र लघु उद्योग निगम पर ताला लगेगा। यानि तिलहन संघ, बुनकर सहकारी संघ, राज्य परिवहन निगम, भूमि विकास बैंक और कुक्कुट महासंघ की तरह यह कॉर्पोरेशन भी बंद होगा। एक हजार करोड़ के निगम को बंद करने की पटकथा प्रदेश के एमएसएमई मंत्री और लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष चेतन्य कुमार काश्यप ने लिखी है। दरअसल, उनका कहना है कि दूसरे विभागों ने लघु उद्योग निगम को कमीशनखोरी का अड्डा बना दिया है। ऐसे में दूसरे विभागों की गंदगी धोते-धोते लघु उद्योग निगम बदनामी का अड्डा बन गया है। मंत्री का मानना है कि लघु उद्योग निगम के माध्यम से दूसरे विभाग भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे में हम कब तक दूसरे विभाग के भ्रष्टाचार का दाग अपने पर लगाएं?

गौरतलब है कि मप्र लघु उद्योग निगम को राज्य शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 1961 में स्थापित किया गया। अपनी स्थापना से निगम लगातार प्रगति करते हुए कंपनी के उद्देश्यों एवं शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है। वर्ष 1978 में निगम को विभिन्न सामग्रियों के दर अनुबंध के विरुद्ध शासकीय क्रय माध्यम से प्रदेश के लघु उद्योगों को विपणन सुविधा प्रदान किए जाने का कार्य सौंपा गया। लेकिन अब कमीशनखोरी के लिए बदनाम लघु उद्योग निगम (एलयूएन) को सरकार बंद करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सरकार को निगम बंद करने की विधिवत घोषणा भर करना है। निगम 1961 में दूसरे विभागों के लिए उपकरण एवं अधोसंरचना का सामान खरीदने के लिए गठित हुआ था। इसके बदले निगम को कमीशन मिलता है, पर इसी काम के लिए केंद्र सरकार का जेएम पोर्टल आने के कारण निगम का कामकाज सीमित हो गया और महज 70 करोड़ रुपए का काम मिला। इसे देख सरकार ने निगम को बंद करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि निगम में 300 कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा था।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2017 में अनियमितताओं की शिकायत के चलते निगम को बंद करने के निर्देश दिए थे, इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था, तभी सत्ता में परिवर्तन हो गया और कमलनाथ सरकार आने से निगम को संजीवनी मिल गई। लेकिन एक बार फिर से लघु उद्योग निगम को बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। एलयूएन बंद होने के बाद उसकी संस्था मृगनयनी एम्पोरियम को हस्तशिल्प विकास निगम संचालित करेगा। इसकी भी तैयारी चल रही है। अधिकारी विचार कर चुके हैं। सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। सूत्रों का कहना है कि चेतन्य कुमार काश्यप जबसे लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बने हैं, उनके सामने निगम का काला इतिहास आते ही वे इसे बंद करने की योजना में जुट गए हैं। जानकारों का कहना है कि फिलहाल चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री से बिना पूछे अधिकारियों के सामने मप्र लघु उद्योग निगम को मार्केटिंग तथा प्रोक्योरमेंट करने के व्यावसायिक एजेंडे को बाहर करने का निर्णय ले लिया है। आश्चर्य एवं चौंकाने वाली बात यह है कि लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों की पगार 30 करोड़ है और सरकार वैसे भी वित्तीय घाटे के चरम पर है।

जानकारी के अनुसार सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री एवं एलयूएन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में निगम की विपणन विभाग की 3 जुलाई को समीक्षा बैठक में निगम को बंद करने के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया। समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विभागों को आवश्यकता होने पर निगम भंडार क्रय निगमों के अनुसार खुली निविदा आमंत्रित करने के लिए केवल सलाहकार के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए निगम को निविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत सेवा शुल्क देना होगा। सूत्र बताते हैं कि मंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय का विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि लघु उद्योग निगम विभागों की आवश्यकताओं के लिए होने वाली खरीदी के लिए एक संगठित प्लेटफार्म है। जिस भी विभाग को अपने विभाग के लिए सामानों की खरीदी करनी होती है, वह लघु उद्योग निगम को अपनी डिमांड बता देता है। हालांकि निगम द्वारा जितनी भी खरीदियां होती है, उनमें से अधिकांश भ्रष्टाचार के विवाद में फंस जाती हैं। बताया जाता है कि ऐसे ही विवादों से बचने के लिए लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष चेतन्य काश्यप ने इसे बंद करने की कवायद शुरू कर दी है।

● **विकास दुबे**

कंसल्टेंसी का काम करेगा लघु उद्योग निगम

विगत 6 दशकों से निगम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का मप्र में विकास को बढ़ावा देता आ रहा है एवं बहु-आयामी गतिविधियों, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास, निर्माण एवं रखरखाव, प्रदेश के बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को प्रसिद्ध मृगनयनी एम्पोरियम के माध्यम से व्यवसाय सुविधा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को लौह-इस्पात एवं कोयला प्रदाय तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की परीक्षण सुविधा का संचालन कर रहा है। वर्तमान में लघु उद्योग निगम ट्राइबल, पीएचई, शिक्षा आदि विभागों के सामानों की खरीदी करवाता है। किसी भी सरकारी विभाग के लिए खरीदी का काम एलयूएन द्वारा किया जाता है। एलयूएन विज्ञप्ति के जरिए अलग-अलग कंपनियों से उनके प्रोडक्ट के रेट आमंत्रित करता है। कंपनी अपने रेट के साथ प्रोडक्ट का प्रदर्शन भी कमेटी के सामने करती है। इसके बाद एक तकनीकी कमेटी, रेट तय करती है। फिर रेट कॉन्ट्रैक्ट (आरसी) कर लिया जाता है। उसी दर पर कंपनियां माल सप्लाई करती हैं। लेकिन लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष की मंशा है कि अब केवल लघु उद्योग निगम कंसल्टेंसी का काम करेगा। ऐसे में विभाग की कितनी आमदनी होगी और विभाग का खर्चा कैसे चलेगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि सरकार ने अभी तक जितने निगम मंडलों का बंद किया है, उनके अधिकारियों, कर्मचारियों का भार दूसरे विभागों पर थोपा गया है। ऐसे में लघु उद्योग निगम को बंद करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।

आईएएस सर्विस मीट में छापों की गूंज...

साल भर फाइलों में व्यस्त रहने वाले आईएएस अधिकारियों और उनके परिजनों ने तीन दिन तक राजधानी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित आईएएस सर्विस मीट में जमकर खेल, मस्ती और खाने का लुत्फ उठाया। इस आयोजन में प्रदेशभर से आईएएस अधिकारी पहुंचे। अपने-अपने विभाग और जिलों का काम भूलकर अफसरों ने टंग ऑफ वार, क्विज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, पूल, बिलियर्ड्स, फुटबॉल, कैरम, नौकायन, डांस, कुकिंग आदि में हाथ आजमाया। इसी दौरान राजधानी में लोकायुक्त और आयकर विभाग ने बिल्डर्स और कारोबारियों के यहां छापामार कार्रवाई की। इस कारण आईएएस सर्विस मीट के दौरान छापों की गूंज भी सुनाई देती रही। अफसर एक-दूसरे से छापे के संदर्भ में जानकारियां लेते रहे। इस बार मीट भी फीकी रही, क्योंकि दिल्ली से सिर्फ एक आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ही शामिल हुए।

गौरतलब है कि तीन दिनी आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था। 21 दिसंबर को बोट क्लब पर रेस में अफसरों ने परिवार के साथ नाव चलाई। इसके बाद जुंबा डांस करते हुए थिरके भी। वहीं अरेरा क्लब में फुटबॉल, कैरम, फन गेम्स समेत अन्य एक्टिविटी हुई। कई आईएएस अधिकारी अपनी टीम के साथ व्यंजन बनाने की कुकिंग कॉम्पिटिशन में भी शामिल हुए थे। रात में डीजे नाइट के प्रोग्राम में फैमिली के साथ डांस किया। दो साल बाद हो रही सर्विस मीट को लेकर इस बार अफसरों और उनके परिजनों में उत्साह दिखा। सर्विस मीट में आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान के अलावा एसीएस, प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों ने जूनियर अफसरों के साथ अलग-अलग विषयों पर जुगलबंदी दिखाते हुए प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी टीम को जिताने का काम किया।

सिंगिग और डांसिंग में बिखेरे जलवे

आईएएस सर्विस मीट के पहले दिन कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कल्चरल प्रोग्राम में एक तरफ जहां आईएएस ऑफिसर्स अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ रैंप वॉक करते दिखे, वहीं डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस में लोकगीतों पर प्रस्तुति के जरिए भाषा की विविधिता का जश्न मनाया गया। आईएएस सर्विस मीट के दूसरे दिन अफसर पत्नी और बच्चों के साथ दिनभर मस्ती करते दिखे। अरेरा क्लब में जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े, खाद्य आयुक्त सिबी चक्रवर्ती एम. और मदन कुमार समेत अन्य आईएएस अफसरों ने बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस समेत अन्य गेम्स में हिस्सा लिया। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान, एसीएस अनुपम राजन, रिटायर्ड एसीएस मलय श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन में फैशन शो में हिस्सा लिया।

प्रमोटी अफसरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार

2 साल बाद हुए आईएएस सर्विस मीट में अफसरों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। लेकिन यह आयोजन इसलिए भी चर्चा में रहा कि आयोजन के दौरान प्रमोटी आईएएस अधिकारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। सूत्रों का कहना है कि डायरेक्ट आईएएस बनने वालों ने प्रमोटी आईएएस अधिकारियों को उतना महत्व नहीं दिया, जितना डायरेक्ट वालों को दे रहे थे। यही नहीं, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला, जितना अन्य अफसरों को मिल रहा था।

मुख्यमंत्री ने दिखाया आईना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 दिसंबर को प्रशासन अकादमी भोपाल में आईएएस ऑफिसर्स द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मीट के तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने आईएएस अफसरों को आईना दिखाते हुए कहा कि कर्म तो सब करते हैं, लेकिन भाग्य परमात्मा देता है। आपने इस मार्ग पर चलते हुए न सिर्फ कर्म किया, बल्कि भाग्य भी पाया है। मैं आपको दोनों तरह से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की दुनिया के सामने जो पहचान बनी है, उसमें आईएएस अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही है। यह हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्होंने कहा, राज्य के विकास के नए आयाम देने और प्रगति पथ पर बढ़ाने में आईएएस अफसरों का बहुमूल्य योगदान रहता है। हम सब मिलकर विकसित मप्र का संकल्प साकार करेंगे। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भी मौजूद रहे।

सीएम ने तीनों स्तंभ का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हमारे प्रशासनिक ढांचे को स्थिर रखते हैं। राजनेता विधायिका के जरिए अपनी भूमिका अदा करते हैं। हमारा एग्जाम जनता लेती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका दूसरी है। जहां वकालत नामा से काम होता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अदालत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जब आपको सेवा में देखता हूं, तो मन में बहुत श्रद्धा महसूस होती है। आप पूरी ताकत से काम करते हैं। निर्णय करना सरल है, लेकिन पूरा करने के लिए कानूनी जटिलताओं से बचाना तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि आप जीवनभर क्लब के सदस्य रहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने विचार मंथन के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा, विचार मंथन नए दौर और नए प्रदेश के लिए फायदेमंद रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि ऐसा क्लब बने, जिसके जरिए आपके विचार हम तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आईएएस अफसर मंत्रियों की प्लान की गई योजनाओं को धरातल तक लेकर जाता है। सुबह से लेकर रात तक बिना थके योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में लगा रहता है। उन्होंने आईएएस और इंद्र का सिंहासन की कहानी भी सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा, एक आईएएस धरती ही नहीं स्वर्ग में निगेटिव परिस्थितियों को सकारात्मक करने की शक्ति रखता है। वहीं मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी कहा कि आईएएस अपने आपको खुदा न समझें।

● **अक्स ब्यूरो**

कोठारी-नरहरि पीएस लवानिया-इलैया राजा सचिव बनाए गए

म प्र के 82 आईएएस अफसरों को डॉ. मोहन यादव की सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। अलग-अलग बैच के आईएएस का प्रमोशन करते हुए बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रमोशन की इस लिस्ट में 2001 बैच के दो आईएएस अधिकारी सचिव से प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। पर्यावरण विभाग में सचिव नवनीत मोहन कोठारी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सचिव पी नरहरि प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद पदोन्नति सूची जारी की गई। सभी अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ एक जनवरी 2025 से मिलेगा। एक जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाली लिस्ट में अविनाश लवानिया और इलैया राजा टी भी पदोन्नत होकर सचिव बन गए हैं। इसके अलावा दो आईएएस अफसर नवनीत मोहन कोठारी और पी नरहरि को पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। 16 अपर सचिव को सचिव पद पर प्रमोशन दिया गया है। 29 आईएएस को अपर सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। एक अन्य आदेश में उपसचिव स्तर के 26 आईएएस अफसरों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मंजूर किया गया है।

ये बने प्रमुख सचिव

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में सचिव पद पर कार्यरत जिन दो अफसरों को प्रमोट कर प्रमुख सचिव बनाया गया है, उनमें नवनीत मोहन कोठारी और पी नरहरि के नाम शामिल हैं। अभी कोठारी को पुराने विभाग पर्यावरण में ही प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं नरहरि भी सचिव पीएचई से प्रमुख सचिव पीएचई बनाए गए हैं।

इन्हें बनाया गया सचिव

अपर सचिव प्रियंका दास (एमएसएमई विभाग) को पदोन्नत कर सचिव एमएसएमई, अविनाश लवानिया अपर सचिव मुख्यमंत्री और एमडी एमपी सड़क विकास निगम को सचिव मुख्यमंत्री और एमडी एमपीआरडीसी, सूफिया फारुकी वली ओएसडी सह आयुक्त महिला और बाल विकास विभाग को आयुक्त महिला और बाल विकास विभाग, अभिषेक सिंह सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को ओएसडी सह सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, धनराजू एस ओएसडी सह आयुक्त वाणिज्यिक कर को आयुक्त वाणिज्यिक कर तथा सचिव वाणिज्यिक कर विभाग, इलैया राजा टी अपर सचिव मुख्यमंत्री तथा एमडी पर्यटन विकास निगम को सचिव मुख्यमंत्री और एमडी पर्यटन विकास निगम, प्रीति मैथिल अपर सचिव उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को सचिव उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, अजय गुप्ता संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास को इसी पद पर पदोन्नत किया गया है।

ये बने बने अपर सचिव

जीएडी द्वारा जारी आदेश में जिन अफसरों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव) पर पदोन्नत किया गया है उसमें उपसचिव नवीन व नवकरणीय ऊर्जा वीरेंद्र कुमार, कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह, एमडी भवन विकास निगम डॉ. पंकज जैन, एमडी मत्स्य महासंघ निधि निवेदिता, उप सचिव वित्त विभाग, स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर सीधी, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर सीहोर, अनुराग वर्मा, कलेक्टर सतना, प्रतिभा पाल, कलेक्टर रीवा शामिल हैं। डॉ. फटिंग राहुल हरिदास, कलेक्टर बड़वानी, राजीव रंजन मीणा, संचालक संस्थागत वित्त, दीपक आर्य, सीईओ एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, हर्षिका सिंह, संचालक कौशल विकास तथा आयुक्त तकनीकी शिक्षा, आशीष भार्गव (पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत), अवधेश शर्मा, कलेक्टर टीकमगढ़, कुमार पुरुषोत्तम, एमडी कृषि विपणन बोर्ड, सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर अशोकनगर, रत्नाकर झा, उप सचिव श्रम विभाग शामिल हैं। इनके अलावा कलेक्टर उमरिया, धरणेंद्र कुमार जैन, केडी त्रिपाठी, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर रायसेन, नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर बैतूल, केदार सिंह, कलेक्टर शहडोल, राजेश बाथम, कलेक्टर रतलाम, दिनेश कुमार मौर्य, ओएसडी सह कंट्रोलर खाद्य और औषधि प्रशासन, विवेक श्रोत्रिय, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राजेश कुमार ओगरे, सचिव राज्य सूचना आयोग, अरुण कुमार परमार, उपसचिव मुख्यमंत्री तथा भारती जाटव, उपसचिव खनिज साधन विभाग को भी अपर सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है।

इनका भी प्रमोशन

अमित तोमर आईजी पंजीयन और मुद्रांक, श्रीकांत बनोठ आयुक्त सह संचालक नगर व ग्राम निवेश, शैलबाला अंजना मार्टिन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, वंदना वैद्य ओएसडी सह अपर आयुक्त आदिवासी विकास, अनुभा श्रीवास्तव प्रमुख राजस्व आयुक्त, प्रबल सिपाहा सचिव एमपी पीएससी, सतेंद्र सिंह कलेक्टर गुना मनीष सिंह सचिव परिवहन विभाग भी पदोन्नत किए गए हैं।

20 आईएएस होंगे सेवानिवृत्त

2025 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मोहम्मद सुलेमान, जेएन कंसोटिया, एसएन मिश्रा, अजीत केसरी और विनोद कुमार शामिल है। इसके अलावा फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों में सागर आयुक्त वीरेंद्र कुमार रावत, जबलपुर आयुक्त अभय कुमार वर्मा, दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कमिश्नर निशक्तजन डॉ. रामराव भोंसले, जनगणना निदेशालय एमपी भावना वालिम्बे और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी भी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। इन अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद नए अधिकारियों को एसीएस और मुख्य सचिव स्तर पर प्रमोशन का मौका मिलेगा। मौजूदा एसीएस डॉ. राजेश राजौरा 2026 तक सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे और मई 2027 में रिटायर होंगे। प्रदेश के कई एसीएस और पीएस स्तर के अधिकारी दिल्ली में पदस्थ हैं। इनमें नीलम शमी राव, वीएल कांताराव, आशीष श्रीवास्तव, पंकज अग्रवाल, अलका उपाध्याय, मनोज गोविल, पल्लवी जैन गोविल, अनिरुद्ध मुखर्जी, दीप्ति गौड़ मुखर्जी, विवेक अग्रवाल, हरिरंजन राव के नाम शामिल हैं। वहीं, प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद कई अधिकारियों को मुख्य सचिव स्तर के वेतनमान में प्रमोशन मिलेगा। इसमें संजय कुमार शुक्ला, रश्मि अरुण शमी, मनीष रस्तोगी, दीपाली रस्तोगी, शिवशेखर शुक्ला और सचिन सिन्हा शामिल हैं।

संतोष सिंह बने एडीजी

मप्र के 9 आईपीएस अफसरों को नए साल का तोहफा देते हुए उनका प्रमोशन किया गया है। 4 डीआईजी को आईजी बनाया गया है। वहीं 4 एसपी को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। मप्र गृह विभाग ने इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया है। इसके अलावा चार डीआईजी को प्रमोट कर आईजी और चार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया गया है। फील्ड में पदस्थ छिंदवाड़ा और चंबल रेंज के डीआईजी को आईजी बनाया गया है। इसी तरह डीआईजी बनने वालों में धार, अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। प्रमोट होने वाले अफसरों को एक जनवरी 2025 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा।

गृह विभाग ने 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार सिंह को एडीजी पद पद पदोन्नत किया है। संतोष सिंह अभी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर हैं। पदोन्नति के बाद एडीजी, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर के पद पर काम करते रहेंगे। एक अन्य आदेश में 2007 बैच के आईपीएस अफसर डीआईजी छिंदवाड़ा सचिन कुमार अतुलकर को पदोन्नत कर आईजी बनाया गया है। इसी तरह डीआईजी चंबल रेंज कुमार सौरभ, उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल मध्यक्षेत्र कृष्णावेनी देसावतु और डीआईजी प्लानिंग जगत सिंह राजपूत को पदोन्नत कर आईजी बनाया गया है। इन सबकी पदस्थापना यथावत रखी गई है। गृह विभाग द्वारा जारी एक अन्य आदेश में रुचिका जैन को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। जैन का नाम सीनियरिटी लिस्ट में कुमार सौरभ के नाम के ऊपर होगा। शासन द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो भोपाल विजय कुमार खत्री को डीआईजी बनाया गया है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक अशोकनगर विनीत कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह और सहायक पुलिस महानिरीक्षक एसआईएसएफ पीएचक्यू राकेश कुमार सिंह को प्रमोट कर डीआईजी बनाया गया है। पदोन्नति के बाद इनकी पदस्थापना वर्तमान पद पर यथावत रखी गई है।

इस साल बड़े बदलाव

वहीं प्रदेश में नए साल में पुलिस महकमे में भी बड़े बदलाव की संभावना है। क्योंकि नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार पुलिस सुधार की दिशा में काम किया है। उन्होंने पुलिस की लगभग सभी शाखाओं की समीक्षा कर ली है। इसके बाद बदलाव की संभावना बढ़ गई है। पुलिस महानिदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार रिव्यू बैठकें की हैं। जहां खामियां हैं, उन्हें निकट भविष्य में सुधारा जाएगा। 2025 में पुलिस सुधार की दिशा में बड़े-बड़े निर्णय होंगे। जिसमें थानों से लेकर पुलिस मुख्यालय में तक बदलाव भी शामिल हैं। पुलिस में बदलाव की शुरूआत पहले ही महीने में हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव एक ही जगह लंबे समय से जमे पुलिस अधिकारियों को लेकर होगा। हाल ही में पुलिस मुख्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली सरकार की दो प्रमुख एजेंसी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में व्यापक बदलाव किए हैं। आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारियों को एजेंसियों से बाहर किया और प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बेहतर छवि के अधिकारी एवं कर्मचारियों को इन एजेंसियों ने पदस्थ किया है। अब जिलों में भी यही क्रम दोहराया जा सकता है।

● **राजेंद्र आगाल**

मनोज श्रीवास्तव बने राज्य निर्वाचन आयुक्त

रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव मप्र के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले आयोग के आयुक्त रहे बसंत प्रताप सिंह का 6 माह का अतिरिक्त कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा हुआ। इसके चलते राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नई

नियुक्ति के आदेश जारी किए। श्रीवास्तव के पहले इस पद पर पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा और रिटायर्ड एसीएस मलय श्रीवास्तव की भी दावेदारी थी। आदेश के अनुसार श्रीवास्तव की नियुक्ति 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए होगी। मनोज श्रीवास्तव 1987 बैच के मप्र कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उनको प्रशासनिक काम का अच्छा अनुभव है। इससे प्रदेश में राज्य निर्वाचन के माध्यम से होने वाले चुनाव के संचालन को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। श्रीवास्तव प्रदेश सरकार के विभागों में कई अहम पदों पर रहे। वह 2021 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। श्रीवास्तव को केंद्रीय हिंदी संस्थान से स्वामी विवेकानंद पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय विमानन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा, वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के हिंदी भवन से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका अक्षरा के प्रधान संपादक भी हैं। इसके पहले 30 सितंबर को पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा के रिटायरमेंट के दिन उन्हें नया राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने के आदेश जारी होने वाले थे। राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी तैयारी भी कर ली गई थी और बीपी सिंह ने स्टाफ को हाई-टी देकर खुद को कार्यमुक्त भी बता दिया था। हालांकि अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी होने के बाद समीकरण बदल गए। इसके बाद वीरा राणा को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने का फैसला टल गया। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे बीपी सिंह का कार्यकाल 30 जून 2024 को खत्म हो गया था। तब सरकार ने किसी नए आयुक्त को नियुक्ति नहीं देते हुए बीपी सिंह को ही पद पर बने रहने के आदेश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 माह तक पद पर बने रह सकते हैं। गौरतलब है कि रिटायरमेंट के समय पुराने मुख्य सचिव ने इन्हें बिना पदस्थापना के एक ही जगह पर रखा था। अब यह संघ के करीब आ गए हैं और संघ के कहने पर ही इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है।

पर्यावरण की अनुमतियां 6 माह से रुकीं

मप्र में निर्माण परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, खनन कार्य आदि के लिए पर्यावरण अनुमति ली जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि मप्र में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) यानि सिया एवं सेक की समिति गठित नहीं होने के कारण अनुमतियां अधर में लटकी हुई हैं। इस कारण राज्य सरकार के विकास कार्य तथा राजस्व प्राप्ति के काम पूरी तरह रुके हुए हैं। जानकारों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानि सिया की समिति का गठन करते हुए मुकेश जैन और सुनंदा सिंह रघुवंशी को समिति का सदस्य बनाया है। इसको लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। विवाद इतना बढ़ गया है कि भोपाल के एक व्यक्ति ने केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और सचिव लीलानंदन से इस मामले की लिखित शिकायत की है। बताया जाता है कि 18 नवंबर को लिखे इस पत्र को पर्यावरण मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है, और इस संदर्भ में मप्र के पर्यावरण विभाग से इस संदर्भ में जानकारी तलब की है। उसने विभाग से जानकारी मांगी है कि किस आधार पर मुकेश जैन को सिया समिति में सदस्य नियुक्त किया है।

गौरतलब है कि भोपाल निवासी अजय कुमार ने 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में उल्लेखित किया है कि मप्र में पर्यावरण स्वीकृति का काम पिछले 5-6 माह से नहीं हो रहा है, क्योंकि सिया एवं सेक की समिति अभी तक गठित नहीं हुई है। जिसके कारण निर्माण परियोजना, सिंचाई परियोजना, खनन कार्य सभी बंद हैं। राज्य सरकार के विकास कार्य तथा राजस्व प्राप्ति के कार्य पूरी तरह रुके हैं। वास्तव में इन कमेटियों में विषय विशेषज्ञों को नामांकित किया जाना चाहिए ताकि नियमों के अनुसार काम शीघ्रता से हो सकें। जानकारी के अनुसार, इन समितियों में जो नाम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, वह अधिकांश कॉलेज के प्रोफेसर तथा राजनीतिक आस्था रखने वाले लोगों के हैं। उदाहरण के लिए सिया में सदस्य के लिए इंदौर के मुकेश जैन का नाम भेजा गया है। मुकेश जैन बिल्डर हैं तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता बीएससी (कृषि विज्ञान) तथा एमबीए (मार्केटिंग) है। जबकि कृषि कार्यों में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्डर को नामांकित करने पर नियमों का ज्ञान निरीक्षण की योग्यता नहीं होने पर सही ढंग से पर्यावरण समिति के प्रकरणों में निर्णय नहीं हो सकेगा।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण मंत्रालय से मांग की है कि सिया और सेक की समिति में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए, जिन्हें विषय का अच्छा ज्ञान हो। साथ ही मुकेश जैन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण का समुचित संरक्षण हो।

जानकारों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सिया और सेक की समिति का मामला फुटबॉल बना हुआ है। इसका असर यह हो रहा है कि पिछले 6 माह से प्रदेश में कई विकास कार्य इसलिए रुके हुए हैं कि उनके लिए पर्यावरण की अनुमतियां नहीं मिल पा रही हैं। सूत्र बताते हैं कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, वह पर्यावरण अनुमति के लिए भेजे गए आवेदनों के आधार पर हो रहे हैं। गौरतलब है कि मप्र में पर्यावरण स्वीकृति के लिए, मप्र राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत काम करता है। पर्यावरणीय मंजूरी एक नियामक प्रक्रिया है। यह किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करती है और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एक व्यापक कानून है। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार देता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर, 1986 को लागू हुआ था। लेकिन जानकारों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर अनुमतियां दी जा रही हैं। इसलिए मप्र में सिया और सेक की विश्वसनीयता हर दम सवालों के घेरे में रहती है। वर्तमान में मुकेश जैन और सुनंदा सिंह रघुवंशी की नियुक्ति सवालों के घेरे में है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

बिना पर्यावरण अनुमति के हो रहे निर्माण कार्य

गौरतलब है कि दो लाख वर्गफीट (20 हजार स्क्वायर मीटर) से बड़े हर कंस्ट्रक्शन के लिए सिया की मंजूरी जरूरी है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि सिया समिति नहीं होने के कारण लोग केवल आवेदन देकर निर्माण कार्य करा रहे हैं। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हो या पैन सिटी, दोनों में सिया की अनुमति इसलिए जरूरी है ताकि अनुमान लग सके कि इन प्रोजेक्ट्स से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा और इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है। इसी असेसमेंट के आधार पर क्षतिपूर्ति प्लान तैयार किया जाता है। गौरतलब है कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 6 सप्ताह के भीतर उन स्थानों पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण गठित करें, जहां उनका गठन नहीं हुआ। यह निर्देश तब दिया गया, जब न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश के विरुद्ध दीवानी अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एनजीटी के बजाय जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा कुछ पट्टों में पर्यावरण मंजूरी दिए जाने को अस्वीकृत किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए हुए एक माह से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन मप्र में सिया समिति का गठन नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि समिति का मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच घूम रहा है। ऐसे में प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

केन-बेतवा की नहर से बुझेगी बुंदेलखंड की प्यास

पानी की कमी से पलायन की मार झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों की मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली ऐतिहासिक परियोजना से यहां के 10 जिलों को इस समस्या से निजात मिलेगी। यहां के ज्यादातर किसान पानी के अभाव में सिर्फ खरीफ की फसलें ही उगाते हैं। 25 दिसंबर को करीब तीन दशक पहले शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में हरी झंडी दिखा दी है। प्रधानमंत्री ने पन्ना और छतरपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में दौधन बांध का शिलान्यास किया।

छतरपुर और पन्ना जिलों की सीमा पर केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाएगा। इस बांध के माध्यम से पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दो टनल बनाई जाएंगी। एक मुख्य टनल के जरिए 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। यह छतरपुर, झांसी, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के गांवों से गुजरते हुए झांसी जिले में बेतवा नदी पर बने पारीछा बांध के ऊपरी क्षेत्र में केन नदी का पानी पहुंचाएगी। इस 221 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से रास्ते में पड़ने वाले गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही प्रेशराइज्ड पाइपलाइन के जरिए खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत बनने वाली नहर से पानी की बर्बादी रोकने के लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार नहर से पंपों के जरिए प्रेशराइज्ड पाइप डालकर सीधे खेतों तक पानी पहुंचाएगी।

चंदेल राजाओं द्वारा बुंदेलखंड इलाके में तालाबों का निर्माण कराया गया था। पूरे बुंदेलखंड में करीब दो हजार चंदेलकालीन तालाब हैं। इनमें से करीब 500 जलाशय आज भी जीवित अवस्था में हैं। ये सभी तालाब आपस में जोड़े गए थे यानी एक तालाब के भरने के बाद उसके अतिरिक्त जल से अगला तालाब भरता था। इन्हीं जलाशयों के आसपास बावड़ियां भी बनाई गई थीं। केन-बेतवा लिंकेज नहर से चंदेलकालीन तालाब भी पुर्नजीवित हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का वर्चुअली लोकार्पण किया। केंद्र सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) योजना के तहत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मप्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट का ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दो चरणों में स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग पीवी प्लांट और दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर इंस्टालेशन में से एक है। पहले चरण में यहां तीन कंपनियों द्वारा 278 मेगावाट प्रदूषण मुक्त बिजली का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया हैं।

ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर स्थित पानी पर तैरते सौर ऊर्जा पावर हाउस के प्रथम चरण में 278 मेगावाट हरित ऊर्जा का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इससे मप्र को सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली मिलने लगी है। यहां एनएचडीसी 88 मेगावाट, एएमपी एनर्जी 100 मेगावाट तथा एसजेवीएन 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2030 तक देश में 5000 गीगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य का आह्वान किया गया है। इस दिशा में जिले की पुनासा तहसील में बैकवाटर पर स्थापित यह सोलर परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली एमपीपीजीसीएल को बेची जा रही है। इसके लिए बैकवाटर किनारे ग्राम सत्तापुर में 33 केवीए क्षमता का पावर सबस्टेशन व कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां 100-100 मेगावाट क्षमता के चार ट्रांसफार्मर लगाए हैं। जो 33 केवीए को 220 केवीए में परिवर्तित कर यहां से मप्र ट्रांसमिशन कंपनी के छैगांवमाखन सबस्टेशन को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इस परियोजना से एक साल में 204.58 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन होगा। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर जलाशय में 207.4 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर पैनल लगाए गए हैं। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी होती है। हर किलोवाट घंटे में करीब 50 ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड (सीओ-2) की बचत होती है। कोयले से बिजली बनाने की तुलना में करीब 20 गुना कम कार्बन उत्सर्जन होता है। कोयले से बिजली बनाने की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 80 प्रतिशत की कटौती होती है। कार्बन उत्सर्जन में इतनी काफी कमी होती है कि सौर पैनल लगाने के तीन साल के अंदर ज्यादातर सौर पैनल कार्बन तटस्थ हो जाते हैं। कार्बन उत्सर्जन में इतनी कमी होती है कि यह 432 गैलन गैस के कार्बन उत्सर्जन के बराबर होती है। यह कार्बन उत्सर्जन लगभग एक साल के लिए कार को सड़क से हटाने जैसा होता है।

● **जितेंद्र तिवारी**

प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के भागीरथः सीएम

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ये दिन भारत ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। जैसी गंगा को धरती पर लाया गया था, वैसे ही नदी जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के भागीरथ बन गए हैं। सीएम ने कहा, मप्र में जब भी सूखे की खबर आती थी, तो बुंदेलखंड का नाम सबसे पहले जहन में आता था। लोग अपने घरों के गेट निकालकर उन्हें ईंटों के पैक करके रोजगार की तलाश में घर छोड़कर चले जाते थे। बड़ा कष्ट होता था कि हमारा ये क्षेत्र सालों तक सूखे का दंश झेलता रहा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- कांग्रेस के लोग आते थे, सूखा दूर करने के लिए बड़े-बड़े वादे करते थे। लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन नदी जोड़ो परियोजना से 10 जिलों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा।

चंबल प्रोजेक्ट...सात साल से अधर में

ग्वालियर-चंबल अंचल के बड़े शहरों की प्यास बुझाने के लिए सात साल पहले तैयार किया गया चंबल प्रोजेक्ट अभी भी अधर में लटका हुआ है। यह स्थिति तब है जब इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश का पॉलिटिकल पावर एकजुट नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट का खाका तैयार हुआ था और उन्होंने भूमिपूजन किया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्रीय जोर रहा है। लेकिन योजना सात साल में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। वहीं अब 16 दिसंबर को वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेयू कैंपस में कार्य शुभारंभ के नाम पर भूमिपूजन किया है।

दरअसल चंबल नदी से पानी लाने की योजना 2017-18 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार के समय बनाई गई। उस समय अधिकारियों पर चुनाव से पहले टेंडर कराने का दबाव था और आनन-फानन में टेंडर अपलोड कर दिया गया। लेकिन टेंडर खुले नहीं। आचार संहिता के चलते टेंडर पर रोक लगा दी गई। इसके बाद सरकार बदली और कांग्रेस सत्ता में आई। चूंकि सरकार को श्रेय लेना था इसलिए प्रोजेक्ट में बहुत से बदलाव किए गए। फिर भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही ग्वालियर के साथ मुरैना को भी चंबल का पानी दिलाने को प्राथमिकता दी। वर्तमान में चंबल नदी-कोतवाल बांध से पानी लाने का प्रोजेक्ट देवरी गांव (मुरैना जिला) से ही बाहर नहीं आ सका है। जबकि जलालपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (ग्वालियर) तक का सफर 43 किलोमीटर का तय करना है। काम के नाम पर वहां अभी सिर्फ एक गड्ढ़ा ही नजर आया। जबकि प्रोजेक्ट पर काम करने वाली जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन एवं इनविराड प्रोजेक्ट (ज्वाइंट एडवेंचर) ने 12 मार्च 2024 को वर्क ऑर्डर लिया था। उसे 24 महीने में काम पूरा करना है, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी पाइपलाइन डालने का भी काम शुरू नहीं हो सका है।

चंबल नदी से पानी लाने के 458.64 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की रफ्तार राजनीतिक रस्साकशी और प्रशासनिक अड़चनों में फंस गई है। 14 महीने में दो मुख्यमंत्रियों से भूमिपूजन कराए गए। पहले 6 अक्टूबर 2023 को महाराज बाड़ा पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली जुड़कर और 16 दिसंबर को वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेयू कैंपस में कार्य शुभारंभ के नाम पर भूमिपूजन किया। खास बात यह है कि इन दोनों आयोजनों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। ग्वालियर नगर निगम को नेशनल हाईवे, रेलवे, जल संसाधन विभाग, और अन्य विभागों से जरूरी एनओसी लेनी है। एनएच-44 पर काम करने के लिए निगम को 16.57 करोड़ की लाइसेंस फीस और पर्सनल गारंटी के रूप में 3.95 लाख की राशि देनी है। निगम ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पत्र लिखकर राशि कम करने को कहा है। कोतवाल बांध पर इंटेकवेल के लिए जमीन आवंटित न होना और सांक नदी का मिट्टी परीक्षण जैसे मुद्दे काम में देरी की वजह बने हुए हैं। देवरी गांव से चंबल नदी का पानी संपवेल के जरिए ग्वालियर पहुंचाना है, लेकिन मौके पर केवल चार कर्मचारी काम करते दिखे। संपवेल का बेस तैयार होने में महीनों का समय लगने की संभावना है। कोतवाल बांध से ग्वालियर के लिए इंटेकवेल बनाने की योजना है, लेकिन अभी तक जमीन का चिन्हांकन तक नहीं हो पाया है। वहीं 43 किमी लंबी पाइपलाइन के लिए गड्ढ़ा खोदने तक का काम शुरू नहीं हुआ। इंविराड कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर एफआई खान का कहना है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कार्य शुभारंभ करने के बाद चंबल प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमिपूजन किया था उसके बाद देवरी गांव में गड्ढ़ा खोदा था। लेकिन अफसरों के मना करने के बाद काम रोक दिया गया था। वहीं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि चंबल से ग्वालियर तक पानी लाने के प्रोजेक्ट में किन कारणों से देरी हो रही है इसका पता लगाएंगे। काम समय में पूरा कराने का प्रयास करेंगे।

ग्वालियर शहर की वर्ष 2055 तक की पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किए गए चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत नूराबाद पर क्वारी नदी पर पुरातत्व महत्व के अंतर्गत आने वाले पुराने पुल के नजदीक नया पुल बनाने के लिए सहमति बन गई है। गत 9 सितंबर को भोपाल में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार और नगर निगम आयुक्त के साथ हुई बैठक में पुराने पुल से कम ऊंचाई का नया पुल बनाने की ड्राइंग देने पर सहमति बनी थी। इसके बाद निगम ने गत 20 सितंबर को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए प्रभारी मंत्री ने भी पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा है। अमृत योजना के दूसरे चरण में चंबल नदी व कोतवाल बांध से 150 एमएलडी प्रतिदिन पानी के लिए टेंडर स्वीकृत होने के बाद गत 11 मार्च को कंपनियों से अनुबंध किया गया था।

● **लोकेश शर्मा**

दोनों पुलों से कम रहेगी ऊंचाई

पुरातत्व विभाग के तकनीकी सलाहकार आरबी शाक्य व निगम अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान तय किया कि नूराबाद में वर्तमान में सांक व क्वारी नदी के ऊपर बने जिस पुल से ट्रैफिक का आवागमन होता है, उससे प्रस्तावित पुल की ऊंचाई 3.17 मीटर कम रखी जाएगी। इसके अलावा पुरातत्व महत्व के पुल से इसकी ऊंचाई डेढ़ मीटर कम रखी जाएगी। इससे पुरातत्व विभाग को एनओसी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस आधार पर नगर निगम ने संशोधित प्रस्ताव को आयुक्त सहसंचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय को भेज दिया है। संभावना है कि जल्द ही वहां से मंजूरी मिल जाएगी। नदी क्षेत्र में होने वाले निर्माण के लिए दो माह पहले प्रभारी मंत्री की पहल पर ही जलसंसाधन विभाग द्वारा नगर निगम को सांक नदी में निर्माण के लिए एनओसी प्रदान की जा चुकी है। अब पुरातत्व विभाग की अनुमति मिलते ही चंबल नदी व कोतवाल बांध से पानी लाने के लिए पाइपलाइन डालने के काम की शुरूआत हो जाएगी।

5 साल में मप्र में 61,872 मौतें

सड़क हादसों में मौत के मामले में मप्र के आंकड़े सदमा देने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में ये कड़वा सच सामने आया है। सड़कें खराब होने और मोबाइल पर बात और स्पीड के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रदेश में 5 साल के दौरान सड़क हादसों में 61,872 लोगों की मौत हो चुकी है। मप्र में साल 2019 में 11,249, 2020 में 11,341, 2021 में 12,057, 2022 में 13,427 और 2023 में 13,798 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है।

सरकार सड़क हादसों को रोकने के लाख दावे करती है, लेकिन केंद्र की रिपोर्ट और प्रदेश के मौजूदा आंकड़े उन तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट में मप्र के आंकड़े शॉकिंग हैं। मप्र चौथे नंबर पर है। मप्र से आगे उप्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। मप्र में इतनी बड़ी तादाद में रोड एक्सीडेंट होने के पीछे 12 प्रमुख कारण बताए गए हैं। इनमें खराब सड़कें, स्पीड, शराब पीना, मोबाइल पर बात करना प्रमुख कारण हैं। इसमें से 29 फीसदी मौतें हेलमेट नहीं पहनने के कारण हुईं। वहीं देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा 1.08 लाख मौतें उप्र में हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु 84 हजार मौत और महाराष्ट्र 66 हजार मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 2022 के डेटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुई थीं, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गईं। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। जब भी मैं किसी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है, तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं।

अगर राज्य स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की बात करें तो उप्र नंबर वन स्टेट के रूप में उभरकर सामने आता है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर मप्र और पांचवें स्थान पर कर्नाटक का नाम आता है। उप्र में साल 2019 में 22,665, 2020 में 19,149, 2021 में 21,222, 2022 में 22,595 और 2023 में 23,652 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हुईं। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर 2019 में 18,129, 2020 में 14,527, 2021 में 15,384, 2022 में 17,884 और 2023 में 18,347 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई। महाराष्ट्र में साल 2019 में 12,788, 2020 में 11,569, 2021 में 13,528, 2022 में 15,224 और 2023 में 15,366 लोगों की सड़क दुर्घटना की चपेट में आने की वजह से मौत हुई। इसी प्रकार मप्र में साल 2019 में 11,249, 2020 में 11,341, 2021 में 12,057, 2022 में 13,427 और 2023 में 13,798 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। कर्नाटक में साल 2019 में 10,958, 2020 में 9,760, 2021 में 10,038, 2022 में 11,702 और 2023 12,321 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हुई।

इस साल दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल 2,435 सड़क दुर्घटनाओं में 193 लोगों की जान चली गई। यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 1 जनवरी से 31 अक्टूबर के बीच 1,865 लोग घायल भी हुए। 2023 में, 2,498 सड़क दुर्घटनाओं में 155 लोग मारे गए, जबकि इसी अवधि के दौरान शहर में 1,917 लोग घायल हुए। यातायात पुलिस ने कहा कि इस साल दर्ज की गई घातक सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति थी। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि शहर की सड़कें उनकी हाई-एंड बाइक और एसयूवी को तेज गति से चलाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जिनकी अधिकतम गति 150-200 किमी प्रति घंटा है। एक बार फिर, मिसरोद पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र सड़क दुर्घटना में घायलों के मामले में शहर का सबसे घातक क्षेत्र बनकर उभरा। यातायात पुलिस का कहना है कि शहर में होने वाली लगभग 90 प्रतिशत घातक सड़क दुर्घटनाओं में तेज गति मुख्य कारण पाई गई है। इसके अलावा यातायात नियमों और सुरक्षा उपायों का पालन करने में लापरवाही दुर्घटनाओं का कारण बनती है।

● बृजेश साहू

2024 में 63,318 चालान हुए जारी

एक वरिष्ठ यातायात अधिकारी ने बताया कि यातायात पुलिस ने साल 2024 में अब तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के 63,318 चालान जारी किए हैं, जो इसी अवधि के दौरान 2023 में जारी किए गए चालानों से अधिक है। इस साल हेलमेट न पहनने पर 34,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि सीटबेल्ट न पहनने पर 8,800 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया। सख्ती के बावजूद लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 1 जनवरी से 31 अक्टूबर के बीच मिसरोद में सड़क हादसों में 22 लोगों की मौत हुई, जो शहर में सड़क हादसों में मरने वालों की सबसे अधिक संख्या है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मिसरोद क्षेत्र में होशंगाबाद रोड को अत्यधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। दुर्घटनाओं के प्राथमिक कारणों में सड़क के डिवाइडर पर कट पॉइंट और आवासीय कॉलोनियों को मुख्य हाईवे से जोड़ने वाली सड़कें शामिल हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने से स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन सड़क के चौड़ीकरण से वाहनों की गति बढ़ गई है। कई दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि आसपास की कॉलोनियों के निवासी बिना सामने से आने वाले तेज रफ्तार वाहनों की जांच किए लापरवाही से हाईवे पर एंट्री करते हैं। पुलिस ने कहा कि ड्राइवरों को पूरी तरह से रुककर सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क साफ है, और उसके बाद ही हाईवे पर आगे बढ़ना चाहिए।

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सुशासन पर पूरा फोकस है। लेकिन आंकड़ों के महारथी अफसर सरकार की आंख में धूल झोंककर फर्जीवाड़ा और घोटाला करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका खुलासा मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में हुआ है।

सरकार को लगाई अरबों की चपत

मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में मप्र के कई विभागों में हेराफेरी के मामले सामने आए हैं। सरकार ने 18 दिसंबर को बिजली कंपनियों, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की 2018 से 2022 के वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी। कैग की रिपोर्ट में तीनों ही विभागों में वित्तीय अनियमितता और योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ियां पाई गईं। इसकी वजह से राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। सड़कों के निर्माण में अनियमितता बरती गई। सड़क निर्माण के दौरान जरूरी स्पेसीफिकेशन और नियमावली का पालन नहीं किया और सड़क निर्माण की निगरानी तय मानदंडों के मुताबिक नहीं हुई और संबंधित जिम्मेदार लोगों ने कागजों में इसको गलत तरीके से लोक निर्माण विभाग के सामने पेश किया। बता दें कि कैग एक संवैधानिक संस्था है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च का लेखा-जोखा रखती है।

सीएजी के अनुसार, मप्र की मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने साल 2019 में केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार हासिल किया था लेकिन ये पुरस्कार गलत आंकड़े पेश कर लिया गया था। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती 16 हजार सांस और ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों में से 3025 की मौत हो गई क्योंकि उन्हें इलाज के लिए दवाएं ही नहीं मिलीं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शाला त्यागी बालिकाओं का सर्वे नहीं किया और 5.08 लाख फर्जी हितग्राहियों को पोषण आहार बांट दिया। इस तरह 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सौभाग्य योजना के तहत दूर-दराज के ऐसे गांव, जहां बिजली की पहुंच नहीं है, वहां केंद्र सरकार ने हर परिवार को सोलर एनर्जी से 200 वॉट बिजली देने का फैसला किया था। इसके लिए हर घर में एक यूनिट लगाई जानी थी। प्रति यूनिट 31,348 रुपए हजार खर्च आना था। मप्र सरकार को इस योजना के लिए 1871 करोड़ रुपए मिले थे। राज्य सरकार ने कहा था कि वह योजना पर 10 प्रतिशत राशि व्यय करेगी। कैग की रिपोर्ट कहती है कि पूर्व क्षेत्र कंपनी ने इसके लिए लोन लिया और उसे मार्च 2022 तक ब्याज के तौर पर 24 करोड़ रुपए देने पड़े। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मप्र में बिजली कंपनियों ने पहले 50 वॉट के पैनल 17,622 रुपए और फिर 150 वॉट के पैनल 24,774 रुपए में लगाए। इस तरह हर यूनिट पर 11 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए गए। नया कनेक्शन देने के लिए केबल का खर्च 3 हजार रुपए फिक्स था लेकिन पूर्व क्षेत्र कंपनी ने दो तरह के केबल का इस्तेमाल किया। एक केबल के लिए 3514 रुपए और दूसरे के लिए 4461 रुपए के हिसाब से भुगतान कर दिया। ऐसे में प्रति कनेक्शन 946 रुपए का भुगतान किया गया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे कंपनी को 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

कैग के मुताबिक, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन का ठेका ई-टेंडर के माध्यम से दिया जाना था लेकिन पूर्व व पश्चिम विद्युत वितरण कंपनियों ने 1 लाख 38 हजार घरेलू कनेक्शन के लिए टुकड़ों में 4 हजार से ज्यादा वर्क ऑर्डर निकाले। इनके जरिए 50 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। इसी तरह कनेक्शन के लिए 4 एमएम का तार इस्तेमाल करना था लेकिन कैग ने जांच में पाया कि तीनों कंपनियों ने 3 लाख 36 हजार से ज्यादा घरों में

स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल

मप्र में स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, मप्र सरकार ने स्वीकृत संख्या के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की। जिला अस्पतालों में 6 से 92 फीसदी, सिविल अस्पतालों में 19 से 86 फीसदी, सामुदायिक, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में 27 से 81 फीसदी डॉक्टरों की कमी देखी गई। मेडिकल कॉलेजों में 27 से 43 फीसदी डॉक्टरों की कमी पाई गई। इसी तरह अस्पतालों में नर्सों की कमी पाई गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू में भर्ती 34 हजार 643 मरीजों में से 16 हजार 848 (48.64 फीसदी) सांस और हार्ट पेशेंट्स थे। इनमें से 3025 (18 फीसदी) मरीजों की मौत हो गई। इसकी वजह ये रही कि इन मरीजों को इलाज के लिए जरूरी 16 अहम दवाओं में से 11 दवाएं नहीं मिलीं। इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं के इलाज के लिए 26 महत्वपूर्ण दवाएं नहीं थीं। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि दवाओं की कमी चिंता का विषय है। साथ ही दवाओं के स्टॉक के मिस मैनेजमेंट की वजह से भोपाल, ग्वालियर और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की 200 से ज्यादा दवाएं एक्सपायर हो गईं। केंद्र सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने की शुरुआत की थी। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को 10 फीसदी तक कम करना था। कैग ने सभी जिला अस्पतालों से ट्रॉमा केयर सेंटर के आंकड़े इकट्ठा किए तो पता चला कि 18 जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर काम ही नहीं कर रहे थे। इसकी अलग-अलग वजहें सामने आईं। अशोकनगर में स्टाफ और उपकरण नहीं थे तो बुरहानपुर में भवन ही नहीं था। कई जिलों में भवन थे मगर उनका इस्तेमाल ट्रॉमा केयर सेंटर के रूप में नहीं किया गया था।

बिजली कनेक्शन के लिए 2.5 एमएम के तार का इस्तेमाल किया। कैग ने कहा है कि सौभाग्य योजना की कार्ययोजना ही गलत बनाई गई। बिजली कंपनियों ने पहले बताया कि 9 लाख घर ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है। जब डीपीआर बनी तो ऐसे घरों की संख्या 9 लाख 77 हजार 056 हो गई। जब इसे संशोधित किया गया तो यह संख्या घटकर 5 लाख 4 हजार 841 रह गई जबकि वास्तविक घरों की संख्या 5 लाख 9 हजार 053 है। केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2018 को एक पुरस्कार शुरू किया था। जिसमें कहा गया था कि सौभाग्य योजना का कंपनी स्तर पर 30 नवंबर 2018 तक 100 फीसदी घरेलू कनेक्शन देने का टारगेट था। मप्र की दो कंपनी- पश्चिम व मध्य विद्युत वितरण कंपनी ने इस टारगेट को पूरा करने का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया था। इसके आधार पर केंद्र ने दोनों कंपनियों को 100-100 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया, जबकि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक यह टारगेट 2019 में पूरा हुआ था। पुरस्कार की अवधि निकल जाने के बाद मध्य क्षेत्र कंपनी ने 4 हजार 725 घरों में कनेक्शन करने के 24 वर्क ऑर्डर दिसंबर 2018 में जारी किए थे। यह काम अक्टूबर 2019 में पूरा किया गया था। इसी तरह पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने यह टारगेट जून 2019 में पूरा किया था।

मप्र में विद्युत वितरण कंपनियों की लापरवाही से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है। गौरतलब है कि गतदिवस विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखी गई। इस रिपोर्ट में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बिजली वितरण कंपनियों और पॉवर जनरेशन कंपनी की लापरवाहियों का खुलासा किया गया है। इससे कंपनियों को करोड़ो का घाटा हुआ है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में

सभी गैर-विद्युतीकृत गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की थी। जांच में परियोजना के निर्माण, कार्य के आवंटन में कमियां मिलीं। डीपीआर के तहत 97,756 घरों के विद्युतीकरण किया जाना था, लेकिन 5,09,053 घरों का विद्युतीकरण हो पाया। इसके चलते 42.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वितरण कंपनियों ने दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन करते हुए निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित किए बिना 138,054 घरों के विद्युतीकरण के लिए 50.62 करोड़ रुपए के 4080 आदेश जारी कर दिए। मप्रपूक्षेविविकंलि ने योजना दिशा-निर्देशों का उलंघन करते हुए 98.93 करोड़ से अधिक का ऋण लिया और उसे 24.65 करोड़ का ब्याज का भुगतान करना पड़ा। वितरण कंपनियों ने अगर ईसी के समक्ष योजनांतर्गत 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण को जल्दी पूरा करने की असत्य घोषणा कर, अपात्र होते हुए भी नकद पुरस्कार और 250.53 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर, विद्युतगृह में वर्ष 2019-20 और 2021-22 में मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाया। इससे 106.57 करोड़ की सीमा तक स्थायी लागत की वसूली कम हुई। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारनी में नियामक आयोग द्वारा 2019-20 से 2021-22 तक निर्धारित उच्च सकल स्टेशन ऊष्मा दर मानदंडों को बनाए रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 32.12 करोड़ मूल्य के 116041.76 मीट्रिक टन कोयले की अतिरिक्त खपत हुई। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी के प्रत्येक विद्युतगृह के लिए सहायक खपत मानदंड तय किए हैं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर विद्युतगृह, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारनी विद्युतगृह और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चचाई वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंदर सहायक ऊर्जा की खपत को प्रतिबंधित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 14.30 करोड़ मूल्य की 74.78 एमयू विद्युत की अतिरिक्त खपत हुई।

● **कुमार विनोद**

टेक होम राशन की आपूर्ति में फर्जीवाड़ा

कैग ने टेक होम राशन पर लेखा परीक्षण किया, जिसकी कई गड़बड़ियों को रेखांकित किया है। प्रदेश में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताएं और 11 से 14 वर्ष शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत टेक होम राशन दिया जाता है। इसे प्रदेश के विभिन्न संयंत्रों में तैयार किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन ट्रेकों से टेक होम राशन की परियोजनाओं को आपूर्ति बताई गई वे जांच में मोटर साइकिल, कार, ऑटो और ट्रैक्टर के नंबर निकले। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे लिपिकीय त्रुटि बताया, जिसे कैग ने अस्वीकार कर दिया। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैग 2021 में टेक होम राशन का लेखा परीक्षण किया था। इसमें जिन फर्मों ने ट्रकों द्वारा 2.96 करोड़ रुपए का 467 टन टेक होम राशन की आपूर्ति बताई थी, वाहन पोर्टल पर जांच में वे ट्रक के नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो, ट्रैक्टर और टैंकर के रूप में पंजीकृत पाए गए। इससे साफ है कि फर्जी आपूर्ति के अभिलेख प्रस्तुत किए गए। यह आपूर्तिकर्ताओं और परियोजना अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इसके अलावा इस आपूर्ति के लिए फर्मों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और रियायती दर पर गेहूं और चावल के अंतर के रूप में 35.74 लाख रुपए का अनुचित लाभ उठाया। ढाई करोड़ रुपए के 404 टन टेक होम राशन की आपूर्ति उन ट्रकों के माध्यम से की गई, जिनके अभिलेख वाहन पोर्टल पर नहीं पाए गए।

इकोनॉमी के डॉक्टर, राजनीति के गेमचेंजर...

देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से शोक में है। देश में सात दिन का राष्ट्रीय शोक है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्षी कांग्रेस और अन्य पार्टियों तक, तमाम शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर सिंह के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि देश ने एक विशिष्ट नेता खो दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर सिंह को अपना गुरु बताते हुए कहा है कि मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक, ग्लोबलाइजेशन का शिल्पकार भी बताया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। डॉक्टर सिंह ने शुरुआती पढ़ाई गाह गांव के प्राइमरी स्कूल से ही की। विभाजन के समय डॉक्टर सिंह का परिवार अमृतसर में बस गया। मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और एमए की पढ़ाई की और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया।

अर्थशास्त्र डीफिल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योजना आयोग में सहायक सचिव से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में आमूलचूल बदलाव किए। डॉक्टर सिंह ने 16 सितंबर 1982 को आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला और 14 जनवरी 1985 तक वे इस पद पर रहे। डॉक्टर सिंह के आरबीआई गवर्नर रहते बैंकिंग क्षेत्र में कई कानूनी सुधार हुए, शहरी बैंक विभाग की नींव पड़ी और आरबीआई एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया। बैंकों की स्वायत्तता के पक्षधर रहे डॉक्टर सिंह ने ही यह प्रावधान किया था कि बैंकों को अपनी कुल जमाराशि का 36 फीसदी सरकार के पास सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में रखना होगा। इसे ही एसएलआर कहा जाता है।

राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने 1985 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया था। 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मनमोहन सिंह का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास पर रहा। आरबीआई गवर्नर और योजना आयोग का उपाध्यक्ष रहते डॉक्टर सिंह ने सुधारवादी कदम उठाए और देश जब 1990 के दशक में आर्थिक संकट के भंवर में था, बतौर वित्त मंत्री उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही पूरी तरह से बदलकर रख दी। मनमोहन के फैसलों ने देश को आर्थिक संकट से बाहर लाने में बड़ा योगदान दिया और नए भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। बतौर वित्त मंत्री अपने पहले ही बजट भाषण में डॉक्टर सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म करने, विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था खोलने का ऐलान किया। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन के युग की शुरुआत की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के फैसले क्रैश हो गई, दिवालिएपन के मुहाने पर खड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल साबित हुए। एक मुश्किल समय में मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डॉक्टर साबित हुए।

डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब सियासत में कदम रखा था, वह दौर मंडल और कमंडल की राजनीति का था। डॉक्टर सिंह ने मंडल-कमंडल की सियासत के बीच विकास को भी प्रमुखता से स्थापित किया। राजनीति के गेमचेंजर डॉक्टर सिंह का ये चेंजिंग मोड प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने तक भी कायम रहा। मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बने, गठबंधन की राजनीति जोरों पर थी। सरकार पर प्रधानमंत्री और लीडिंग पार्टी से अधिक घटक दल हावी माने जाते थे। ऐसे दौर में डॉक्टर सिंह ने सहयोगियों के विरोध और समर्थन वापसी के दबाव में झुके अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार पर कदम वापस लेने की जगह सत्ता दांव पर लगा उसे अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता चुना। मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसे कानून आए, आधार कार्ड आया और डायरेक्ट कैश बेनिफिट की बात शुरू हुई। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए-1 सरकार के समय हुई किसान कर्जमाफी भी 2009 के लोकसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई। 2009 के आम चुनाव में जीत के साथ कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और मनमोहन सिंह का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पांच साल सरकार चलाने के बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का जनादेश पाने वाले पहले प्रधानमंत्री के तौर पर भी दर्ज हो गया।

1991 में, जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में देश ने उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण (एलपीजी) की नीति अपनाई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाला और उसे तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर किया। विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग खत्म हो गया था, उनके सुधारों के बाद स्थिर हो गया। उन्होंने आयात-निर्यात नीतियों में बदलाव, टैक्स सुधार और औद्योगिक लाइसेंस राज को समाप्त करके व्यापार को प्रोत्साहित किया। मनमोहन सिंह अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे राजनीतिक जीवन में आदर्श माने जाते रहे हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन बेहद सादा था, और उन्होंने कभी भी राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत संपन्नता के लिए अपने पद का उपयोग नहीं किया। वह न दिखावे में विश्वास रखते थे और न ही भव्यता में। उनकी सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण उनका निजी जीवन है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे सामान्य जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्ध रहे। वे साधारण भोजन करते थे और हमेशा अपनी पत्नी के साथ एक सामान्य परिवार की तरह जीवन जीते रहे। उन्होंने कभी भी अपने पद का उपयोग करके अपने लिए विशेष सुख-सुविधाएं नहीं जुटाईं।

● **प्रवीण सक्सेना**

वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व

प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उनकी शांत और सटीक कूटनीति ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया। जी-20, ब्रिक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत के हितों को मजबूती से रखा। उनकी विशेषज्ञता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें वैश्विक नेताओं में से एक महान विचारक कहा था। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। वे छात्रों के बीच एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका यह अनुभव प्रधानमंत्री के रूप में नीति-निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में प्रेरित किया। मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व राजनीति तक सीमित नहीं था। वे एक विद्वान, शिक्षक और प्रशासक भी थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले, उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इन सभी भूमिकाओं में उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा।

मप्र धार्मिक स्थलों का पानी सबसे प्रदूषित

मप्र को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है जहां 200 से ज्यादा छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं। इसके बावजूद दो दर्जन से ज्यादा ऐसी नदियां हैं जो प्रदूषित हो चुकी हैं। इनमें से क्षिप्रा, बेतवा, नर्मदा नदियां तो ऐसी हैं कि इनका पानी पीना तो दूर आचमन करने लायक भी नहीं बचा है। खासकर इन नदियों के किनारे स्थिति धार्मिक स्थलों का पानी सबसे अधिक प्रदूषित है। इसका खुलासा मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) की रिपोर्ट में हुआ है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मप्र की 89 नदियां ऐसी हैं, जिनमें सालभर पानी रहता है। एमपीपीसीबी ने इन नदियों के रूट पर 293 स्थानों पर पानी की जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि 197 जगहों का पानी ए-कैटेगरी का है। जबकि 96 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई। इनमें से 60 से अधिक स्थान धार्मिक स्थलों के पास हैं। यहां का पानी आचमन या स्नान तो छोड़िए हाथ धोने के लायक भी नहीं है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश की गई एमपीपीसीबी की 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन में नदियों के पानी की गुणवत्ता की वार्षिक औसत स्थिति के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में इंदौर की कान्ह (खान) नदी को सबसे प्रदूषित बताया गया है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी की स्थिति भी खराब है। देवास की छोटी कालीसिंध नदी सूखने से उसकी जांच नहीं हो सकी। एमपीपीसीबी ने 5 कैटेगरी में गुणवत्ता जांची है। ए-कैटेगरी का पानी रोगाणु मुक्त होता है। ये बिना किसी परंपरागत उपचार के सीधे पीने के लिए उपयुक्त है। बी-कैटेगरी में रोगाणु (जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव) पाए जाते हैं। यह धुलाई या सफाई के लिए उपयुक्त है। सी-कैटेगरी के पानी में अतिरिक्त हैवी मेटल और अन्य प्रदूषक तत्व होते हैं। डी-कैटेगरी के पानी का रंग पूरी तरह काला हो जाता है। ई-कैटेगरी का पानी उद्योगों से निकले अपशिष्ट या अत्यधिक घातक प्रदूषण से प्रभावित होता है।

एमपीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार कान्ह सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। वहीं चंबल का पानी भी डी-कैटेगरी का है। बेतवा नदी में मंडीदीप के अपस्ट्रीम और नयापुरा डाउनस्ट्रीम पर पानी सी-कैटेगरी का है। यह पानी नहाने के योग्य भी नहीं है। भोजपुर मंदिर ब्रिज और विदिशा के चरणतीर्थ घाट पर भी पानी बी-कैटेगरी का है। चंबल नदी में उज्जैन के जूनानागदा, इटलावदा, गीदघर में पानी डी-कैटेगरी का है। राजगढ़, ताल रोड ब्रिज के पास पानी सी-कैटेगरी का है। क्षिप्रा नदी में देवास के एबी रोड जलप्रदाय केंद्र पर पानी ए-कैटेगरी का है। हवनखेड़ी नागदमन से पानी डी-कैटेगरी में आ जाता है। उज्जैन के गोघाट, रामघाट, सिद्धवटघाट से महिदपुर तक पानी काला और डी-कैटेगरी का है। मंदाकिनी नदी में चित्रकूट में उद्गम स्थल पर पानी ए-कैटेगरी का है। स्फटिक शिला से रामघाट तक पानी बी-कैटेगरी का है। कान्ह (खान) नदी में इंदौर के लीम्बोड़ी शिवधाम में पानी डी-कैटेगरी का है। कमला नेहरू पार्क, अहिल्या आश्रम, खाटीपुरा और धान खेड़ी में पानी ई-कैटेगरी का है। क्षिप्रा से मिलने से पहले रामवासा में पानी डी-कैटेगरी का है। नर्मदा नदी में अमरकंटक के पास पुष्पकर डैम, कपिलधारा और बुदनी क्षेत्र में पानी बी-कैटेगरी का है। पार्वती नदी में सीहोर में पानी बी-कैटेगरी का है, लेकिन जिले से बाहर निकलते ही ए-कैटेगरी का हो जाता है। शिवना नदी में मंदसौर में रामघाट पर पानी ए-कैटेगरी का है। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के पास पानी सी-केटेगरी का है। तमसा (टोंस) नदी में सतना के बरधिया घाट पर पानी बी-कैटेगरी का है, जबकि रीवा में ए-कैटेगरी का है।

मप्र के छोटे और कस्बाई शहरों के पास से गुजरने वाली 32 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना फाइलों में अटकी हुई है। जो विधानसभा में छोटी नदियों की साफ-सफाई को लेकर पूछे गए एक सवाल में सामने आई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 253 नगरीय निकायों को यूज्ड और ग्रे-वाटर को ट्रीटमेंट के बाद या रीसाइकिल कर नदियों में गंदा पानी जाने से रोकना था। इसका उद्देश्य इन नदियों को निर्मल और अविरल बनाना है। तीन साल पहले इन प्रोजेक्ट्स के लिए राशि मंजूर की गई थी, लेकिन 110 नगरीय निकायों के प्रोजेक्ट अब तक फाइलों से बाहर नहीं आ सके हैं। 32 नदियों में से सिर्फ 2 नदियों से जुड़े शहरों में ही काम ठीक स्थिति में है। इनमें सीहोर का बुदनी और ग्वालियर का पिछोर शामिल है।

● **अरविंद नारद**

40 से ज्यादा नदियों का अस्तित्व खतरे में

मप्र को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है कि यहां 200 से ज्यादा छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं इसमें से कई नदियों का यहीं से उद्गम भी होता है। इनमें से 40 से ज्यादा ऐसी नदियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है और लगभग 20 नदियां ऐसी हैं जिनका पानी आचमन करने लायक नहीं है, इनमें से 5 ऐसी बड़ी और प्रमुख नदियां शामिल हैं। अगर लोगों ने इन नदियों को प्रदूषित करना नहीं छोड़ा तो तय मानिए कि वह दिन दूर नहीं जब ये विलुप्त हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां इन्हें किताबों में ही पढ़ेंगीं। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के तहत नदियों के पानी की जांच की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदियों की जल गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाता है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल नदियों की संख्या की बात करें तो वो लगभग 603 हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 279 नदियां प्रदूषित पाई गईं। इन 279 नदियों के 817 स्थानों पर बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर 3 एमजी/एल से अधिक था। हालांकि साल 2022 और 2018 से तुलना की जाए तो 2022 में नदियों के प्रदूषण में सुधार देखा गया है। साल 2018 की बात करें तो उस समय 31 राज्यों की 323 नदियां प्रदूषित थीं। इस रिपोर्ट में यदि मप्र की बात की जाए तो अलग-अलग श्रेणी में प्रदूषण के अनुसार यहां 19 नदियां प्रदूषित हैं।

चाइनीज लहसुन से किसान परेशान

भारतीय मंडियों में लहसुन के गिरते दाम को लेकर इन दिनों लहसुन उत्पादक किसान और लहसुन व्यापारी चिंतित हैं। खासकर मप्र में इसे लेकर लहसुन पंचायत हो रही है और सियासत भी गर्मा रही है। लहसुन के दाम गिरने की मुख्य वजह विदेश से चोरी-छिपे आयात की जा रही लहसुन को बताया जा रहा है। किसानों और व्यापारियों का मानना है कि चीन से प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज लहसुन नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए भारतीय मंडियों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पिछले एक महीने में लहसुन के दाम प्रति क्विंटल 10 से 15 हजार रुपए तक नीचे गिर गए हैं। वहीं रिटेल में भी लहसुन की कीमत 100 प्रति किलो तक कम हो चुकी है।

लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र मालवा में जावरा के किसानों ने चाइना की लहसुन होने के संदेह में अफगानिस्तान से आयातित लहसुन के दो ट्रक भी पकड़े हैं। दरअसल, भारत में चीन से लहसुन के आयात पर बीते 10 वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र और जापान से लहसुन का आयात भारत में होता है। इस वर्ष भारत में लहसुन के दाम अच्छे मिलने की वजह लहसुन उत्पादक किसानों और व्यापारियों को फायदा भी मिला है। हालांकि, रिटेल ग्राहकों के लिए लहसुन 350 रुपए से लेकर 500 किलो तक भी महंगी हो गई थी। लेकिन विदेश से आयातित होकर भारतीय मंडियों में पहुंचे लहसुन की वजह से लहसुन के भाव 10 से 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए। इसके बाद लहसुन उत्पादक किसानों और व्यापारियों को लहसुन के दाम गिरने की चिंता सताने लगी है। वहीं, किसानों और व्यापारियों का मानना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत आ रही लहसुन चीन की प्रतिबंधित अमानक लहसुन है, जिसकी वजह से लहसुन का बाजार लगातार गिर रहा है।

लहसुन व्यापारी और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के जानकार निलेश बाफना के मुताबिक, लहसुन के बाजार गिरने का मुख्य कारण विदेश से आयात किया जा रहा लहसुन ही है। चीन में उत्पादित लहसुन भारत में दो रूट से लाया जा रहा है, जिसमें पहले नेपाल के रास्ते बिहार में स्मगल कर लहसुन लाया जा रहा है। वहीं, चीन से अफगानिस्तान के एक्सपोर्टर लहसुन खरीद कर भारत की मंडियों में भिजवा रहे हैं, जिसका असर लहसुन के दामों पर सीधे पड़ रहा है। 1 महीने में करीब 15000 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की गई है। आगामी सीजन में भी लहसुन के दाम कम होने की संभावना बनी हुई है। रिटेल में प्याज और लहसुन जैसी खाद्य सामग्री और वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार विदेश से प्याज और लहसुन का आयात करती है। भारत में अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र और जापान से लहसुन का आयात किया जाता है। करीब 10 वर्षों से चीन लहसुन के आयात पर प्रतिबंधित है। लेकिन अन्य देशों से लहसुन का आयात किया जाता है। इस वर्ष रिटेल में लहसुन के दाम 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से लहसुन शहरों में आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो गया था। रिटेल लहसुन व्यापारी सुरेश शर्मा बताते हैं कि 1 महीने में विदेशी आयात की वजह से रिटेल में भी 100 रुपए प्रति किलो तक लहसुन के दाम गिर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने चीन का प्रतिबंधित लहसुन मप्र की मंडियों में बेचे जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि चीन का प्रतिबंधित लहसुन लगातार बाजार में आ रहा है। इससे लहसुन उत्पादक किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। चीनी लहसुन बाजार में आने का सुबूत यह है कि पिछले दिनों रतलाम में ऐसे दो ट्रक लहसुन को किसानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

दिग्विजय ने बताया कि मप्र के रतलाम, मदंसौर, नीमच सहित पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान के रास्ते से चीन का लहसुन आयात किया जा रहा है। इससे किसानों द्वारा उपजाए जाने वाले लहसुन की कीमत कम हो गई, जिससे 500 रुपए किलोग्राम की दर से लहसुन का बीज खरीदकर लगाने वाले किसानों को घाटा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में किसानों द्वारा उत्पादित लहसुन की मांग पूरे देश में होती है। इंदौर सहित अन्य स्थानीय मंडियों के माध्यम से स्थानीय व्यापारी इस लहसुन को खरीदकर देश के अन्य भागों में विक्रय के लिए भेजते हैं। कुछ दिन पूर्व मंदसौर जिले के नयाखेड़ा के पास दो लहसुन से भरी गाड़ियों को मंडी सचिव द्वारा अफगानिस्तान के कागज दिखाने के बाद भी बिना जांच पड़ताल के छोड़ दिया गया है, जो अटारी बॉर्डर से बेंगलुरु की ओर जा रही थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीमावर्ती देशों के रास्ते भारत में बिकने आ रहे चीन के लहसुन की जांच करने केंद्र सरकार से अनुरोध करने की मांग की।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

बैन है चीनी लहसुन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गत दिनों एक याचिकाकर्ता ने प्रतिबंधित लहसुन को पेश किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रतिबंधित चीनी लहसुन इन दिनों बाजारों में खुलेआम बिक रहा है। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार से देश में चीनी लहसुन पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश पेश करने को कहा और यह भी बताने को कहा कि चीन से उक्त प्रतिबंधित लहसुन के आयात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। मामले के याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 2014 में चीनी लहसुन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसमें कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी यह बाजार में खुलेआम बिक रहा है। जब अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि लहसुन कहां है, तो उसने कहा कि वह इसे लेकर आया है। इसके बाद अदालत की अनुमति से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने इसे सील कर जांच के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि चीनी लहसुन को खाने से पेट से संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं। किडनी पर भी यह लहसुन बुरा असर डालता है।

कुपोषण का नहीं मिट रहा दंश

मप्र में कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि कुपोषण को रोकने के जितने प्रयास हो रहे हैं, वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कुपोषित बच्चों का आहार आखिर जमीन खा रही है या आसमान निगल रहा है। शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश के कम वजनी व कुपोषित बच्चे योजनाओं के संचालन की हकीकत बयां कर रहे हैं। गांव-गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषण रोकने के लिए महिलाओं के गर्भवती रहने से लेकर बच्चों के पांच साल होने तक आहार दिया जाता है। साथ ही अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। फिर भी कुपोषण का दंश कम नहीं हो रहा है।

सरकार के तमाम वादों और दावों के बावजूद प्रदेश के आदिवासी इलाके कुपोषण के दंश से बेहाल हैं। प्रदेश के 15 लाख में से करीब 70 हजार बच्चे कुपोषण के दायरे में हैं। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, श्योपुर, शिवपुरी व खरगोन सहित कई इलाके कुपोषण की गिरफ्त में आ चुके हैं। बता दें कि गांवों में संचालित होने वाली अनेक आंगनवाड़ियों के ताले तक नहीं खुलते, जिससे ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। इसका नतीजा होने वाले बच्चे के शरीर पर पड़ता है। खास बात यह है कि योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च तो किए गए लेकिन कुपोषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुपोषण को लेकर ग्रामीण इलाके की तस्वीर सबसे भयावह है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बाहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका पदस्थ है, जिसके चलते आंगनवाड़ी न तो समय पर खुलती और न हीं बंद होती है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी भी निरीक्षण कर महज औपचारिकता पूरी करते हैं। गौरतलब है कि शासन के तमाम प्रयास के बावजूद कुपोषण का कलंक नहीं मिट पा रहा है। कुपोषण समाप्त करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कुपोषण की स्थिति कम नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण आंगनवाड़ी पर मिलने वाली सुविधाएं बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जबकि शासन ने गर्भ अवस्था से ही बच्चों के देखरेख की जिम्मेदारी आंगनवाड़ियों को सौंप रखी है। लेकिन जिले में कई आंगनवाड़ियों के ताले तक नहीं खुलते, वहीं कई आंगनवाड़ियां ऐसी हैं जहां दर्ज बच्चों की संख्या में से नाममात्र ही आंगनवाड़ी पहुंचते हैं। कार्यकर्ता व सहायिका उन्हें आंगनवाड़ी तक लाने में असफल रहती हैं।

आदिवासी बहुल शहडोल जिले में कुपोषण के भयावह हालात हैं। जिले में पोषण पुर्नवास केंद्र तक बच्चों को लाने में विभाग लापरवाह है। 20 बेड वाले जिला चिकित्सालय पोषण पुर्नवास केंद्र में शहर से सटे गोरतरा में रहने वाला इकलौता बच्चा भर्ती है। जिले में 6 केंद्र हैं जहां 70 से ज्यादा बच्चे भर्ती हो सकते हैं। लेकिन लापरवाही के चलते बच्चे केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे। जिले में 5 से 9 नवंबर तक स्वास्थ्य जांच शिविर में 1622 कुपोषित बच्चों की जांच की गई थी। समाजसेवी चिन्मय मिश्र का कहना है कि सहारिया वर्ग को जंगल से निकाला गया। पहले वे कुपोषित नहीं थे, अपने हिसाब से खाते थे, लेकिन उनके रहन-सहन बदलने का असर हुआ है। आदिवासी तबके में कुपोषण बढ़ना चिंताजनक है।

कुपोषण को कम करने और उसे मिटाने की कागजों में बाजीगरी करने वाले अधिकारी आंकड़ों को तो घटा सकते हैं लेकिन हकीकत को नहीं बदल सकते। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में कुपोषण का काला टीका अभी सैकड़ों बच्चों के माथे पर लगा हुआ है। बचपन का खून चूसकर कुपोषण ने इन बच्चों को अपंग बना दिया है। तीन से चार साल तक बच्चे हो गए लेकिन उनका वजन उतना है जितना एक हाल के जन्मे बच्चे में होता है। छतरपुर एनआरसी में ऐसे बच्चे पहुंचे हैं जिनको देखकर आपका हृदय पसीज उठेगा। क्योंकि सरकार कुपोषण को मिटाने के लिए हर महीने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इलाज से लेकर पोषण आहार तक की व्यवस्था संचालित की है। लेकिन छतरपुर जिले में महिला बाल विकास के दिखावटी आंकड़े और लापरवाही ने इन कुपोषितों को जिंदगी और मौत के मुहाने पर लाकर रख दिया है। यह वो कुपोषित बच्चे हैं जो भूखे रह-रहकर कुपोषित हो गए। चार साल की उम्र होने के बाद भी यह अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। इधर विभागीय अधिकारी कहते हैं कि जिले में तो कुपोषण अब कहीं नहीं है। छतरपुर जिले के गंज क्षेत्र के जीवनपुरा गांव की रहने वाली आरती चार साल की है, लेकिन उसका वजन मात्र चार किलो है। सूखते हाथ-पांव और रग-रग में बसे कुपोषण ने आरती को अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में ला दिया है। चार साल की आरती की मां का कहना है कि राशन नहीं मिलता, आज तक कोई बीमार बच्चों को देखने तक नहीं आया। जब हालत ज्यादा खराब हो गई तो वह अपने तीन बच्चों के साथ अस्पताल गई। आरती बेहद गंभीर है।

● **सुनील सिंह**

पोषण आहार पर 1200 करोड़ से अधिक खर्च

प्रदेश में पोषण आहार पर हर साल 1200 करोड़ से अधिक खर्च होते हैं। महिला बाल विकास विभाग ने 2022-23 में पूरक पोषण आहार में 73,06,088 रुपए 22 लाख बच्चों पर खर्च किए। वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में भी अलग से बजट के प्रावधान और करोड़ों खर्च के बाद भी हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। पोषण आहार को लेकर कैग रिपोर्ट में घोटाला उठ चुका है। अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, रीवा, सागर, सतना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में करीब 10 हजार टन पोषण आहार गायब होना पाया था। इन जिलों में कुल 97 हजार मीट्रिक टन पोषण आहार के स्टॉक की सूचना दी गई, लेकिन उसमें से 87 हजार मीट्रिक टन पोषण आहार का ही वितरण हुआ। करीब 62 करोड़ रुपए के बाकी 10 हजार टन पोषण आहार वितरण को लेकर संदेह की स्थिति रही। इसके भुगतान भी हो गए, लेकिन वितरण के प्रमाण नहीं मिले। इनमें अधिकतर पोषण आहार आदिवासी इलाकों में वितरित होना था, जो कि नहीं हुआ।

बेरोजगारों से लूट...अरबों की वसूली

मप्र में भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर मप्र की किरकिरी करा चुकी सरकारी एजेंसी व्यापमं (अब मप्र कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी) बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है। मप्र कर्मचारी चयन मंडल हर साल परीक्षाएं आयोजित कर रहा है और बेरोजगारों से अरबों रुपए की वसूली कर रहा है। परीक्षा हो या न हो लेकिन परीक्षा फीस वसूल कर ईएसबी अरबपति बन गया है। बेरोजगारों से हर परीक्षा का शुल्क वसूला जाता है। वर्तमान में मंडल के पास 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी है। इसके बाद भी बेरोजगारों को शुल्क से राहत नहीं दी जा रही है।

गौरतलब है कि मप्र में भर्ती घोटाले के बाद सुर्खियों में आए व्यापमं का नाम बदलकर सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया था। अब इसका नाम मप्र कर्मचारी चयन मंडल हो गया है। कर्मचारी चयन मंडल बेरोजगारों से शुल्क वसूलकर करोड़पति बन गया है। बेरोजगारों से हर परीक्षा का शुल्क वसूला जाता है। गौरतलब है कि मप्र के सभी विभागों में खाली पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा कराता है। इसके अलावा मंडल द्वारा प्रवेश परीक्षाएं भी ली जाती हैं। भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क वसूला जाता है। खास बात यह है कि मंडल परीक्षा कैलेंडर के पालन में भी पिछड़ा हुआ है। न तो समय पर रिजल्ट जारी हो रहे है और न ही परीक्षाओं का आयोजन समय पर हो पा रहा है। परीक्षा प्रणाली में तमाम सुधार के बाद भी पेपर आउट हो जाते हैं और परीक्षाओं में भी गड़बड़ी हो रही है।

गौरतलब है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी छात्राओं से 250 और अनारक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों से 500 रुपए परीक्षा शुल्क लिया जाता है। इस वजह से मप्र कर्मचारी चयन मंडल की आय लगातार बढ़ रही है, जबकि जिन छात्रों से परीक्षाओं के नाम पर शुल्क लिया जाता है, उनमें से 1 फीसदी से भी कम को नौकरी मिल पाती है। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं का शुल्क माफ नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में मंडल के पास 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी है। इसके बाद भी बेरोजगारों को शुल्क से राहत नहीं दी जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षा के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहां छात्र परीक्षा शुल्क माफ किए जाने की कई बार मांग उठा चुके हैं।

गौरतलब है कि व्यापमं घोटाला सामने आने के बाद मंडल की कार्यप्रणाली में कई बदलाव किए गए। पहले शीट पर गोले भरकर एग्जाम लिया जाता था। इस प्रक्रिया में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। इसके बाद महल की परीक्षाओं के सिस्टम को बदला गया है। अब इसकी सभी प्रकार की परीक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इससे आंसर शीट और प्रश्नपत्र के छपवाने का खर्च भी कम हुआ है। इसके बाद भी मंडल ने अपनी परीक्षाओं का शुल्क कम नहीं किया है। इससे मंडल की आय उसी तरह बढ़ रही है, जिस तरह प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मंडल की 8 भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं, जो प्रस्तावित तारीखों में नहीं हो पाईं। माध्यमिक शिक्षक (खेल, गायन वादन व नृत्य) तथा प्राथमिक शिक्षक (खेल, गायन वादन व नृत्य) चयन परीक्षा और माध्यमिक (विषय) शिक्षक चयन परीक्षा अगस्त में होना थी, जो नहीं हो पाई। समूह-4 के अंतर्गत सहायक वर्ग-3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा सितंबर में होनी थी। समूह-1 उपसमूह-3 मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित थी। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा भी अक्टूबर में होना थी। वहीं समूह-2 उपसमूह-3 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा और समूह-2 उपसमूह-4 सहायक सपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा नवंबर में व सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा दिसंबर में और वनरक्षक क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा अगले साल जनवरी में होना प्रस्तावित है, लेकिन अब ये परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाएंगी।

ईएसबी हर साल 10 से ज्यादा परीक्षाएं कराता है। इसमें करीब 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षार्थी साल में तीन से अधिक परीक्षाओं में भाग्य आजमाते हैं। हर बार परीक्षा शुल्क जमा करने के अलावा उन्हें दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते हैं। एक परीक्षा पर ऐसे विद्यार्थियों का औसत खर्च पांच हजार रुपया आंका गया है। कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक परीक्षा पर इतना खर्च वित्तीय दबाव बढ़ा देता है। बताया जा रहा है कि ईएसबी के पास 400 करोड़ रुपए बचत खाते में जमा हैं। इसके बाद भी परीक्षा शुल्क के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है।

● श्याम सिंह सिकरवार

छत्तीसगढ़ में निशुल्क हो चुकीं परीक्षा

वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में राज्य लोक सेवा आयोग और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सभी परीक्षाएं निशुल्क हो गई हैं। 2022 से पहले वहां सामान्य के लिए 500 और आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपए परीक्षा शुल्क लिया जाता था। अब वहां किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतिभागी को शुल्क नहीं देना होता। सरकार हर विभाग के खाली पदों को भरने में जुटी है। प्रदेश के सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती हैं। साल की शुरुआत में ही मंडल संभावित भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर देता है। इसके मुताबिक इस साल मंडल को 10 भर्ती परीक्षाएं करानी थीं। इनमें से मंडल अब तक सिर्फ दो भर्ती परीक्षाएं ही करा पाया है। 8 भर्ती परीक्षाओं की तो तारीख तक जारी नहीं हो पाई है। अब ये भर्ती परीक्षाएं अगले साल ही हो पाएंगी।

माननीयों में वर्चस्व की जंग

भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से आए नेताओं पर उठाए थे सवाल

भूपेंद्र सिंह ने गत दिवस मीडिया से चर्चा में कहा था कि कुछ लोग सागर में भाजपा को खत्म करने में लगे हैं। इसमें एक मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए थे। वे लोग अब हमारी पार्टी में आकर फिर से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। सिंह ने कहा- ये मामला सागर जिले का है, वहां दो लोगों को लेकर मेरी आपत्ति पहले भी थी और आज भी है। सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार इन्हीं दो लोगों ने किए हैं। ये कौन दो लोग हैं, इसकी जानकारी सभी को है। प्रशासन उनकी बात सुन रहा है जो कांग्रेस से आए हैं। प्रशासन को पता है कि कब किसकी सुनना है। प्रशासन जिनके इशारे पर काम कर रहा है, वे नहीं चाहते कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता मजबूत हों। वे तो कांग्रेस के लोगों को ही मजबूत कर रहे हैं।

सागर जिले में 8 विधायक हैं। इनमें से एक मंत्री व दो पूर्व मंत्री सहित तीन वरिष्ठ विधायक व दो पहली बार बने विधायक हैं। 7 भाजपा से व 1 कांग्रेस से हैं। जो कांग्रेस से हैं वे भाजपा की राह पर हैं, यानी सभी उसी दल से हैं जिसके मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके सालभर में जिले में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं आई है। लंबे समय से चल रही बीना, खुरई को जिला बनाने की मांग पूरी नहीं हुई है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू नहीं हुआ है। बीना विधानसभा से एकमात्र कांग्रेस से चुनकर भाजपा में आईं विधायक निर्मला सप्रे जिला बनवाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक यह घोषणा पूरी नहीं हुई है। विधायक सप्रे ने अपने स्तर पर हर तरह से प्रयास किए, घोषणा भी होने वाली थी लेकिन अटक गई। मुख्यमंत्री भी क्षेत्र के दौरे पर आए, उनसे क्षेत्र की जनता बड़ी उम्मीद भी कर रही थी, लेकिन विधायक कोई बड़ी घोषणा क्षेत्र के लिए नहीं करा पाई हैं। वहीं खुरई विधानसभा से विधायक व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से क्षेत्र की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। बीती सरकार में सिंह मुख्यमंत्री के बाद प्रमुख मंत्री थे, इसलिए जनता को बड़ी आशाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अब तक इन आशाओं व उम्मीदों के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। रोजगार देने वाले उद्योग धंधे आदि नहीं आए हैं। हालांकि अब तक पूर्व मंत्री सिंह ने ऐसी कोई मांग भी मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखी है।

चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से भाजपा में आए और विधायक बने बृजबिहारी पटैरिया के क्षेत्र देवरी में तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तक चरमराई हुई हैं। देवरी में एक बड़े स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल की तरह सेवाओं की जरूरत है लेकिन फिलहाल यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है। रात में गर्भवती महिलाओं को भी सागर जिला अस्पताल तक आना पड़ता है। गांवों की स्थिति तो और खराब है। उद्योग क्षेत्र नरयावली विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहां उद्योग लगवाने का दावा विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया करते रहे हैं। जनता को नए उद्योग लगवाने का भरोसा भी देते रहे ताकि बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके, इस पर सालभर बात भी खूब हुई। उद्योगों के कॉन्क्लेव भी हुए। निवेश के आंकड़े भी दिए, हालांकि यह अब तक जमीन पर नहीं आए हैं। बंडा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने वीरेंद्र सिंह लोधी ने प्राचार्य की अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई के लिए लिखा है। अब तक यह मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा है। बंडा नगर पालिका में भी बड़ी हेराफेरी की गई थी, इस मामले को विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था। बावजूद इसके बीते एक साल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। पहले से शुरू काम ही चल रहे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र में भी रूटीन काम हो रहे हैं या पिछली विधानसभा के दौरान स्वीकृत हुए कामों को कराया जा रहा है। बीती सरकार में प्रमुख मंत्री होने के नाते जनता बड़ी आशाएं लेकर चल रही है। अब तक कोई नया काम क्षेत्र में नहीं आया। वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री होने के नाते बड़े उद्योग की उम्मीद थी, वादे भी हुए, लेकिन अब तक यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। जिले की 8 विधानसभा में एक सुरखी विधायक प्रदेश शासन में मंत्री हैं। सरकार में अहम भूमिका में हैं बावजूद इसके बीते एक साल में मंत्री का क्षेत्र होने के बाद एक बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आती है। रूटीन काम सभी बेहतर हो रहे हैं, अफसर कर्मचारी काम कर रहे हैं। रीजनल कॉन्क्लेव में डाटा सेंटर के नाम पर बड़ा निवेश होने की उम्मीद भी बंधी है, लेकिन वह भी विवादित है। सागर शहर में मेडिकल कॉलेज है। यहां लंबे समय से सुपर स्पेशियलिटी सेंटर शुरू करने की जरूरत महसूस की जाती रही है। जनप्रतिनिधि इसके लिए आश्वासन भी देते रहे लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हो पाया है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन भी इसके लिए प्रयासरत हैं। कैंसर के इलाज के लिए भी यूनिट शुरू होना है। विधायक जैन राजघाट बांध की ऊंचाई बढ़वाने के लिए प्रयासरत रहे हैं।

कुलीनों के कुनबे में इस समय सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सागर जिले में दो नेताओं के वर्चस्व की जंग से पार्टी की साख पर दाग लग रहा है। पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह हाथ धोकर पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पूर्व मंत्री पर हमलावर हैं। दोनों कद्दावर नेताओं के बीच चल रहे शीतयुद्ध से पार्टी की साख गिर रही है। गौरतलब है कि सागर जिले के दो सीनियर विधायकों में इस समय कोल्ड वार चल रहा है। अनुशासन की सीमाओं को तोड़कर यह विवाद अब मीडिया में आ गया है। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला खुलकर जारी है। जिन दो नेताओं में कोल्ड वार चल रहा है उनमें एक हैं पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह और दूसरे हैं प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत। भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया था कि कुछ लोग सागर में भाजपा को खत्म करने में लगे हैं। इनमें एक मंत्री भी है। इस पर गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि एक व्यक्ति खुद को पार्टी से बड़ा समझ रहा है। शीर्ष नेतृत्व इसे देख रहा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

मप्र में कालेधन के कुबेरों की खुली पोटली

नेता-अफसर-बिल्डर की जुगलबंदी...!

लोकायुक्त, आयकर, ईडी और डीआरआई खंगाल रहे खेल

काली कमाई के और कितने कुबेर... मप्र में मची रेलमपेल

वर्ष 2024 की विदाई बेला में यानि दिसंबर महीने में लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापों ने कालेधन के कुबेरों की पोटली खोल दी है। प्रदेश में कुछ साल पहले तक जिसके सामने जीवन-यापन की समस्या थी, आज काली कमाई से वे कुबेर बन बैठे हैं। प्रदेश में काली कमाई किस हद तक हो रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आयकर, लोकायुक्त, ईडी और केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) नेता-अफसर-बिल्डर की जुगलबंदी खंगालने में जुट गई हैं।

● राजेंद्र आगाल

मप्र विकास की उड़ान भर रहा है। प्रदेश में विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार को हर माह औसतन 5 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि योजनाओं-परियोजनाओं के लिए आवंटित होने वाले फंड को सफेदपोशों, अफसरों और बिल्डरों की जुगलबंदी से लूटा जा रहा है। इसका खुलासा दिसंबर महीने में आयकर विभाग और लोकायुक्त के छापों में हुआ है। बिल्डरों के यहां मारे गए छापे में यह तथ्य सामने आया है कि किस तरह नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों की मिलीभगत से मप्र के संसाधनों का दोहन कर काली कमाई की जा रही है। वहीं लोकायुक्त के छापे में यह तथ्य सामने आया है कि एक अदने से सिपाही ने नेताओं और अफसरों के साथ मिलकर सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काली कमाई करके किस तरह अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है।

मप्र जहां एक ओर खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, वहीं दूसरी तरफ यह प्रदेश भ्रष्टों, माफिया और काली कमाई करने वालों के लिए चारागाह बना हुआ है। प्रदेश में जब-जब भी आयकर विभाग या लोकायुक्त-ईओडब्ल्यू के छापे पड़े हैं, धन कुबेरों की कलई खुली है। हर बार के छापे में एक तथ्य सामने आता है कि प्रदेश में काली कमाई का कारोबार नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत और संरक्षण से ही हो रहा है। हर बार काली कमाई के जादूगर सामने आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही होती है। इस बार राजधानी में परिवहन विभाग के एक पूर्व आरक्षक के यहां लोकायुक्त के छापों में अभी तक जो अकूत संपत्ति सामने आई है, उससे सभी की आंखें चौंधिया गई हैं। कांग्रेस तो हमलावर हो गई है और कह रही है कि अगर एक आरक्षक इतनी कमाई कर सकता है तो अधिकारियों और मंत्रियों-नेताओं की कमाई तो अपरंपार होगी। आयकर विभाग और लोकायुक्त ने छापों में जो डायरी, हार्डडिस्क और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं, उससे काली कमाई के सौदागरों की हकीकत सामने आ सकती है। बताया जा रहा है कि बिल्डरों ने अपने कारोबार में कई नेताओं और अधिकारियों की काली कमाई को लगाया है। सौरभ शर्मा के कई नेताओं से संबंध रहे हैं। उसके यहां मिली डायरी और मोबाइल में ऐसे-ऐसे लोगों के नाम मिल जाएंगे, जिससे लोगों के होश उड़ जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग से होने वाली काली कमाई की बंदरबाट सौरभ शर्मा ही भोपाल से दिल्ली तक करता था।

सौरभ शर्मा के यहां जो संपत्ति पकड़ाई है, वह न तो किसी सरकारी खरीदी और न ही टेंडर में घपला कर कमाई गई है। उस संपत्ति के आने के स्रोत का भी पुख्ता प्रमाण जांच एजेंसियों के पास नहीं है। यही नहीं आयकर विभाग ने 10 करोड़ रुपए और 52 किलो सोने वाली कार को भी दूसरी जगह से जप्त किया है। ऐसे में सौरभ शर्मा आसानी से बच सकता है। सूत्र बताते हैं कि सौरभ शर्मा के ठिकानों से जो नगद और सोने-चांदी मिले हैं, उसको वह दुबई के एक ज्वैलर्स का बताने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े हंगामे के बाद क्या सौरभ शर्मा की काली कमाई का टोह जांच एजेंसियां लगा पाएंगी।

बिल्डर्स, आईएएस और कारोबारी का कनेक्शन

त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, ईशान और क्वालिटी ग्रुप के खिलाफ छापे की कार्रवाई के बाद आयकर विभाग अब इनके यहां से जब्त किए दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है। इन दस्तावेजों की पड़ताल के साथ मोबाइल और अन्य लिंक के आधार पर भी टैक्स चोरी से संबंधित नामों की लिंक निकाली जा रही है। विभाग का मानना है कि, 50 करोड़ के कुल टर्नओवर वाले इस छापे में 10 गुना तक टैक्स चोरी सामने आ सकती है। यह बात भी सामने आई है कि 52 ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी अंतिम दौर में 56 ठिकानों तक पहुंच गई थी। भोपाल में इन तीन बिल्डर्स और उनके सहयोगियों के यहां हुई आयकर छापेमारी में रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका की संलिप्तता उजागर हुई है। साथ ही, महेंद्र गोयनका के मप्र और छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारियों के साथ संबंधों का भी खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान ग्वालियर में पदस्थ एक आईएएस अधिकारी से महेंद्र गोयनका के करीबी संबंधों के सबूत मिले हैं। वहीं, त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा और छापे के जद में आए बिल्डर्स के मामले में यह तथ्य सामने आया है कि इनकी कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है, लेकिन टैक्स चोरी इससे दस गुना अधिक होने की आशंका जताई जा रही है।

त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के मामले में आयकर छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि राजेश शर्मा एंड कंपनी द्वारा राजधानी के होशंगाबाद रोड पर स्थित सहारा सिटी की 110 एकड़ जमीन की खरीदी की गई है। इस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि राजेश शर्मा रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका के लाइजनर के रूप में भी काम कर रहा है और उसकी कंपनियों में सहयोगियों के साथ मिलकर 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। भोपाल के 49 ठिकानों और इंदौर के दो ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद अब त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक राजेश शर्मा और इसके सहयोगियों के कारनामों की परतें खुलने लगी हैं। आयकर विभाग की जांच

डमी कर्मचारियों के नाम पर काली कमाई खपाई

आयकर विभाग द्वारा छापे से संबंधित बिल्डर्स, प्रमोटर्स और कंपनियों के मालिकों व इनके परिजनों के साथ अब इनके यहां काम करने वालों को भी नोटिस जारी कर तलब किया जाएगा। सबसे पहले त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा के ड्राइवर, अकाउंटेंट व अन्य कर्मचारियों को नोटिस देकर उनसे आय के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसी तरह अन्य बिल्डर्स के मामले में भी कार्रवाई होगी। उधर छापे के दौरान चड्डी-बनियान में घर से भागने वाले राजेश शर्मा के डमी कर्मचारी विश्वनाथ साहू के बारे में आयकर विभाग को जानकारी मिल गई है। पता चला है कि उसकी टांग टूट गई है और वह अस्पताल में एडमिट है। आयकर छापे में जो जानकारियां सामने आई हैं। उसमें सूरजनगर के समीप बनाए जा रहे सेंट्रल पार्क को लेकर भी अफसरों की निगाहें हैं। यहां ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के इन्वेस्टमेंट हैं। खास बात यह है कि ग्रीन बेल्ट एरिया होने के बाद भी यहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बताया गया कि सेंट्रल पार्क का मालिक प्रदीप अग्रवाल ही अकेले करीब एक एकड़ में कंस्ट्रक्शन करा रहा है। इसे किस आधार पर परमिशन दी गई है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। आयकर अधिकारियों ने महाराष्ट्र के भुसावल से राजेश शर्मा के डमी कर्मचारी सतीश चौधरी को उठाकर उससे पूरे मामले में बयान ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि चौधरी ने बयान में कहा है कि वह कुछ नहीं जानता, राजेश शर्मा उससे जहां साइन कराते थे वह कर देता था। दूसरी ओर यह पता चला है कि चौधरी निसर्ग और अन्य प्रोजेक्ट में राजेश शर्मा के नाम पर ऑथराइज्ड सिग्नेचर के रूप में काम कर रहा था।

सौरभ सिर्फ मोहरा, असली मास्टरमाइंड्स कोई और

मेंडोरी में इनोवा कार से 52 किलो सोने और 11 करोड़ रुपए कैश जब्ती के मामले में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में आयकर विभाग ने लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके बाद, सौरभ शर्मा अब भारत आने पर सीधे आयकर अधिकारियों के शिकंजे में आ सकेगा और बिना आयकर विभाग की पूछताछ के देश से बाहर नहीं जा सकेगा। वहीं इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि सौरभ शर्मा सिर्फ मोहरा है। असली गुनाहगार और मास्टरमाइंड्स तो कोई और है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ही होने की पुष्टि के बाद आयकर विभाग ने दो दिन पहले लुक आउट सर्कुलर जारी करने का फैसला लिया था। इसके लिए डीआरआई को पत्र भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। दो दिनों में आयकर अधिकारियों ने यह प्रक्रिया पूरी की और अब सौरभ शर्मा से पूछताछ संबंधी कार्रवाई के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सौरभ शर्मा लोकायुक्त द्वारा उसके घर पर छापेमारी के बाद से दुबई में है और अब वह लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग दोनों के जांच के दायरे में आ गया है, दोनों एजेंसियों को उसकी तलाश है। आयकर विभाग की जांच टीम अब जब्त किए गए गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। विभाग यह जांच कर रहा है कि इस 52 किलो सोने की आपूर्ति कहां से हुई और यह किसने तैयार किया। इस मामले में गोल्ड व्यापार से जुड़े कुछ व्यापारियों को तलब किया गया है, ताकि यह पता चल सके कि ऐसे गोल्ड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा सके।

में यह सामने आया है कि राजधानी में अलग-अलग स्थानों पर करोड़ों के प्रोजेक्ट लगाने के साथ राजेश शर्मा और उसके सहयोगी टीम के साथियों ने सहारा एस्टेट की 110 एकड़ लैंड की खरीदी की है। इसके साथ ही आयकर अफसरों को भारी संख्या में बेनामी रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। जिनके मामले में एक-एक बिंदु पर जांच की जा रही है। आयकर की पड़ताल में राजेश शर्मा के तार रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका से जुड़े होने का पता चला है। इसके बाद भोपाल, इंदौर के अलावा राजेश शर्मा एंड टीम के रायपुर, जबलपुर, कटनी समेत अन्य शहरों में भी भारी इन्वेस्ट करने के खुलासे हो सकते हैं। आयकर सूत्रों के अनुसार गोयनका की कंपनियों में शर्मा और उसके सहयोगियों द्वारा 400 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्ट किए जाने के दस्तावेज सामने आ चुके हैं। इसमें बेनामी कंपनियों में खासा लेन-देन होने की भी बात सामने आई है। जिसकी जांच की जा रही है।

सीएम राइज स्कूल का भी ठेका

खनन और कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े राजेश शर्मा एक पूर्व मुख्य सचिव के करीबी माने जाते हैं। राजेश शर्मा त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक होने के साथ ही भोपाल में क्रशर संचालकों के संगठन का नेतृत्व भी करते हैं। वे राजधानी और आसपास के इलाकों में खदानों के ठेके और क्रशर संचालन का काम भी करते रहे हैं। राजेश शर्मा की सत्तापक्ष के कई नेताओं से दोस्ती है। इसके चलते ही उन्हें सीएम राइज स्कूलों के कंस्ट्रक्शन का भी काम मिला है। रायसेन का सीएम राइज स्कूल इनकी कंपनी ही बना रही है। शर्मा भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे रामपाल सिंह के करीबी बताए जाते हैं। भोपाल में दीपक भावसार, विनोद अग्रवाल, रूपम शिवानी के यहां भी आईटी के छापे पड़े हैं। ये सभी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों पर आयकर विभाग के छापे पर मप्र विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि मैंने इस बात को सदन के पटल पर रखा। स्पीकर से कहा कि आपसे 9 महीने से आग्रह कर रहा था, बार-बार कह रहा था कि यहां भ्रष्टाचार है। रिटायर हो चुके पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। अरबों-करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की। न जाने क्यों संरक्षण दिया जा रहा था। आज आईटी ने रेड मारी है और अगर बिना दबाव के जांच हो जाती है, तो बड़ा घोटाला निकलकर

ईओडब्ल्यू ने सौरभ को दे दी थी क्लीनचिट

परिवहन विभाग की काली कमाई से धनकुबेर बने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह के अब भी कई राज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि लोकायुक्त पुलिस, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों के पास महीनों से सौरभ शर्मा की लिखित शिकायत पहुंच रही थी। यह 500 करोड़ से अधिक बेनामी संपत्ति से जुड़ी है। लोकायुक्त संगठन के सूत्र बता रहे हैं कि सौरभ के खिलाफ पिछले सालभर में ही 50 से अधिक शिकायतें जांच एजेंसियों के पास पहुंचीं। इन सभी में बैरियर के कलेक्शन, देसी हवाला, अफसरों को घूंस के साथ कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। सूत्रों का कहना है कि ये शिकायतें आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास भी पहुंची थी। एक साल पहले जांच के बाद उसे क्लीनचिट दे दी गई। समिति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लिखा गया कि रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोयासटी को पत्र भेजकर जांच कराई जा सकती है। जिस केके गोगिया के नाम पर सौरभ ने अरेरा कॉलोनी में मकान खरीदा, एजेंसी को उससे भी संबंध नहीं मिले। परिवहन विभाग ने बैरियर से वसूली की कोई जानकारी नहीं दी। सौरभ के सहयोगी के रूप में शरद जायसवाल की जगह आकाश कुमार पटेल का नाम मिला। शिकायकर्ता राजाराम का पता भी जांच एजेंसी को सही मिला। ऐसे में अब छापे के बाद इस क्लीनचिट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में जो कागजात मिले हैं, उनमें इंद्रा सागर डेम का टेंडर दिव्या और सौरभ के सहयोगी चेतन के नाम पर है। इंदौर में तीन घर हैं। ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या और चेतन के नाम पर है। पुत्र अभिरल के नाम लाखों रुपए की एफडी मिली है। सूखी सेवनिया भोपाल में मां उमा शर्मा और चेतन के नाम पर वेयर हाउस और कोलार में एक बड़ा स्कूल है। दुबई में 150 करोड़ रुपए का विला एमआर ग्रुप बिल्डर से खरीदा गया है। भोपाल के मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी, 11 नंबर बस स्टॉप एवं प्रधान मंडपम में चार बंगले, अरेरा कॉलोनी का आवास 4.60 करोड़ रुपए का बताया गया। पहले अरेरा कॉलोनी के आवास को केके गोगिया के नाम पर खरीदा गया। गोगिया कौन है, जांच जारी है। होशंगाबाद रोड और औबेदुल्लागंज रोड पर तीन पेट्रोल पंप भी सौरभ ने खरीद रखे हैं। भोपाल में निर्माणाधीन स्कूल पर मोटी रकम खर्च की गई है। इंदौर के विजयनगर के पास होटल है। रेंज रोवर व मर्सिडीज गाड़ी अन्य व्यक्तियों के नाम पर खरीदी गईं। सौरभ के कथित सहायक शरद जायसवाल के लिए ई-8 में 3.30 करोड़ का मकान है। बंसल हॉस्पिटल के पास शाहपुरा में फजीटो नाम का रेस्टोरेंट भी है।

सामने आएगा। इन बिल्डरों को नेताओं का संरक्षण है, मैं इनके नाम भी जानता हूं। इन बिल्डरों की जहां जमीनें हैं, वहां ग्रीन बेल्ट कम कर दिए गए। गलत तरीके से नक्शे बदले गए, मेरे पास इसके प्रमाण भी हैं।

कॉन्स्टेबल मंत्री-अफसरों का चहेता

लोकायुक्त और इनकम टैक्स ने पूर्व ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से 3 करोड़ कैश और 2 करोड़ कीमत की 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवर और 50 लाख का सोना बरामद किया है। सौरभ इस समय दुबई में है। जब एक मामूली से परिवहन कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के पूरे करियर की पड़ताल की तो पता चला कि नौकरी लगने से लेकर उसके इस्तीफा होने तक की पूरी स्टोरी में सरकार की बड़ी कृपा रही है। कहने को वह एक कॉन्स्टेबल था, लेकिन मंत्री और अफसरों का सबसे चहेता था। उसके पास मप्र के आधे परिवहन चेक पोस्ट की जिम्मेदारी थी। इन चेकपोस्ट में आने वाले पूरे कैश को वो खुद डील करता था। चेकपोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर और दूसरे अफसरों का शेयर वो खुद तय करता था। उसके काम में कोई अफसर और इंस्पेक्टर दखल नहीं देता था। सीनियर अफसरों का कहना है कि सौरभ ने सरकारी चेकपोस्ट का निजीकरण कर दिया था। चेकपोस्ट को उसने ठेके पर दे दिया था। हर चेकपोस्ट से हर दिन की निर्धारित रकम तय थी। चेकपोस्ट से वह खुद ये पैसे ले जाता था। 1 जुलाई 2024 से पहले मप्र में कुल 47 परिवहन चेकपोस्ट थे, इसमें से 23 को सौरभ संभालता था।

मार्च 2020 में जब मप्र में कमलनाथ सरकार का तख्तापलट हुआ और शिवराज सरकार की वापसी हुई, तो मंत्रालय में भी फेरबदल हुए। एक सीनियर अधिकारी कहते हैं कि जुलाई 2020 में चेकपोस्ट पर नई व्यवस्था बनने लगी। इसमें अधिकारियों को भरोसे में नहीं लिया गया। कॉन्स्टेबल सौरभ का दखल सीधे हाई लेवल पर हो गया। वह सरकार के एजेंट के तौर पर अफसरों को दरकिनार कर मनमाफिक व्यवस्था बनाने लगा। उसने चेकपोस्ट को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। इसके बाद चेकपोस्ट के कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए मनमाफिक वसूली करने लगे। इसके बाद ही चेकपोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतें बढ़ीं। 2022 आते-आते उसकी शिकायतें जांच एजेंसियों तक पहुंचने लगीं। परिवहन चेक पोस्ट से पैसा लेकर सौरभ ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता था। परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये रकम चेकपोस्ट से लेकर उसे व्यवस्थित ठिकानों तक खुद सौरभ पहुंचाता था। यही वजह है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों का उस पर नियंत्रण नहीं था। सूत्रों का यह भी कहना है कि

अफसरों-कारोबारियों की साठगांठ की खुलेंगी परतें

मप्र में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी तीन कंपनियों पर आयकर की छापेमारी में अफसरों और कारोबारियों के काले कारोबार की परतें खुलने वाली हैं। दरअसल, त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के कॉल डिटेल्स (सीडीआर) आयकर विभाग को मिल चुकी है। आयकर विभाग इसकी पड़ताल में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि इसकी पड़ताल से चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों पर आयकर की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग ने दस्तावेजों में एंट्री की है कि चंदनपुरा में 54 एकड़ जमीन खरीदने के लिए रायपुर के खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका ने बिल्डर राजेश शर्मा को 45 करोड़ रुपए कैश दिया था। यह जमीन तीन अलग-अलग कंपनियों के जरिए खरीदी गई। राजेश शर्मा के घर से मिले दस्तावेजों में यूरो पायलेट प्रालि नामक कंपनी सामने आई, जो गोयनका की बताई जा रही है। जमीन का सौदा 65 करोड़ रुपए में हुआ था। बाद में कीमत 110 करोड़ हो गई। भुगतान तीन किश्तों में 25 करोड़, 55 करोड़ और 30 करोड़ रुपए के रूप में हुआ। जानकारी के अनुसार त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के कॉल डिटेल्स (सीडीआर) आयकर विभाग को मिल चुकी है। इससे पहले महेंद्र गोयनका की डायरी से भी कई क्लू मिले हैं। सूत्रों की मानें तो राजेश शर्मा के यहां से मिले मोबाइल फोन की सीडीआर का दस महीने का डेटा निकाल लिया है। जिसमें उसने कई अफसरों से सीधे बातचीत की। इनमें लगातार टू वे कम्युनिकेशन करने वाले की सूची बन रही है।

2016 से 2023 तक सरकार और मंत्री जरूर बदलते रहे, लेकिन हर सरकार और हर परिवहन मंत्री के बंगले में सौरभ का बेरोकटोक आना जाना था। जब इस संबंध में शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे और वर्तमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से पूछा गया तो जवाब मिला कि वे सौरभ शर्मा को नहीं जानते। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि राजनीतिक जीवन में कई लोग आते-जाते हैं, मुलाकात करते हैं। हर मुलाकात करने वाले से आपके नजदीकी संबंध नहीं होते। परिवहन विभाग में भी सैकड़ों कॉन्स्टेबल होते हैं, वो मिलते रहते हैं।

लोकायुक्त के छापे पर सवाल

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां लोकायुक्त के छापों पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सौरभ सरकारी सेवा में नहीं था। ऐसे में उस पर लोकायुक्त की जगह ईओडब्ल्यू को छापामार कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर भोपाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके वकील ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लोकायुक्त की कार्रवाई को गलत बताया है। एडवोकेट राकेश पाराशर के मुताबिक, सौरभ लोकसेवक नहीं है। इसके बाद भी लोकायुक्त ने उसके घर छापा मारा। यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। हालांकि न्यायाधीश ने अपने आदेश में उसे लोक सेवक मानते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

जानकारों का कहना है कि लोकायुक्त ने

अपनी यह कार्रवाई बिना प्लान और बिना परमिशन के की है। जिस समय लोकायुक्त ने छापा मारा उस समय एसपी भी छुट्टी पर थे। लोकायुक्त के छापे के बाद ईडी की कार्रवाई में जो अतिरिक्त कमाई का खुलासा हुआ है, उससे सरकार की भी थू-थू हो रही है। सब कह रहे हैं कि आखिर लोकायुक्त ने कैसे छापा मारा कि ईडी को बड़ी संपत्ति मिली। सौरभ शर्मा और उसके साथियों की काली कमाई से जांच एजेंसियां भी चकित हैं। लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी ने कहा कि सौरभ और उसके सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी के दौरान करीब 33 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। केंद्र की इस एजेंसी ने इस मामले में 27 दिसंबर को राज्य परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा, उनके सहयोगी चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल समेत रिश्तेदार रोहित तिवारी सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राज्य की राजधानी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में करीब 8 परिसरों में छापेमारी की थी। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये लोग या तो अपराध की आय के संदिग्ध लाभार्थी थे या कथित तौर पर उसके मनी लॉन्ड्रिंग में सहायक थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मप्र सरकार की लोकायुक्त पुलिस की ओर से सौरभ शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधित फर्म और कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है, जो आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक है। संघीय एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान बैंक खातों और संपत्तियों के विवरण की पहचान की गई और विश्लेषण में पाया गया कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और उन कंपनियों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी हैं, जिनमें उनके करीबी सहयोगी निदेशक थे। चेतन सिंह गौड़ के नाम पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति मिली और सौरभ शर्मा के परिवार

के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक जमा राशि पाई गई। ईडी ने दावा किया कि सौरभ शर्मा की तमाम कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों से संबंधित कुछ दस्तावेज अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ मिले हैं। एजेंसी ने कहा कि सौरभ शर्मा ने ये संपत्तियां कथित तौर पर राज्य परिवहन विभाग में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने के दौरान भ्रष्ट तरीके से अर्जित अवैध पैसे से खरीदी थीं। इससे पहले आयकर विभाग ने कुछ समय पहले सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह गौर के वाहन से 52 किलोग्राम सोने की छड़ें और 11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। वहीं, लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी में सौरभ के ठिकानों से 234 किलो चांदी सहित 7.98 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की थी।

दिल्ली तक पहुंची छापे की गूंज

मप्र में लोकायुक्त की इस कार्रवाई की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी हो रही है। वहीं नैटग्रिड यानि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने भी इस मामले पर काम करना शुरू कर दिया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। नैटग्रिड कोर सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है। नैटग्रिड की परिकल्पना 2009 में की गई थी। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम के दिमाग की उपज कहा जाता है। उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के बाद इस विचार की परिकल्पना की थी। सूत्र बताते हैं कि नैटग्रिड अब आंकड़ों के आधार पर लोकायुक्त के छापे की तहकीकात कर रहा है। दूसरी ओर, केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भोपाल में मेंडोरी के जंगल में कार से गोल्ड-कैश मिलने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस गोल्ड के विदेश से आयात किए जाने की आशंका के मद्देनजर डीआरआई आयकर विभाग के पैरेलल जांच करेगा। इस संबंध में निदेशालय के अधिकारी एक होटल और स्कूल से जुड़े निवेश की भी जांच कर रहे हैं। 19 दिसंबर को लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापों में सौरभ शर्मा के ठिकानों से 235 किलो चांदी सहित कुल 8 करोड़ की नकदी और आभूषण मिले हैं। वहीं, आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में 19 दिसंबर की देर रात एक कार से 52 किलो सोना मिला और 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। कार का मालिक चेतन सिंह गौर सौरभ का करीबी है।

सौरभ शर्मा कैसे बना धनपति, पड़ताल में जुटी कई एजेंसियां

मप्र में परिवहन विभाग ऐसा है जिसमें हमेशा ही कमाऊ पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है। विभाग का बड़ा अधिकारी हो या विभागीय मंत्री कमाऊ पुत्र का ओहदा नहीं उसकी बाजीगिरी को देखते हैं। यही कारण है कि इस विभाग में अदना सा कर्मी भी बड़े-बड़े अफसरों पर भारी पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा है। सेवा में रहते और रिटायरमेंट के बाद भी वह परिवहन विभाग का नाक-कान बना रहा। परिवहन विभाग के पूर्व कर्मी सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। इस बीच सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने समन जारी किया है। साथ ही उसकी पत्नी, मां, दोस्त शरद जायसवाल और चेतन सिंह को भी समन जारी किया गया है। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। सौरभ शर्मा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी भी चलाता था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कार्यालय ग्वालियर में 22 नवंबर 2021 को पंजीकृत कंपनी अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में सौरभ के दोस्त शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर और रोहित तिवारी डायरेक्टर हैं। 25 जून 2024 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10 लाख रुपए दर्शाई गई है, जबकि चुकता पूंजी एक लाख रुपए बताई गई है। कंपनी का काम सिविल इंजीनियरिंग अर्थात् निर्माण कार्य बताया गया है। कंपनी की अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद अंतिम बार बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को दाखिल की गई थी। सौरभ शर्मा के घर और उसके दोस्त चेतन गौर की कार से करोड़ों की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण मिलने के मामले में लोकायुक्त और आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब सौरभ और चेतन के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भोपाल में मेंडोरा के जंगल में कार से गोल्ड-कैश मिलने के मामले की जांच शुरू कर दी है।

कौन बनेगा दिल्ली का सिकंदर?

नई दिल्ली सीट पर तीन दशक से एक ट्रेंड चल रहा है। इस सीट से हारने वाले नेता का सियासी मुकद्दर खराब हो जाता है, वहीं जीतने वाला सिकंदर बन जाता है और मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठता है। नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने तीन-तीन बार जीत हासिल की और साथ ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने।

अंग्रेजों के समय में बसाई गई लुटियंस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को अपने में समेटे हुए हैं। इस इलाके की सियासी चमक अंग्रेजों के समय से अभी तक कायम है। नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली की सियासत ही नहीं बल्कि सत्ता की दशा और दिशा तय करती है। नई दिल्ली सीट पर जिस भी पार्टी और नेता ने जीत दर्ज की, वहीं दिल्ली की सत्ता का सिकंदर रहा। इस सीट से हारने वाले नेता का सियासी मुकद्दर खराब हो जाता है। नई दिल्ली सीट पर तीन दशक से यही ट्रेंड चला आ रहा है।

नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित इसी नई दिल्ली सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। वो तीन बार इस सीट से विधायक रही हैं, लेकिन 2013 में अरविंद केजरीवाल से हार गई थी। संदीप दीक्षित अपनी मां की राजनीतिक विरासत को पाने और अपनी मां की हार का हिसाब बराबर करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ उतरे हैं। दिल्ली में विधानसभा का गठन 1993 में हुआ है, उसके बाद से राजधानी में सात बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 2008 से पहले तक गोल मार्केट सीट के तहत आता था। 2008 में परिसीमन के बाद से यह सीट नई दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इस तरह दिल्ली में सात बार विधानसभा चुनाव हुए और जो पार्टी नई दिल्ली सीट जीतने में कामयाब रही, उसी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है। सात चुनाव में तीन-तीन बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एक बार भाजपा ने जीत हासिल की, जिस पार्टी ने गोल मार्केट और नई दिल्ली सीट जीती, उसकी ही सरकार बनी है।

1993 में नई दिल्ली सीट भाजपा ने जीती और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद 1998, 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट जीती और तीनों ही बार कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही। इसी तरह से 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी ने जीती और तीन बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। नई दिल्ली सीट जीतने वाली पार्टी की सिर्फ सरकार ही नहीं बनती बल्कि सत्ता के सिंहासन पर उसी का कब्जा होता है। पिछले सात चुनाव में छह बार नई दिल्ली सीट जीतने वाले नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। 1993 में नई दिल्ली सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। इस चुनाव में भाजपा के टिकट पर कीर्ति आजाद विधायक चुने गए थे, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद नई दिल्ली सीट पर 1998 से लेकर 2008 तक लगातार तीन बार शीला दीक्षित ने जीत दर्ज की और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी सफर का आगाज नई दिल्ली विधानसभा सीट से किया। 2013 से लेकर 2020 तक लगातार तीन बार केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक बने और तीनों ही बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस तरह अब तक जो भी राजनीतिक दल नई दिल्ली सीट पर काबिज हुआ, वही दिल्ली की सत्ता का सिकंदर बना।

नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीतने वाले विधायक सिकंदर बने तो हारने वाले प्रत्याशी का राजनीतिक मुकद्दर खराब हो गया। 1993 के चुनाव में भाजपा से कीर्ति आजाद विधायक बने और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले बृजमोहन भामा हारने के साथ ही सियासी बियाबान में चले गए। इसके बाद 1998 चुनाव में नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित विधायक बनीं और भाजपा प्रत्याशी कीर्ति आजाद को हार झेलनी पड़ी। 2003 में कीर्ति आजाद की जगह उनकी पत्नी पूनम आजाद भाजपा से शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन उसके बाद से सियासी हाशिए पर चली गईं। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शीला दीक्षित के खिलाफ भाजपा से विजय जौली चुनाव लड़े। जौली दिल्ली के भाजपा के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन नई दिल्ली सीट से चुनाव हारने के बाद से दोबारा से उभर नहीं सके। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस की शीला दीक्षित को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसी शिकस्त दी कि दोबारा से उभर ही नहीं सकी। शीला दीक्षित ने अपनी सीट के साथ-साथ सत्ता भी गंवा दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा से 2015 के चुनाव में नुपुर शर्मा मैदान में उतरीं, लेकिन जीत नहीं सकीं। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ भाजपा से सुनील यादव मैदान में उतरे, लेकिन वो जीत नहीं सके। नुपुर शर्मा को भाजपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो सुनील यादव गुमनाम हैं।

● **रजनीकांत पारे**

केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित

नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार जीत का चौका लगाने के लिए उतर सकते हैं। 2020 में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 46226 वोट मिले थे तो भाजपा के सुनील यादव को 21697 वोटों से शिकस्त दी थी। इस सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी रोमेश सभरवाल रहे और उन्हें महज 3206 वोट मिले थे। इस बार केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, लेकिन भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और शीला दीक्षित के बेटे हैं। इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो सबसे ज्यादा आक्रामक रहने वाले कांग्रेसी नेता हैं। इसके चलते मुकाबला रोचक हो गया है, लेकिन देखना है कि कैसे केजरीवाल अपनी सियासी नैया पार लगाते हैं?

नसीहत पर गौर करें

इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस जिस तरह अडानी-ईवीएम को मुद्दा बनाकर सड़क से संसद तक हल्ला मचाए हुए है, उससे गठबंधन के अन्य दल सहमत नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वह आमजन से जुड़े मुद्दे लेकर आए।

इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस से अलगाव का रुझान और आगे बढ़ा है। अब नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन का नेता बने रहना चाहती है, तो उसे यह स्थान मेहनत से कमाना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने ईवीएम में हेरफेर को लेकर रोने की प्रवृत्ति से कांग्रेस को बाहर आने की सलाह भी दी और कहा कि उसे चुनाव नतीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसके पहले गठबंधन के नेता के रूप में कांग्रेस या राहुल गांधी की हैसियत को ममता बनर्जी, शरद पवार और लालू प्रसाद यादव से प्रत्यक्ष एवं शिवसेना (उद्धव) और डीएमके से परोक्ष चुनौती मिल चुकी है।

मुमकिन है कि इस प्रवृत्ति के पीछे प्रमुख कारण अडानी ग्रुप के खिलाफ राहुल गांधी के लगातार हमले और उनकी कुछ दूसरी नीतियां रही हों। इसके बावजूद वह वक्त अब निर्णायक मोड़ पर है, जब पार्टी को बन रहीं विपरीत परिस्थितियों पर गहन विचार-विमर्श करना चाहिए। यह तथ्य है कि कांग्रेस गठबंधन के अघोषित नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई। लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक अच्छे नतीजों के बाद तो वह जननायक परिघटना का ऐसे शिकार हुई कि उसे लगा अब राहुल गांधी की लहर चल रही है। इसका असर हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के दौरान उसके हठी रुख में नजर आया। संसद में किस मुद्दे को कितनी तरजीह देनी है, इस पर गठबंधन में आम सहमति बनाने की कोशिश के बजाय खुद मुद्दे तय कर लेने का उसका रुख भी इसी परिघटना से प्रभावित लगा है। राहुल गांधी ने बिना आज की सियासी हकीकतों को समझे जातीय पहचान की राजनीति को जिस तरह अपने एजेंडे में प्रमुखता दी है, उसका उलटा असर चुनावों के साथ-साथ संभवत: अन्य दलों के साथ कांग्रेस के रिश्तों पर भी हुआ है। फिर चुनावी राजनीति में रहते हुए खुद को इसके ऊपर दिखाने की कोशिश कभी कारगर नहीं होती। इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि कांग्रेस वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक समीकरणों के प्रति बेहतर समझ बनाए और उसके अनुरूप अपना रुख तय करे। वरना, नरेंद्र मोदी विरोधी विपक्षी एकता की जो संभावना बनी थी, वह बिखर जाएगी।

संसद का शीतकालीन सत्र कई मायने में बहुत दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम वाला रहा है। इस सत्र में जो विधायी कामकाज हुए या दोनों सदनों में संविधान पर जो चर्चा हुई वह अपनी जगह है लेकिन जो राजनीति हुई वह ज्यादा दिलचस्प रही। यह पहली बार हुआ कि पूरे सत्र में कांग्रेस सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष की पार्टियों के निशाने पर भी रही। कांग्रेस को अलग-थलग करने का प्रयास भाजपा की ओर से हो रहा था तो साथ-साथ विपक्षी गठबंधन की पार्टियों की ओर से भी हो रहा था। यह प्रयास इतना व्यवस्थित था कि शुरू में तो कांग्रेस भी नहीं भांप सकी कि जो हो रहा है वह एक डिजाइन की तहत हो रहा है। लेकिन फिर कांग्रेस को समझ में आया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक महीने के सत्र में वह अपना एक भी एजेंडा सदन में ठीक से नहीं उठा सकी। सरकार से ज्यादा विपक्ष की पार्टियों ने कांग्रेस के एजेंडे को पंचर किया।

कांग्रेस का इस सत्र में सबसे बड़ा एजेंडा अडानी का था। सत्र से ठीक पहले अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी और सागर अडानी सहित आठ लोगों के खिलाफ फ्रॉड और घूसखोरी के आरोप लगे थे और वारंट जारी होने की खबर आई थी। इस लिहाज से यह विपक्ष के लिए बड़ा मौका था कि वह केंद्र सरकार को क्रोनी कैपिटलिज्म पर घेरे। कांग्रेस ने यही किया। उसने संसद ठप्प किया और संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। लेकिन दो दिन के बाद ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने को कांग्रेस के प्रदर्शन से अलग कर लिया। इतना ही नहीं तृणमूल कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि वह अडानी के मसले पर संसद

विपक्षी गठबंधन आगे कैसा?

अगर संसद के शीतकालीन सत्र में पहले तीन हफ्ते की कार्यवाही की रोशनी में विपक्षी राजनीति को देखें तो यह सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे नेता नहीं होते हैं और ममता बनर्जी को कमान मिलती है तो विपक्षी राजनीति का स्वरूप कैसा होगा? क्या ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन को एक रखते हुए उसे भाजपा के खिलाफ ज्यादा प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए तैयार कर पाएंगी? यह बड़ा सवाल है क्योंकि एक तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वे पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ेंगी और वहीं रहकर विपक्षी गठबंधन का संचालन करेंगी। कोलकाता से कैसे राष्ट्रीय गठबंधन का संचालन होगा, यह समझना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि वे डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की पोजिशनिंग कर रही हैं। वे अपने को राष्ट्रीय नेता और कोलकाता को शक्ति पीठ दिखाना चाहती हैं ताकि बांग्ला मानुष में गर्व की भावना भर सकें और अगला चुनाव जीत सकें। यही राजनीति पिछले साल तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने की थी। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया था और अपने को राष्ट्रीय नेता बताना शुरू किया था लेकिन वे चुनाव में पिट गए थे। अब ममता बनर्जी वही राजनीति कर रही हैं। उनका मकसद किसी तरह से 2026 का विधानसभा चुनाव जीतना है। उनको पता है कि अगला चुनाव बहुत मुश्किल होगा। लगातार 15 साल के राज की एंटी इन्कम्बैंसी को किसी बड़े गेमप्लान से ही काउंटर किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक राज्य की पार्टी है। उन्होंने अनेक राज्यों में पैर फैलाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसलिए बाकी प्रादेशिक पार्टियों के लिए भी उनका नेतृत्व स्वीकार करना मुश्किल होगा। कहने को सभी पार्टियां तैयार हो जाएंगी कि वे विपक्षी गठबंधन की नेता बनें लेकिन वे कोई सामूहिक फैसला सभी पार्टियों से लागू करवा पाएंगी इसमें संदेह है। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की प्रकृति अकेले चलने की है।

राहुल का एजेंडा क्या है?

कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आरोप है कि वे देश में विकास को बाधित कर रहे हैं, निवेश रोकना चाहते हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं आदि, आदि। सवाल है कि क्या गौतम अडानी के खिलाफ कोई बात कहना देश के खिलाफ बोलना हो गया? पहले तो भाजपा और केंद्र सरकार के इकोसिस्टम ने यह नैरेटिव बनाया कि सरकार के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार को ही देश बना दिया। अब क्या नरेंद्र मोदी वाली स्थिति ही गौतम अडानी की भी देश में बना रहे है, जो उनके खिलाफ बोलने को भी देश के खिलाफ बोलना कहा जाएगा? इसी तरह दूसरा सवाल यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी ओसीसीआरपी की किसी रिपोर्ट का हवाला देना देश विरोधी कैसे हो गया? यह संस्था तो पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के मामले खोलती है। इसका मतलब है कि संस्था भ्रष्टाचार विरोधी है। तो भ्रष्टाचार विरोधी संस्था भारत विरोधी संस्था कैसे हो गई? संस्था की रिपोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ है। भाजपा का राहुल गांधी के ऊपर सबसे ज्यादा हमला इस बात को लेकर है कि उन्होंने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का बार-बार हवाला दिया है। इस संस्था ने पेगासस से जासूसी का मामला खोला था और अडानी समूह द्वारा शेयर बाजार में हेराफेरी का भी खुलासा किया था।

ठप्प करने के समर्थन में नहीं है। वह चाहती है कि दूसरे मुद्दों पर संसद में चर्चा हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि अडानी के अलावा दूसरे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने राज्य के स्थानीय मुद्दे और मणिपुर का मुद्दा उठाने के नाम पर अपने को कांग्रेस से दूर किया। तृणमूल के यह स्टैंड लेने के करीब एक हफ्ते बाद समाजवादी पार्टी ने भी यही स्टैंड ले लिया। सपा ने भी कह दिया कि वह अडानी के मसले पर कांग्रेस के साथ नहीं है। उसके लिए संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा ज्यादा बड़ा था।

जिस समय तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अडानी मसले पर कांग्रेस को अलग-थलग करने का अपना दांव चला उसी समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी जिद में कहा कि कांग्रेस अडानी का मुद्दा नहीं छोड़ने जा रही है। उनको पता था कि यह मुद्दा सरकार को और भाजपा को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तभी उन्होंने साफ कर दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस यह मुद्दा उठाती रहेगी। उस समय तक संभवत: उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस मुद्दे की हवा निकालने के लिए तृणमूल कांग्रेस किस हद तक जाएगी। तृणमूल कांग्रेस का अगला कदम था, सीधे कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती देना और विपक्षी गठबंधन में उसकी अथॉरिटी को कमजोर करना। इसके लिए सीधे ममता बनर्जी मैदान में उतरीं। पहले कल्याण बनर्जी या काकोली घोष दस्तीदार या दूसरे नेताओं के जरिए बयानबाजी हो रही थी लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने की बात आई तो खुद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था मौका मिले तो वे इसका नेतृत्व करना चाहेंगी। इसके बाद तो पंडोरा बॉक्स खुल गया। ऐसा लगा, जैसे पार्टियां कांग्रेस से भरी बैठी हैं। एक के बाद एक नेताओं ने कांग्रेस से नेतृत्व छीनकर ममता बनर्जी को देने की मांग शुरू कर दी। संजय राउत से लेकर शरद पवार और रामगोपाल यादव से लेकर लालू यादव तक सब ममता की जयकार करने लगे। रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल विपक्षी गठबंधन के नेता नहीं हैं तो लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस के विरोध की परवाह किए बगैर ममता को नेता बनाना चाहिए। इसके बाद मीडिया में कथित राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा बताया जाने लगा कि ममता बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने के क्या-क्या फायदे इंडिया ब्लॉक को मिल सकते हैं।

जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर इससे भी फर्क नहीं पड़ा और वे अडानी का मुद्दा उठाते रहे तब ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को पंचर करने का प्रयास शुरू हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम का रोना बंद करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तो जश्न मनाती है और हारने पर ईवीएम को दोष देती है। इसके तुरंत बाद ईडी और सीबीआई की जांच में फंसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के ईवीएम विरोध को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस सबूत पेश करे कि कैसे ईवीएम हैक किया जाता है। अडानी के बाद ईवीएम दूसरा मुद्दा था, जिस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरोध का पूरा नैरेटिव बनाया था। लेकिन भाजपा के साथ-साथ विपक्ष की पार्टियों ने ही इन दोनों मुद्दों को पंचर करने का प्रयास किया।

सवाल है कि विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को अलग-थलग करने का यह जो प्रयास संसद सत्र में किया उससे कांग्रेस कमजोर हुई, बैकफुट पर गई, अलग-थलग हुई या विपक्ष की चुनिंदा पार्टियों की पोल खुली? क्या इससे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं? क्या इन दोनों को अंदाजा है कि इनको लेकर क्या नैरेटिव बन रहा है? सहज रूप से यह धारणा बनी है कि देश के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने चाहे जिस तरह से हो इन दोनों नेताओं को अपना बना लिया है। यह भी कहा और माना जा रहा है कि विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां अडानी मसले पर राहुल के अभियान से इसलिए असहज हैं क्योंकि उनको किसी न किसी तरह का लालच है या भय है।

किसको लालच है और किसको भय है, यह अलग चर्चा का विषय है लेकिन हकीकत है कि कांग्रेस को अलग-थलग करने के चक्कर में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के साथ-साथ विपक्ष की कई पार्टियों ने अपने को एक्सपोज कर लिया है। असल में इन पार्टियों ने एक तीर से दो शिकार करने का प्रयास किया। उनको लगा कि कांग्रेस के एजेंडे को पंचर करेंगे तो सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा और दूसरे, कांग्रेस को भी अलग-थलग कर देंगे तो विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व की राह निष्कंटक बनेगी। साथ ही वोट की राजनीति में भी कांग्रेस की ओर से पैदा की जा रही चुनौती खत्म होगी। पता नहीं यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ लेकिन यह जरूर हुआ कि इन नेताओं ने अपनी जो छवि लड़ने वाले और क्रांतिकारी नेता की बनाई थी वह अब पूंजी के सामने झुकने और सत्ता की ताकत से दबने वाले नेता की हो गई है। कहने को ये पार्टियां अब भी केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करेंगी लेकिन उनका कोई खास मतलब नहीं होगा। उसे नूरा कुश्ती ही माना जाएगा।

● **विपिन कंधारी**

जनवरी में इलाहाबाद में होने वाला महाकुंभ कई मामलों में ऐतिहासिक होने वाला है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस कुंभ में संघ का बड़ा मंथन होने वाला है। यह मंथन 2013 की तरह ही होगा। यानि इस कुंभ में संघ साधु-संतों के साथ मिलकर देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए एकमात्र चेहरा योगी आदित्यनाथ का है।

महाकुंभ से निकलेगा देश का भावी पीएम

2013 के कुंभ में भाजपा के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खरे उतरे। वे अब तक चौकन्ने रहकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की चर्चा तो अब शुरू करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी का कहना हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भाजपा के अगले पीएम कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। वे बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी है। महाकुंभ 13 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाला है। 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को भाजपा का पीएम कैंडिडेट बनाया गया। क्या इस बार ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के लिए होगा।

लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वे राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर भी दिखा। यहां उन्होंने 11 रैलियां कर 17 कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। इनमें 15 चुनाव जीत गए। योगी आदित्यनाथ ने ये नारा उप्र में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बार-बार दोहराया। इसके बाद यही नारा महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर को ठाणे और वाशिम में हुई रैलियों में अलग ढंग से यही बात कही। आरएसएस के पदाधिकारी बताते हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा भले योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला हो, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला बहुत पुराना गीत है। इसे आजादी के समय से गाया जाता है। कुंभ में इस बार हिंदू एकता की चर्चा होगी, क्या किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? इन सवालों पर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इसकी चर्चा तो हम

मोदी को लाने का श्रेय किसको

आरएसएस के एक पदाधिकारी का कहना है कि मोदी को लाने का श्रेय अशोक सिंघल को ही जाता है। तोगड़िया इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी असहमति नहीं जताई। धीरे-धीरे वे संगठन के कामों से दूर हो गए और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का नया संगठन बनाया। सिंघल और तोगड़िया के बीच वैसे भी कुछ बातों और विचारों पर भिन्नता थी। सिंघल ने भी इसे कभी सामने नहीं आने दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी 2013 के कुंभ में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगने की कहानी बताते हैं। मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। रविंद्र पुरी कहते हैं कि संत समाज ने 2010 से ही अलग-अलग मंचों पर पीएम पद के उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लेना शुरू कर दिया था। कुंभ की धर्म संसद में तो उनके नाम पर मुहर लगी थी। ये सारी प्लानिंग पहले से थी। पीएम पद की रेस में कुछ और नाम होने को लेकर रविंद्र पुरी कहते हैं, रेस में लालकृष्ण आडवाणी बहुत आगे थे, लेकिन संत समाज मानता था कि नरेंद्र मोदी पक्के सनातनी हैं। सनातन धर्म की रक्षा वही कर सकते हैं। इसलिए संतों ने एकमत से उन्हें चुना। इस प्रस्ताव पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीधे कुछ नहीं कहा। इतना जरूर कहा कि संतों की वाणी ही देववाणी है। तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि संतों की भावना हम तक आई है। इससे अलग कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। मैं ये प्रस्ताव ऊपर तक ले जाऊंगा।

कई साल से कर रहे हैं। ये हमारे करिकुलम में बहुत पहले से है। इसकी चर्चा कुंभ में क्यों करें। इस बार चर्चा आरएसएस के उस गीत को दोबारा चर्चा में लाने वाले की होगी। चर्चा होगी कि देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। चर्चा होगी कि नया सूर्य कौन होगा। आरएसएस के पदाधिकारी कहते हैं कि ये सब उस तरह नहीं होगा, जैसे मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। वे कहते हैं कि तब कुंभ के अगले साल लोकसभा चुनाव थे। इसलिए पीएम पद के लिए चेहरे पर पक्की मुहर के लिए उस आयोजन से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता था। इतने बड़े स्तर पर हिंदू समाज के संगठन और साधु-संतों का जमावड़ा फिर कहां मिलता। इस बार कुंभ और चुनाव के बीच 4 साल का फासला है। नाम पर तो चर्चा होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच एक प्रस्ताव की तरह इसे लाया जाएगा। पदाधिकारी कहते हैं कि लिस्ट में मोटे तौर पर अब तक तो योगी ही हैं।

प्रयागराज में मिले विश्व हिंदू परिषद के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ का नाम और भी मजबूती से लेते हैं। उनका ताल्लुक उत्तराखंड से है। वे कहते हैं, कि आरएसएस किसी को ऐसे ही आगे नहीं लाता। उसके लिए जमीन तैयार होती है। जमीन पर खाद-पानी दिया जाता है। पहले छोटा सा अंकुर फूटता है और फिर पौधा। यही आरएसएस के काम करने का तरीका है। वे आगे कहते हैं, कि जिस सवाल के जवाब की पुष्टि जनता चाहती है, उसे घटनाओं के क्रम में जोड़कर देखें तो सटीक जवाब मिल जाएगा। आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला गीत उप्र के मुख्यमंत्री योगी के मुख से समय-काल-परिस्थिति के रूप में ढलकर नए अंदाज में बिना किसी उद्देश्य के नहीं निकला। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और कुंभ मेले के आयोजकों में शामिल रविंद्र पुरी कहते हैं, योगी हिंदू धर्म और सनातन के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। वे कतार में हैं। उनकी दावेदारी मजबूत है। कतार में तो अमित शाह का नाम भी है, लेकिन अभी मोदी जी बहुत एक्टिव हैं। किसी पीएम के पद पर रहते दूसरे कैंडिडेट की चर्चा ठीक नहीं।

आरएसएस से जुड़े एक शख्स की कहानी सुनाते हैं। उनका परिवार कई दशकों से आरएसएस में है। वे कहते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को मनाने से लेकर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव लाने और मुहर लगने तक की प्रक्रिया का मैं चश्मदीद गवाह हूं। उस वक्त कॉलेज में था। मेरे दादाजी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष थे। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहे अशोक सिंघल से हमारे परिवार का बहुत जुड़ाव था। 2012 से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुहर लगवाना चाहते थे। मोहन भागवत उनके नाम पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। बहुत कोशिशों के बाद अशोक सिंघल ने मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी कर लिया। उसके बाद कुंभ में धर्म संसद हुई। उसमें मोहन भागवत ने हिंदू और संत समाज के बीच पहली बार पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। वे कहते हैं कि धर्म संसद का आखिरी दिन था। तारीख 5 फरवरी, 2013 थी। करीब 10 हजार दंडी स्वामी मौजूद थे। सभी ने चिमटा बजाकर मोदी का नाम लिया। उनके नाम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। फिर यही नारे जनता के बीच भी लगे। ये जनता संतों की भक्त थी। ये मीडिया और पब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर लाने की प्लानिंग थी।

आरएसएस के सूत्र बताते हैं कि 2012 में अशोक सिंघल ने कई मंचों से नरेंद्र मोदी के नाम का संकेत देना शुरू कर दिया था। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय केसर भवन में धर्म अर्पण रक्षा निधि का कार्यक्रम था। इसमें सालभर के लिए फंड जुटाया जाता है। नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। अगले ही साल कुंभ होना था। अशोक सिंघल ने आरएसएस और भाजपा से पहले संत समाज को राजी किया। कुंभ में भी नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले संत समाज ही लाया था। नारायणी संप्रदाय के एक संत कुंभ में शामिल हुए थे। उन्होंने धर्म संसद के पहले दिन संतों को बताया, मैं गंगा स्नान कर रहा था, अचानक एक चिंता मेरे मन से निकली। मैंने मां गंगा से कहा, भारत का उद्धार कैसे होगा। मैंने आंखें बंद कीं, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया। नारायणी संप्रदाय के संत के बाद वासुदेवानंद शंकराचार्य ने नरेंद्र मोदी के नाम पर सबसे पहले मुहर लगाई और उनका नाम संतों के सामने रखा। 25-26 अक्टूबर को मथुरा में हुई बैठक में कुंभ पर चर्चा हुई थी। सूत्र के मुताबिक, इस बार कुंभ में हिंदू समाज के उन पंथ, संप्रदाय, जातियों और जनजातियों को जोड़ने पर सहमति बनी है, जिन्हें अब तक कुंभ में न्यौता देकर नहीं बुलाया गया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर लिंगायत मठ के मठाधीश हैं। इसके अलावा कई जनजातियां हैं। इनमें नॉर्थ-ईस्ट की जनजातियों के संगठनों को बुलाने की तैयारी हो रही है। नॉर्थ-ईस्ट से कार्बी, जैनतिया, देवरी, खासी, कुकी और मैतेई जनजातियों को बुलाया जाएगा।

● इन्द्र कुमार

मोदी का नया दांव एक देश-एक चुनाव!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने तीसरे कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे है, जिसके तहत मौजूदा समय में करीब-करीब पूरे पांच साल चलने वाले चुनावों को एक सूत्र में बांधकर सभी चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान है, यदि वास्तव में निरपेक्ष भाव से देखा जाए, तो यह इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि पूरे पांच साल देश में चलने वाले इस दौर में न सरकारें ठीक से काम कर पा रही है और न ही विधान मंडल। इसलिए मोदी जी की इस पहल की प्रशंसा की जानी चाहिए, इस पहल को मूर्तरूप मिलने के बाद देश की अपार धनराशि और अमूल्य समय दोनों की ही काफी बचत होगी और सरकारें व राजनेता पूरे मनोभाव से जनसेवा के महायज्ञ में अपनी आहूतियां डाल पाएंगे। एक देश-एक चुनाव की इस पहल को शीघ्र ही मूर्त रूप दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विचार कर अपनी सिफारिशें प्रदान करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने हाल ही में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा है, इस पैनल ने सुझाव में कहा है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए।

कांग्रेस में होगी जोगी परिवार की वापसी...

कांग्रेस में जल्द ही जोगी परिवार की वापसी हो सकती है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर विलय का प्रस्ताव भेजा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की गठित पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की है। पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पार्टी का कांग्रेस में विलय हो। सभी पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं। डॉ. रेणु जोगी ने प्रवेश कराने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ अंतागढ़ के उपचुनाव में गड़बड़ी करने के आरोपों पर अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को वर्ष 2016 में पार्टी से निष्कासित किया था। अमित जोगी को छह वर्षों के लिए पार्टी से निकाला गया था। अजीत जोगी ने कवर्धा जिले के ठाठापुर गांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की स्थापना 23 जून 2016 को की थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने 55 तथा बीएसपी ने 35 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। गठबंधन ने अजीत जोगी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। गठबंधन को केवल सात सीटें (जोगी 5 और बसपा 2) ही मिलीं। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। 77 सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से चुनाव लड़ा था।

2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ था, लेकिन 2018 की तरह अच्छे खासे वोट बटोरने वाली जेसीसीजे का 2023 के चुनाव में सफाया हो गया था। पूर्व विधायक और अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखते हुए कहा कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की रही है, ऐसे में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया जाए और फिर से सभी कार्यकर्ताओं को मुख्यधारा में जोड़ा जाए। दरअसल, स्व. अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी में लगातार टूट देखी गई है, कई नेता और पूर्व विधायक कांग्रेस और भाजपा में चले गए हैं। यही वजह है कि जोगी परिवार भी अब फिर से कांग्रेस में वापसी करना चाहता है। पिछले दिनों जब रेणु जोगी और अमित जोगी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से मुलाकात की थी, उसी के बाद से इस बात की कयासबाजी शुरू हुई थी।

दरअसल, 2014 के एक उपचुनाव में कथित ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सीनियर नेता अजीत जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जबकि उनके बेटे अमित जोगी को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी के बाद से अजीत जोगी ने नई पार्टी बनाने की शुरुआत की थी। 21 जून 2016 को छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपनी अलग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम से पार्टी बनाने का ऐलान किया था। जिसके बाद 2018 के चुनाव में जेसीसीजे और बसपा ने गठबंधन किया था। लेकिन दोनों पार्टियों का गठबंधन महज 7 सीटें ही जीत पाया था। 29 मई 2020 को अजीत जोगी के निधन के बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। 2023 के विधानसभा चुनाव आते-आते पार्टी में कई बार फूट दिखी। आलम यह रहा है कि जेसीसीजे राज्य की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई थी। पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया। बाद में भाजपा की सरकार बनने के बाद जोगी परिवार एक बार फिर कांग्रेस से अपनी नजदीकियां बढ़ाता दिखा। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी जेसीसीजे ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। इसके बाद जोगी परिवार की नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से मुलाकात के बाद पार्टी विलय की बात चली थी, जबकि अब रेणु जोगी के पत्र से भी यह साफ होता दिख रहा है कि जेसीसीजे का विलय कांग्रेस में हो सकता है। हालांकि सवाल यह भी है कि पार्टी के कई नेता इसके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में जेसीसीजे का कांग्रेस में विलय होता है या नहीं यह फैसला कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया जा सकता है।

रेणु जोगी के लेटर के बाद सियासत तेज हो गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। उन्होंने आयोजन दिया है। उनके प्रवेश को लेकर साथियों के विचार हैं इसे लेकर स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे इस संबंध में क्या विचार हैं मैं इसे पार्टी को बता दूंगा। अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हुआ। अजीत जोगी के निधन के चार साल बाद उनकी पत्नी ने कांग्रेस में वापसी का फैसला किया है। रेणु जोगी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। अजीत जोगी की छत्तीसगढ़ की सियासत में जमीनी पकड़ थी। अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी के अस्तित्व पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

सचिन पायलट ने गठित की है समिति

बताते चलें कि जोगी परिवार की कांग्रेस में वापसी के प्रयास कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की ओर से समिति गठित करते ही शुरू हो गई थी। विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले कुछ नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कुछ को पार्टी के खिलाफ काम करने पर हटाया गया था। अब कुछ नेता पार्टी में वापसी के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे नेताओं ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से संपर्क कर लिखित में आवेदन दिया है। पायलट ने आवेदनों की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए सात सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश सहप्रभारी एसए संपत कुमार, जरिता लैतफलांग, विजय जांगिड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू और मोहन मरकाम शामिल हैं।

मंत्री पद को तरसे भुजबल

छगन भुजबल एक वक्त में महाराष्ट्र के दूसरे नंबर के नेता थे। भुजबल महाराष्ट्र के दो बड़े नेता शरद पवार और बालासाहेब ठाकरे के साथ काम कर चुके हैं। 5 मुख्यमंत्री के साथ भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें फडणवीस कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के विस्तार के बाद छगन भुजबल सियासी सुर्खियों में हैं। येवला से एनसीपी सिंबल पर विधायक चुने गए भुजबल मंत्री न बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भुजबल की गिनती एक वक्त में महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में होती थी। शरद पवार से लेकर बालासाहेब ठाकरे और सोनिया गांधी तक भुजबल की सीधी पहुंच थी, लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि भुजबल अब मंत्री पद को तरस रहे हैं।

पुणे से 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले भुजबल शुरुआत के दिनों में अपनी मां के साथ बायकुला में सब्जी बेचा करते थे। 1960 के दशक में भुजबल बाल ठाकरे के मराठा आंदोलन से जुड़ गए। जब शिवसेना का गठन हुआ, तो वे इसके संस्थापक सदस्य बने। शिवसेना की स्थापना के वक्त बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र में फायरब्रांड नेताओं को तरजीह दे रहे थे। भुजबल को इसका फायदा मिला। वे पहले पार्षद और फिर 2 बार मुंबई के मेयर चुने गए। 1985 में बालासाहेब ठाकरे ने भुजबल को मझगांव सीट से विधायकी का टिकट दिया। भुजबल जीतने में कामयाब रहे। 1990 में भी वे इसी सीट से विधायक चुने गए। 1991 में भुजबल ने शिवसेना से बगावत कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। भुजबल ने यह बगावत उस वक्त की थी, जब मुंबई में बालासाहेब ठाकरे के खिलाफ बोलने का कोई नेता रिस्क नहीं लेता था। भुजबल इसके बाद कांग्रेस में आ गए और करीब 8 साल तक ओल्ड ग्रैंड पार्टी में रहे। 1998 में एनसीपी का जब गठन हुआ तो भुजबल शरद पवार के साथ हो लिए। भुजबल को विलासराव देशमुख की सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया गया। भुजबल इसके बाद कई मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। इनमें सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है। 2023 में भुजबल शरद पवार का साथ छोड़ अजित के साथ आ गए। उन्हें उस वक्त अजित के साथ शिंदे कैबिनेट में जगह भी मिली। 2024 में शरद पवार ने भुजबल के क्षेत्र से ही अपनी पार्टी का प्रचार शुरू किया था। इसके बावजूद भुजबल चुनाव जीत गए। जीत के बाद भुजबल को कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फडणवीस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया।

भुजबल क्यों और कैसे साइड लाइन होते गए इसके कई कारण हैं। शिवेसना से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले भुजबल बालासाहेब ठाकरे के सबसे विश्वासपात्र थे। 1991 में जब हिंदुत्व का मुद्दा परवान चढ़ रहा था, तब भुजबल ने जाति एंगल देते हुए ठाकरे से बगावत कर दी। भुजबल इसके बाद कांग्रेस में चले गए, लेकिन शरद पवार ने जब खुद की पार्टी बनाई तो वे भी इसमें आ गए। 2023 में भुजबल शरद पवार का साथ छोड़ अजित के साथ चले गए, जबकि भुजबल को एनसीपी में शरद का सबसे करीबी नेता माना जाता था। कहा जाता है कि 2023 में एनसीपी की टूट के वक्त भुजबल ने ही शरद पवार को अंधेरे में रखा था। दरअसल, शरद ने पार्टी बचाने की जिम्मेदारी भुजबल को सौंपी थी, लेकिन आखिरी वक्त में भुजबल भी अजित के साथ चले गए। फायरब्रांड नेता भुजबल अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री रहते हुए भुजबल ने खुलकर ओबीसी का पक्ष लिया था, जिसकी वजह से मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर पूरी सरकार आ गई थी। वहीं 2023 में भुजबल ने ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। भुजबल ने कहा था कि ब्राह्मण समाज में कोई भी अपने बच्चे का नाम शिवाजी-संभाजी नहीं रखता है। उनके इस बयान पर भी काफी हंगामा हुआ। छगन भुजबल 77 साल के हो गए हैं। फडणवीस कैबिनेट में उम्र का खास ख्याल रखा गया है। अधिकांश मंत्री पद 65-70 साल के उम्र के नेताओं को ही दी गई है। कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री भाजपा के गणेश नाइक (74) हैं। कहा जा रहा है कि 75 प्लस होने की वजह से ही कैबिनेट से भुजबल का पत्ता कटा है। वहीं भुजबल जिस नासिक से आते हैं, वहां से दादा जी भुसे और नरहरि जिरवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ऐसे में क्षेत्रीय समीकरण में भुजबल फिट नहीं बैठ रहे थे। 2003 में तेलगी केस ने महाराष्ट्र और देश की सियासत में हड़कंप मचा दिया। तेलगी पर नकली स्टांप बेचकर पैसा कमाने का आरोप था। इस केस में छगन भुजबल का भी नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ गई। भुजबल इसके बाद साइड लाइन हो गए। 2009 में उन्हें फिर से कैबिनेट में शामिल किया गया, लेकिन इस बार भी उन पर महाराष्ट्र सदन में निर्माण को लेकर घोटाले का आरोप लगा। 2016 में ईडी ने भुजबल को गिरफ्तार भी किया था। इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक भुजबल पर अभी करीब 3 मुकदमे भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, जिसकी जांच एसीबी और ईडी कर रही है।

● **बिन्दु माथुर**

पोस्टर, चप्पल और अनाप-शनाप बोलना

महाराष्ट्र में एनसीपी (अजित पवार) नेता छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाए जाने पर ओबीसी समुदाय में भारी नाराजगी है। समर्थकों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए राज्य में ओबीसी समुदाय के बड़े नेता छगन भुजबल ने समर्थकों से कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ बैनर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ ही उनकी तस्वीरों पर चप्पल फेंकना और उनके खिलाफ अनाप-शनाप बोलना, ये सभी चीजें आपकी तरफ से नहीं की जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हमारे सदस्य नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके समर्थकों पर अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको इसे सभ्य शब्दों और तरीके से करना चाहिए। दरअसल, समुदाय के लोगों ने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पोस्टर को लेकर उनके खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छगन भुजबल ने कहा कि हम 40 से ज्यादा सालों से काम कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल मंत्री पद का नहीं है। हमारी ये लड़ाई पहचान की लड़ाई है।

एकजुट दिखने की कोशिश

कांग्रेस फिर सरकार में आई, तो गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री

पूर्व मंत्री मेघवाल के वायरल हो रहे वीडियो में वह कह रहे हैं कि भजनलाल जी अब भी आपके पास समय है। मैं मानता हूं कि सरकार के लास्ट के दिनों में विरोध होता है, लेकिन आपकी यह पहली ऐसी सरकार है, इसके पहले साल के कार्यकाल में ही अधिकारी कहने लगे हैं कि अगली बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। मेघवाल ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में यदि फिर से कांग्रेस आई, तो गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ मुख्यमंत्री की रेस में है, बल्कि नंबर एक पर हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत के विकास कार्यों की हर जगह चर्चा है। इसमें कोई शक नहीं है और अगर हाईकमान चाहेगी, तो गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर, पूर्व मंत्री मेघवाल के बयान के बाद गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने बिना नाम लिए गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने पहले ही कहा था, एक पार्टी जीतने और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में अलग-अलग नेता मुख्यमंत्री बनने तक ही सीमित रह जाते हैं।

जयपुर में कई सालों बाद एक अलग सियासी नजारा देखने को मिला। राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सारे गुट एक साथ नजर आए। पूरी कांग्रेस एक मंच पर थी। ऐसे नजारे 2018 में कांग्रेस के सत्ता में लौटने से पहले जयपुर की सिविल लाइन्स पर आम थे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध करने से ज्यादा कांग्रेस की एकजुटता की चर्चाएं रहीं। हालांकि, एकजुटता में थोड़ी असहजता भी दिखी, इशारों-इशारों में नेताओं ने एक-दूसरे पर सियासी वार भी किए। मंच पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य नेता मौजूद थे।

गौरतलब है कि 2020 में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसके बाद पायलट को अध्यक्ष पद के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री का पद भी गंवाना पड़ा था। विरोध सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने खूब चुटकी ली। उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास के भाषण पर चुटकी लेते हुए कहा, प्रताप सिंह मंत्री रहे हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग सर्वसम्मति से मानते हैं कि प्रताप सिंह आज जूते पहन कर आए हैं। आज पुलिस के सामने जो प्रदर्शन करना है, उसमें हम सबके तरफ से प्रताप सिंह खाचयिवास जी को नॉमिनेट करते हैं। आगे जाए और मजबूती से हमारी बात रख दें। उन्होंने कहा कि क्या है न प्रताप सिंह जी, समय का पहिया पूरा घूमता है। फिर वही धरना है, फिर वही राजस्थान पुलिस है और फिर वही विरोध का समय है। सचिन पायलट के इस बयान के कई सियासी मायने निकले जा सकते हैं।

राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि सचिन पायलट एक बार अपने उस नैरेटिव को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके संघर्ष की वजह से 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी। सरकार बनने के बाद पायलट हर मंच से यह कहते नजर आते थे कि हमने कांग्रेस को 21 से 95 सीटों पर पहुंचाया है। गौरतलब है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। कांग्रेस 200 में से महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। तभी से गहलोत-पायलट के बीच तनातनी की खबरे आए दिन टीवी और अखबारों की जीनत बनती थीं। कांग्रेस की सियासत में एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान लगे पोस्टर में से सचिन पायलट की फोटो फिर से नदारद दिखी। इसको लेकर सियासी गलियारों में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इस दौरान बैठक में कांग्रेस की युवा नेता विभा माथुर सचिन पायलट की फोटो नहीं होने पर पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल पूछ बैठीं। डोटासरा ने विभा माथुर को बैठ जाने के लिए कहा, तो विभा माथुर ने भी कह दिया कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। पायलट की उपेक्षा को लेकर हो रहा है उबाल कांग्रेस में एक बार फिर पायलट और गहलोत को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। जयपुर में कांग्रेस की बैठक में लगे पोस्टर में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की फोटो लगी हुई थी, उसमें से सचिन पायलट की फोटो गायब थी। इस पर पायलट समर्थक विभा माथुर ने डोटासरा से पूछ लिया कि यहां पायलट की फोटो क्यों नहीं है? इसको लेकर डोटासरा और माथुर की बीच तीखी बहस भी हुई। डोटासरा ने कहा कि फोटो प्रोटोकॉल के तहत लगी हुई है, इसको लेकर दोनों में तकरार हुई। इस पर डोटासरा ने कहा, आप बैठ जाइए, आपसे बात नहीं हो रही है। इस पर विभा माथुर भड़क गईं और उन्होंने डोटासरा को सुनाते हुए कहा कि आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। हमारी चार पीढियां कांग्रेस से जुड़ी हुई है। युवा नेता विभा माथुर सचिन पायलट समर्थक हैं। वह राजस्थान कांग्रेस कमेटी की सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की नातिन भी हैं। उनकी मां वंदना माथुर एआईसीसी कमेटी की सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा विभा कांग्रेस की आईटी सेल की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। इधर, कांग्रेस के पोस्टर में से सचिन पायलट की फोटो गायब होने से फिर से सियासी हलचल मच गई। राजनीतिक जानकार कयास लगा रहे हैं कि गहलोत और पायलट को लेकर अभी भी कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है।

राजस्थान में अगली बार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा? यह मुद्दा फिर गर्माने लगा है। इस बीच पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो काफी चर्चा में है। इसमें उन्होंने भजन लाल सरकार को 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर घेरा। साथ ही उन्होंने इशारों में यह भी बात कर डाली कि मुख्यमंत्री की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर एक हैं। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने पर फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। मेघवाल के इस बयान के कारण कांग्रेस की सियासत में एक बार फिर पारा उबाल पर है। इधर, कांग्रेस में फिर से अशोक गहलोत-सचिन पायलट के विवाद के शुरू होने को लेकर सियासी चर्चा हो रही है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

साइकिल-हाथ में बढ़ी दूरी

केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी की 4 लाख से अधिक वोटों की जीत के बाद उप्र के प्रयागराज में आनंद भवन पर एक होर्डिंग लगी जिसमें लिखा था- इंदिरा इज बैक। वोटर अभी भी कांग्रेस से उम्मीद रखे हैं। उप्र में कांग्रेस के साथ उपचुनाव में सपा ने जिस तरह का व्यवहार किया उससे लोकसभा में नंबर एक की पार्टी बनी सपा को भाजपा के मुकाबले मुंह की खानी पड़ी। उप्र की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर सपा उत्साह से लबरेज थी। कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थीं। उप्र ने ही भाजपा को बहुमत के आंकड़े से दूर रखा था। इस जीत का श्रेय राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को गया था। चुनाव के बाद दोनों नेताओं में दूरी बढ़ने लगी। अखिलेश यादव के करीबी लोगों ने उनको समझाया कि कांग्रेस को मिलने वाली सफलता का कारण सपा थी। कांग्रेस जैसे-जैसे मजबूत होगी सपा वैसे-वैसे कमजोर होगी। इसके बाद कांग्रेस और सपा के बीच बनी दोस्ती में दरार आने लगी।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों का कोई तालमेल नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर में सपा ने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे। सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ उप्र में उपचुनाव भी थे। सपा महाराष्ट्र में कांग्रेस से तालमेल कर सीटें चाहती थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ एनसीपी और शिवसेना भी गठबंधन का हिस्सा थी। ऐसे में सपा के लिए बड़ी गुंजाइश नहीं बनी। इसका बदला अखिलेश यादव ने उप्र में लेने की सोची। उप्र में कांग्रेस 3 से 5 सीटें चाहती थी। सपा ने 2 सीटें दीं, उसमें भी कई तरह की शर्तें थीं। ऐसे में कांग्रेस ने उप्र में उपचुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। अब चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ होते हुए भी साथ नहीं थे। कांग्रेस का फोकस महाराष्ट्र, झारखंड और वायनाड सीट पर था। उसके नेता वहीं प्रचार करते नजर आए। उपचुनाव में कांग्रेस मंझवा और फूलपुर सीट अपने लिए चाहती थी। सपा कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद सीट दे रही थी। असल में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित और मुस्लिम वोट मिले थे। कांग्रेस के साथ होने के कारण ही दलित वोट सपा को मिले थे। दलित और मुस्लिम वोटों के एक साथ आ जाने से भाजपा को काफी नुकसान हुआ था।

दलित वोट की एक खासियत है कि वह कभी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कारण सपा को दलित वोट मिल गए। उपचुनाव में कागज के ऊपर सपा-कांग्रेस का गठजोड़ बना था। चुनाव संचालन के लिए कमेटियां भी बनी थीं। इसके बाद सपा ने कांग्रेस के नेताओं को कोई महत्व नहीं दिया था। जिसके कारण कांग्रेस उप्र में साइलेंट हो गई थी। जिससे चुनावी नतीजे इतने विपरीत आ गए। 2022 की विधानसभा चुनाव में इन्हीं 9 सीटों में से 4 करहल, सीसामऊ, कटेहरी और कुदरकी पर सपा और 4 फुलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर पर भाजपा ने चुनाव जीता था। एक सीट मीरापुर लोकदल के खाते में गई थी। उस समय लोकदल सपा की सहयोगी पार्टी थी। 2022 के चुनावी नतीजों में देखें तो सपा के पास 5 और भाजपा के पास 4 सीटें थीं। 2024 में जब इन सीटों पर उपचुनाव हुए तो सपा के पास केवल 2 सीटें ही रह गईं। जबकि 5 माह ही पहले सपा ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। इसकी मूल वजह दलित वोट रहा जो पीडीए यानि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा देने के बाद भी सपा के साथ खड़ा नहीं हुआ।

उपचुनावों में अखिलेश यादव ने पूरी मेहनत के साथ प्रचार किया। यह बात और है कि उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने उस तरह से प्रचार नहीं किया जैसे टोलियां बनाकर भाजपा के लोगों ने प्रचार किया। भाजपा की टोलियों ने जमीनी स्तर पर सपा के जातीय गोलबंदी के खिलाफ प्रचार किया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लोगों के बीच ले गए। भाजपा ने इन टोलियों में उन नेताओं को कमान सौंपी जिन जातियों के वोट ज्यादा थे। सपा इसकी काट नहीं कर पाई। सपा को लग रहा था कि दलित उसके साथ हैं, मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देगा और पिछड़े भी सपा के साथ हैं। ऐसे में उसे जीत के लिए कांग्रेस के कंधे की जरूरत नहीं है। सपा का अति आत्मविश्वास उसे ले डूबा। उसने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को ऑक्सीजन देने का काम किया है। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो विवाद भाजपा में था वह भी खत्म हो गया है। दलित और मुस्लिम वोटर ने एक और संकेत दे दिया है कि वह सपा और बसपा की जगह पर दूसरे विकल्प की ओर भी देख रहा है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

चुनावी समीकरण गड़बड़ हो गया

सपा में परिवारवाद हावी है। वहां मुलायम परिवार ही नहीं दूसरे नेताओं के परिजनों को सबसे ज्यादा टिकट दिए जाते हैं। जो पार्टी में विरोध के स्वर को मजबूत करता है। 9 विधानसभा सीटों के चुनाव में 3 टिकट परिवार के लोगों को दिए गए। करहल में तेजप्रताप यादव मुलायम परिवार का हिस्सा है। सीसामऊ से चुनाव लड़ी नमीस सोलंकी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी थीं और कटेहरी से चुनाव लड़ी शोभावती वर्मा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी हैं। इन चुनावों में सपा ने 4 सीटों फूलपुर, सीसामऊ, कुदंरकी और मीरापुर में मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, जिनके कारण चुनावी समीकरण गड़बड़ हो गया। सपा ने जिन दो सीटों पर जीत हासिल की में करहल में 14 हजार और सीसामऊ में 8 हजार से ही जीत हासिल हुई। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में सपा की सीट वितरण में कमी नजर आई, जिसकी वजह से यह हार हुई है। इससे भाजपा लोकसभा चुनाव की हार के नैतिक दबाव से बाहर आ गई है। सपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव से ही उम्मीद की जाती है कि वह जीत को थाली में परोस कर दे दें। भाजपा में जिस तरह से तीसरे और चौथे नंबर के नेता भी जीत के लिए मेहनत करते हैं उस तरह की मेहनत सपा-कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। ऐसे में दोनों ही दलों को नए सिरे से संगठन पर काम करने की जरूरत है।

पलटी, एंट्री और धमकी

जब-जब देश में राजनीति की बात होती है, तब-तब लोगों को बिहार जरूर याद आता है। आखिर अपना बिहार है ही इतना खास। बिहार के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को राजनीति में खूब दिलचस्पी होती है। इसके कुछ कारण भी हैं, और वो हैं बिहार के राजनेता। अब चूंकि साल 2024 का अंत हो रहा है, तो इनकी बात होनी तो बनती है।

साल 2024 की शुरुआत में ही बिहार का सियासी पारा हाई हो गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हां, उन्होंने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया, लालू की दोस्ती को ठुकरा दिया और फिर अपने पुराने मित्रों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने एनडीए के साथ पार्टनरशिप कर ली। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये अपने आप में ही एक अनोखा रिकॉर्ड है।

अब चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए में शामिल हो चुकी थी, तो लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू हो गई। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि नीतीश भाजपा के सामने बैकफुट पर नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जदयू को 16 सीटें मिलीं और 12 पर पार्टी को जीत हासिल हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां नीतीश कुमार एनडीए के साथ लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वहीं, उनके भतीजे तेजस्वी यादव भी अपनी जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए थे। हालांकि, उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। उनकी यात्रा में भीड़ तो दिखती थी, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुई। राजद ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सिर्फ 4 सीटों पर मिली। प्रशांत किशोर भी इस दौरान यात्रा पर थे। वह जन सुराज अभियान के तहत बिहार में घूम रहे थे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे थे। उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। वह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए।

अब यात्राओं का दौर समाप्त हुआ और बात नतीजों की हुई। लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव हार गईं। वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की टिकट पर समस्तीपुर लोकसभा सीट से शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र की सांसद बन गईं। दूसरी ओर, लोजपा (रा) की टिकट पर जमुई से चिराग के जीजा अरुण भारती चुनाव जीत गए। लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी जीत गई। जमुई, हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में चिराग की पार्टी ने जीत हासिल की।

अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके थे और बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेता संजय झा को जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंप दी।

पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अगस्त के महीने में एके-47 के मामले में मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया। इस केस में साल 2016 में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। बता दें कि अनंत सिंह के पटना आवास से 24 जून 2015 को रायफल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था। जन सुराज अभियान को प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप दे दिया। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है।

अब साल के अंत में बिहार में धमकियों का दौर शुरू हो गया। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली। कई बार उन्हें वॉट्सएप, फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। साल 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकालने वाले हैं। वहीं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर भी पूरे चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2025 में उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। खैर 2025 के चुनाव में किसका सिक्का चलेगा, वो बिहार की जनता ही बताएगी। उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।

● **विनोद बक्सरी**

बिहार की राजनीति दो फांक

एक देश-एक चुनाव के मुद्दे पर बिहार की राजनीति स्पष्ट तौर पर दो फांक है। इसके समर्थन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ नवगठित जन सुराज पार्टी (जसुपा) भी है। दूसरी ओर महागठबंधन है, जिसे यह विचार कतई स्वीकार्य नहीं। इसके सबसे बड़े घटक राजद द्वारा जगह-जगह पोस्टर लगाकर इसी के समानांतर समान शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था आदि का मुद्दा उछाला जा रहा है। अंदरखाने चर्चा है कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए यह व्यवस्था घातक सिद्ध होगी। यह बात दीगर है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव होने पर मुद्दों के गड्मगड्ड होने और चुनाव परिणाम पर उसके प्रभाव की आशंका है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि जिस कांग्रेस को 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव के जरिए केंद्र और राज्यों की सत्ता में रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी, वह आज विरोध में खड़ी है। आए दिन चुनाव से विकास के काम बाधित होते हैं और सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार का खर्च बढ़ता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल मान रहे हैं कि इस व्यवस्था से राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया में खर्च होने वाले धन और समय का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में किया जा सकता है। जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी यही राय है, बशर्ते कि इस व्यवस्था के पीछे केंद्र की मंशा सही हो। विपक्ष का भय वस्तुतः इस मंशा को लेकर ही है। कांग्रेस इसे महंगाई-बेरोजगारी-असहिष्णुता जैसे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रही है, तो राजद की राय में इस व्यवस्था से संवैधानिक खतरे की आशंका बढ़ेगी।

श्रीलंका से आश्वासन

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की यात्रा से भारत को दो आश्वासन मिले। पहला तो यही कि दिसानायके ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। नई दिल्ली में उसका मतलब यह समझा गया है कि श्रीलंका के मार्क्सवादी राष्ट्रपति की विदेश नीति में भी भारत की अहमियत बनी रहेगी। फिर दिसानायके ने भरोसा दिया कि उनकी सरकार श्रीलंकाई जमीन से किसी भारत विरोधी गतिविधि की इजाजत नहीं देगी। मतलब यह समझा गया कि चीनी खोजी एवं अन्य जहाजों को श्रीलंका में लंगर डालने की अनुमति दी भी गई, तो श्रीलंका सरकार सुनिश्चित करेगी कि वे वहां से भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

दिसानायके अगले महीने चीन जाने वाले हैं। चूंकि भारत में पड़ोसी देशों के चीन से संबंध को लेकर एक खास तरह की संवेदनशीलता रहती है, इसलिए निश्चित रूप से यहां के कूटनीतिकों की नजर उस यात्रा पर रहेगी। फिलहाल, यह साफ हुआ है कि श्रीलंका की नई सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। 2022 में जिस आर्थिक संकट में देश फंसा था, उसके असर से आज भी नहीं उबर पाया है। ऊपर से आईएमएफ से लिए गए कर्ज की शर्तों ने सरकार के लिए नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश के साथ किसी विवाद में उलझनों का जोखिम वहां की सरकार शायद ही उठा सकती है। मगर वह चीन की उपेक्षा करने की स्थिति में भी नहीं है, जिसका बहुत भारी निवेश श्रीलंका में है। संकेत यह है कि दिसानायके इन दोनों बड़े देशों की संवेदनशीलताओं का ख्याल करते हुए फिलहाल दोनों से सद्भावपूर्ण संबंध को प्राथमिकता दे रहे हैं। नई दिल्ली में यह संदेश देने के बाद उनकी कोशिश बीजिंग में भी ऐसा ही पैगाम देने की होगी। बहरहाल, भारत यात्रा के दौरान, जैसा कि अक्सर शिखर नेताओं की यात्रा के समय होता है, कुछ महत्वपूर्ण व्यापार एवं रक्षा समझौते भी हुए। इनसे भी सकारात्मक प्रभाव पैदा हुआ है। भारत के लिए अच्छी बात है कि जिस समय विभिन्न पड़ोसी देशों से चुनौती भरे संकेत आ रहे हैं, श्रीलंका ने उसे आश्वस्त किया है।

श्रीलंका ने माना है कि भारत ने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी और साथ ही उसने वादा किया है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर पहुंचे अनुरा कुमारा दिसानायके ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का वादा भी किया। गत दिनों उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को यकीन दिलाया है कि वे अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका, भारत की मदद से आगे बढ़ेगा और पड़ोसी देश को वे अपना समर्थन देते रहेंगे। दिसानायके ने कहा- हमने करीब दो साल पहले एक बड़े आर्थिक संकट का सामना किया था। भारत ने हमें उस दलदल से बाहर निकलने में बहुत मदद की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा है कि श्रीलंका, भारत की विदेश नीति में अहम जगह रखता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत को चुना है। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी साझेदारी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। इससे पहले दिसानायके का स्वागत राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की गई। दिसानायके ने कहा कि उन्होंने भारत और श्रीलंका के आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। दिसानायके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा- भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान, मुझे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बात करने का मौका मिला। हमारी बातचीत भारत व श्रीलंका के आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, टूरिज्म और एनर्जी जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। पड़ोसी के रूप में भारत और श्रीलंका के बीच केवल कूटनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आपसी सहयोग के स्तर पर भी संबंधों की एक मजबूत कड़ी रही है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

वामपंथी दलों के गठबंधन से राष्ट्रपति बने दिसानायके

कहा जा सकता है कि एक विकट दौर से निकल कर श्रीलंका अब अपनी स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। इस क्रम में भारत के साथ संबंधों के नए अध्याय से भविष्य को लेकर बेहतर उम्मीदें पैदा होती हैं। गौरतलब है कि अनुरा कुमारा दिसानायके जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी के सबसे अहम नेता रहे हैं और उन्होंने वामपंथी दलों के गठबंधन नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी के तहत चुनाव लड़ा था। एनपीपी का भारत विरोधी रुख छिपा नहीं रहा है। इसलिए यह आशंका स्वाभाविक थी कि दिसानायके के सत्ता में पांव मजबूत होने के बाद क्या श्रीलंका की नीति बदलेगी और उसके कदम चीन की ओर बढ़ेंगे! मगर यह भी तथ्य है कि विदेश नीति के मामले में श्रीलंका अब तक गुटनिरपेक्षता की राह पर चलता आया है। आमतौर पर किसी देश की सत्ता के बदलने के बावजूद विदेश नीति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। साथ ही, श्रीलंका और भारत के बीच साझेदारी का एक लंबा सफर रहा है। इसलिए अगर दोनों देश एक-दूसरे के सुरक्षा हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर आगे कदम बढ़ाते हैं तो यह द्विपक्षीय हित में एक जरूरी पहल होगी।

खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध...!

रूस और यूक्रेन जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ युद्ध खत्म करने के लिए संभावित बातचीत में यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है। पुतिन ने कहा कि रूस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत के लिए तैयार है लेकिन उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने की अपनी चाहत को छोड़ देना चाहिए। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने हालांकि इन मांगों को खारिज कर दिया है।

पुतिन ने कहा कि वह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित बातचीत के लिए तैयार हैं, जिन्होंने यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौते पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर हम ट्रंप से मिलते हैं, तो हमारे पास चर्चा करने के लिए मुद्दे होंगे। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, राजनीति समझौता करने की कला है। हमने हमेशा कहा है कि हम बातचीत और समझौते दोनों के लिए तैयार हैं। साथ ही, पुतिन ने कहा कि बातचीत जमीनी हालात के आधार पर होनी चाहिए। पुतिन ने अपने सालाना संवाददाता सम्मेलन और कॉल-इन शो कार्यक्रम में दावा किया कि यूक्रेन में उनके सैन्य अभियान से रूस मजबूत हुआ है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सीरिया में प्रमुख सहयोगी बशर अल-असद को अपदस्थ किए जाने से मॉस्को की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसका इस्तेमाल वह अपने प्रभुत्व का अहसास बनाए रखने और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक नियंत्रण होने का प्रदर्शन करने के लिए करते रहे हैं। यह कार्यक्रम लगभग साढ़े चार घंटे तक चला। पुतिन ने कहा कि मॉस्को ने ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए अपने लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने के जवाब में किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस इस मिसाइल से यूक्रेन पर और अधिक हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल का इस्तेमाल उन देशों के सैन्य परिसरों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्होंने यूक्रेन को रूस में हमले करने के लिए अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। पुतिन ने कहा कि वह सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद से उस अमेरिकी पत्रकार की स्थिति के बारे में पूछेंगे जो 12 साल पहले सीरिया में लापता हो गया था। पुतिन ने कहा कि उन्होंने अभी तक असद से मुलाकात नहीं की है, जिन्हें मॉस्को में शरण दी गई है, लेकिन उनकी उनसे मुलाकात करने की योजना है और वह उनसे अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के बारे में पूछेंगे।

पुतिन के न्यूक्लियर चीफ जनरल इगोर किरिलोव की गत दिनों मॉस्को में हुए एक धमाके में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी (एसबीयू) से जुड़े एक सूत्र ने ली है। यूक्रेन ने एक दिन पहले ही जनरल इगोर को युद्ध अपराधी घोषित किया था। उसका कहना है कि किरिलोव ने ही यूक्रेनी सैनिकों पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के निर्देश दिए थे। उधर रूस का कहना है कि किरिलोव ने यूक्रेन में पेंटागन के बायोलैब्स का पर्दाफाश किया था, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया है। रूस का कहना है कि किरिलोव ने 2 साल पहले यूक्रेन में पेंटागन के बायोलैब्स का खुलासा किया था, जिसके चलते उनकी हत्या की गई है। 54 वर्षीय किरिलोव ने विशेष सैन्य अभियान के दौरान यूक्रेनी प्रयोगशालाओं में पाए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए कथित अमेरिकी जैविक गतिविधियों को उजागर किया था। मार्च 2022 में, उन्होंने दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि यूक्रेन में पेंटागन की ओर से फंडेड बायोलैब में चमगादड़ों और पक्षियों का इस्तेमाल कर जैविक हथियार विकसित किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, किरिलोव ने बताया था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि यूक्रेन की आबादी पर एक्सपेरिमेंट, दवाइयों के परीक्षण और आक्रामक उद्देश्यों के लिए बायोलॉजिकल सैंपल अमेरिका भेजे गए हैं। सितंबर 2023 में किरिलोव ने कैलिफोर्निया के एक अवैध बायोलैब का हवाला देते हुए अमेरिकी बायोलैब नेटवर्क को बायोलॉजिकल खतरा करार दिया, जिसमें कोविड-19, एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे बैक्टीरिया/वायरस को रखा गया था।

● **कुमार विनोद**

सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ी

उन्होंने दावा किया कि 2022 में यूक्रेन में सेना भेजने से रूस की सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसा निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था और रूस को इसके लिए पहले से और अधिक गहन तैयारी करनी चाहिए थी। पुतिन ने कहा कि पिछले दो या तीन सालों में रूस बहुत मजबूत हो गया है क्योंकि यह वास्तव में एक संप्रभु देश बन गया है। उन्होंने कहा, हम अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूती से खड़े हैं, हम अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहे हैं और हमारी सैन्य क्षमता अब दुनिया में सबसे मजबूत है। उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर देश के तेजी से आगे बढ़ने के बारे में बात की और यूक्रेन में अपने सैनिकों की सफलता की सराहना की। पुतिन ने यह भी कहा कि सेना अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति तेजी से बदल रही है, हम अग्रिम मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। रूस द्वारा पिछले महीने पहली बार यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई नई हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पुतिन ने कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों के इस दावे का उपहास उड़ाया कि इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की हवाई सुरक्षा द्वारा रोका जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में 498-ए के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद कहा था। दो दशक बीत चुके हैं लेकिन कानूनी आतंकवाद अब भी कायम है। इससे पहले और कोई अतुल सुभाष अपनी जान दे इस आतंकवाद को रोका जाए। अतुल के जान देने के बाद से लगभग आठ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पत्नी या बहू की प्रताड़ना से त्रस्त लोगों ने जान दी है।

महिला संरक्षण कानूनों का दुरुपयोग

कुछ वर्ष पहले सैयद अहमद मखदूम ने अपनी जान देने के पहले सात मिनट के अपने वीडियो में कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद मेरा बेटा है। मैं उससे मिलने के लिए तिल-तिल मरता हूं। मैं आधा तो उसी दिन मर गया था, जिस दिन मुझे दहेज के झूठे मुकदमे में जेल जाना पड़ा था। मखदूम मास्टर्स इन सोशल वर्क थे। उन पर पत्नी द्वारा दहेज का झूठा आरोप लगाया गया। उन्हें जेल जाना पड़ा और अपने बेटे से दूर होना पड़ा। उन्होंने न्यायालय में लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब समझ आया कि कानून बिल्कुल एकतरफा है तो उम्मीद छोड़ दी।

इस समय देश ऐसी ही एक और आत्महत्या देखकर रो रहा है। पत्नी से प्रताड़ित होकर बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष के सुसाइड वीडियो और 24 पन्नों के नोट ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर महिलाओं के संरक्षण के उपाय पुरुषों की जान क्यों ले रहे हैं? न्याय प्रणाली इतनी एकतरफा कैसे हो गई कि आदमी जान दे दे रहा है? उन कानूनों का धड़ल्ले से मजाक क्यों उड़ाया जा रहा, जो महिलाओं के संरक्षण के लिए लाए गए और कैसे महिलाओं ने ही इन कानूनों को उगाही का जरिया बना लिया है?

यह किसी से छिपा नहीं रह सका है कि झूठे मुकदमों की सूची अंतहीन रूप से लंबी होती जा रही है। पूरे के पूरे परिवार को दहेज के झूठे केस में फंसा देना, आपसी विवाद में दुष्कर्म का आरोप लगा देना, बायफ्रेंड से ब्रेकअप पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाना, लड़ाई हो जाए तो छेड़छाड़ बता देना, बॉस नौकरी से निकाल दे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट बताना, बच्चे की कस्टडी हथियाने के लिए पिता पर ही पॉक्सो लगाना अब आम हो गया है। अनगिनत उदाहरण हैं, जो लोग अपने आसपास देख रहे हैं। विडंबना यह है कि पुलिस सबकुछ जानते हुए भी झूठे मामलों को रद्द नहीं करती। लंबे ट्रायल के बाद जब कभी न्यायालय पुरुष को निर्दोष करार कर देते हैं तो भी महिलाओं को हर्जाना भरने को नहीं कहते। यह कैसा न्याय है?

मप्र उच्च न्यायालय ने हाल में एक पति के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए मुकदमे को रद्द कर दिया। प्रेम विवाह के बाद एक साल चली इस शादी में पति तलाक की अर्जी लगाता है। इससे पत्नी इतनी आक्रोशित हो जाती है कि न केवल 498-ए और दहेज का झूठा आरोप लगाती है, बल्कि ससुर पर दुष्कर्म और देवर पर छेड़छाड़ का झूठा मामला भी दर्ज कराती है। परिवार के सभी लोगों को लपेटते हुए 11 धाराएं लगाई जाती हैं। न्यायालय इन सबको सिरे से झूठा कहकर केस रद्द कर देता है, लेकिन महिला को हजार रुपए तक का भी हर्जाना भरने को नहीं कहा जाता। सोचिए अगर कोई पुरुष ऐसा झूठा मामला बनाता तो उसे कितनी घृणा और सजा मिलती। उक्त मामले में महिला को कोई सजा नहीं मिली।

अब यह आम बात हो गई है कि झूठे केस लगाओ और पैसे उगाहो। यही बात अतुल ने भी अपने अंतिम शब्दों में कही। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपनी ही कमाई अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली दफा है कि किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली और कोहराम मच गया। न जाने कितने अतुल सुभाष मर चुके हैं, लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं, लेकिन समाज दशकों से यह देखते हुए भी चुप रहा, क्योंकि पुरुषों के हित की बात भी महिलाओं के खिलाफ समझी जाती है और फेमिनिज्म और नारीवाद के जमाने में कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। अब अतुल सुभाष की आत्महत्या ने लोगों को प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया है। उनकी आत्महत्या ने देश में वैसी लौ जला दी है, जैसी निर्भया के समय महिलाओं के न्याय और सम्मान के लिए जली थी।

लोग कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत आसार नहीं कि झूठे मुकदमों के सिलसिले को थामने के कोई ठोस जतन होंगे। क्या एक पुरुष की जिंदगी की हमारे देश में कोई कीमत नहीं? जितना उबाल अतुल सुभाष के केस को लेकर है, उतना अगर किसी महिला की मृत्यु पर होता तो संसद में महिला सुरक्षा पर सौ सवाल उठ रहे होते और कानून की कमियों पर चर्चा हो रही होती। हर किसी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री को संदेश देना चाहिए कि अब बदलाव की जरूरत है।

● **ज्योत्सना**

दो दशक बाद भी कानूनी आतंकवाद कायम

कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि सिर्फ एक पहल। पहल एक कमेटी बनाने से की जा सकती है। जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी निर्भया कांड के समय बनी थी, वैसी ही अब महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग और पुरुषों के ऊपर बढ़ती ज्यादतियों को देखने और समझने के लिए बननी चाहिए। कमेटी पूरे देश से सुझाव मांग सकती है। उसे महिला संरक्षण के कानूनों के दुरुपयोग के आंकड़े गहनता से देखने चाहिए। इसके बाद जरूरी बदलाव के कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में 498-ए के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद कहा था। दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन कानूनी आतंकवाद अब भी कायम है। इससे पहले और कोई अतुल सुभाष अपनी जान दे, इस आतंकवाद को रोका जाए। अतुल के जान देने के बाद से लगभग आठ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पत्नी या बहू की प्रताड़ना से त्रस्त लोगों ने जान दी है। इन लोगों की मौतों को सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी देश के ही नागरिक थे।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

सामाजिक

मनोज, सोशल मीडिया- इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर ही नहीं; प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क में भी अग्रणी ही था। सभी के दुख-सुख में भागीदारी करता था। दिखावे के लिए नहीं, वह दुख-सुख में तादातम्य बिठाकार उनकी संवेदनाओं का साझीदार बन जाया करता था। सच्चे अर्थों में सहानुभूति ही नहीं, परानुभूति वाला प्राणी था। उसकी सामाजिकता का लाभ बाहरी ही नहीं, परिवार व गांव के लोग भी उठाया करते थे। इसी कारण उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता जा रहा था।

देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण तिरंगा रैली का आयोजन था। उसे सफल बनाने के लिए मनोज एक माह से जी-जान लगाए हुए था। नौकरी भी करनी थी। आज व्यस्तता के कारण नौकरी पर जाने में विलंब हो गया था। अधिकारी की डांट भी खानी पड़ी; अनुपस्थिति लगी वह अलग। इस प्रकार काम का तनाव भी उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था।

मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। घर आते-आते दोपहर हो गई। बुजुर्ग माता-पिता सुबह से ही प्रतीक्षारत थे। मां, भूखे पेट होने के कारण दवा भी नहीं ले पाई थी।

उसकी पत्नी ने गुस्से में कुछ बनाया नहीं था। स्कूल जाते बच्चे के टिफिन में भी बिस्कुट की पैकिट रख दी थी। जिम्मेदारियों के बोझ तले, कुछ कंजूस हो गई थी। अत: सुबह से न कुछ खाया था और न ही अपने सास-ससुर के लिए कुछ बनाया था। उसे यह भी लगता था कि सास-ससुर के लिए कितना भी करे, ये तो उसकी बुराई ही करते हैं। उसी के गले पड़ गए हैं। खिलाए भी और सुने भी, और भी तो बेटे-बहू हैं, हम ही क्यों करें?

मां! बेटे के तनाव को देखते हुए, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसे उखड़ रही थीं। हिम्मत करके कहना ही पड़ा, बेटा! सुबह से कहां था? बहू ने सुबह से खाने के लिए कुछ बनाया भी नहीं।

मनोज मां-बाप की नजर बचाकर अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश कर रहा था, झुझला पड़ा, नहीं बनाया तो उसने भी तो नहीं खाया। मैंने कहां कुछ खाया है? अभी बारह ही तो बजे हैं। बना देगी खाना। हल्ला क्यों मचा रखा है?

मां! बेटे की मजबूरी और विवशता को समझते हुए चुप रह गई। वह कर भी क्या सकती थी? सिवाय आंसुओं के पी जाने के क्योंकि उसका बेटा सामाजिक था।

- डॉ. संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी

काम का सम्मान

यार रघु, तुम्हें अब भी सब्जी का ठेला लगाते हुए संकोच नहीं होता?

संकोच? क्यों भला? पिछले 26 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। अब काहे का संकोच?

अरे भाई, अब तो तुम्हारा बेटा डीएसपी बन गया है। क्या सोचता होगा वह भी। भाई, अब तो तुम्हें घर में बैठकर आराम करना चाहिए।

हूं, देख भाई, मेरी नजर में कोई भी काम छोटा नहीं होता। यह बात मेरा बेटा भी अच्छे से जानता है। वह भी मुझे कई बार ये काम बंद कर आराम करने के लिए कह चुका है। पर भाई अपना तो कॉन्सेप्ट क्लीयर है। जब तक मेरे हाथ-पैर चलते रहेंगे, काम करता रहूंगा। मैं अपने बेटे को भी हमेशा समझाता हूं कि बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सबका अपना अलग ही महत्व है। इसके साथ ही हमें कभी अपनी जड़ से कटकर नहीं रहना चाहिए। यही कारण है कि वह भी रोज सुबह सोकर उठते ही अपनी मम्मी और मुझे ही नहीं, इस ठेले को भी प्रणाम करता है; क्योंकि वह जानता है कि आज उसके पास जो कुछ भी है, उसमें इस इस ठेले की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

वाह यार, सैल्यूट है तुझे और तुम्हारे बेटे की सोच को।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

अकेला रोता हूँ...

मैं नित-रोज अकेला छुप-छुपकर,
दुनिया से अकेला रोता हूं।
बीती उन यादों की मस्ती को,
अब गीत बनाकर गाता हूं।
अफसोस बचा है इस जीवन में,
सिसकी भर-भर रोने को।
लूटा दिया था वो स्वर्णिम सवेरा
क्या शेष रहा अब खोने को।
मैं नित-रोज अकेला छुप-छुपकर,
दुनिया से अकेला रोता हूं।
नादान दौर के वो किस्सें
अब किसी और के हिस्से में।
मुसकाने दो पागल बनकर
प्यार-वफा की कसमों में।
सुनाएगा लुट-लुट कर फिर
कोई गाथा नए तराने नगमों में।
मैं नित-रोज अकेला छुप-छुपकर
दुनिया से अकेला रोता हूं।
सस्ती है यौवन में मस्ती,
धूल उड़ाते, धुआं फेंकते
पान चबाते पीक मारते जर्दे में मर्दानी है,
लज्जा के थोड़े यूं मुस्काते
प्रेमवीर ये नादानी है।
मैं नित-रोज अकेला छुप-छुपकर
दुनिया से अकेला रोता हूं।
फैला के मंजर बर्बादी,
आग लगाकर अपने ही घर को।
आहुति दी निज जीवन की,
स्वाहा किया मूर्ख मंत्र मित्रों से।
याद सताती प्यार वफा की,
किसी खफा हो जाने से।
मार कुल्हाड़ी निज पैर पर
उपदेश बांचते ब्रह्मा का।
मैं नित-रोज अकेला छुप-छुपकर
दुनिया से अकेला रोता हूं।
क्या करते दुनिया से शिकायत
वक्त को मैं समझा ही नहीं,
ताकत देता था जो जलवा
मंजर बर्बादी छोड़ गया
अफसोस रहा अब इस जीवन में
जीवन की मधुरता बिखर गई।
मैं नित-रोज अकेला छुप-छुपकर
दुनिया से अकेला रोता हूं।

- डॉ. राजेश कुमार बिंवाल

शतरंज के महारथी बने डी गुकेश

भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बने गुकेश

भारतीय शतरंज की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं गुकेश। और सबसे बड़ी बात है कि अपने छोटे-से करियर में वह समय-समय पर अपनी प्रतिभा की झलक दिखलाते रहे हैं। जब महज 17 दिनों से वह दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बनने से चूक गए थे, तभी से इस दिन का इंतजार शुरू हो गया था कि कब वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करेंगे। हर महान उपलब्धि मेहनत और जुनून मांगती है। गुकेश को करीब से देखने वाले जानते हैं कि उन्होंने चेस बोर्ड को इससे कहीं बढ़कर दिया। उनके तैयारी करने का ढंग हो या एकाग्रता, तारीफ उनके विरोधी खिलाड़ी भी करते रहे हैं। तभी तो खिताबी चूक के बाद भी लिरेन अपनी हार से ज्यादा गुकेश की जीत पर बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। भारतीय खेल परिदृश्य के नजरिए से देखा जाए, तो गुकेश ताजी हवा के झोंके की तरह हैं, जिन्होंने चारों तरफ हलचल मचा दी है। शतरंज को दिमागदार लोगों का खेल माना जाता है और यह है भी, लेकिन इसे आम लोगों के बीच ले जाने में गुकेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। याद रखिए, किसी भी खेल में कोई भी देश तब तक बेहतर नहीं कर सकता, जब तक कि युवा पीढ़ी उसमें रूचि न ले। हमें शतरंज में विश्वनाथन आनंद का नाम सुनने की आदत रही है, लेकिन अब गुकेश का नाम भी जोड़ने का वक्त आ गया है।

महज 18 साल में 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर तमिलनाडु के गुकेश डोमाराजा ने इतिहास रच दिया। रोमांचक मुकाबले में चीन के डिंग लिरेन को हराकर वे विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय और यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। शतरंज की दुनिया में भारत का नाम रौशन करने वाले डी. गुकेश ने कड़ी मेहनत, लगन और असाधारण प्रतिभा के दम पर खुद को महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। कम उम्र से ही शतरंज के कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुकेश ने भारतीय शतरंज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विश्व चैंपियनशिप जीतने पर गुकेश को 11.45 करोड़ रुपए की ईनामी राशि मिली है। गुकेश का कहना है कि वे पैसे के लिए शतरंज नहीं खेलते हैं। वे जीत के पल का आनंद लेने के लिए खेलते हैं। वे कहते हैं, बचपन से ही चेसबोर्ड मुझे बहुत पसंद है। यह मेरा पसंदीदा खिलौना रहा है। शतंरज मेरा पहला प्यार है।

29 मई 2006 को चेन्नई, तमिलनाडु में जन्मे गुकेश के पिता रजनीकांत पेशे से नाक, कान, गला विशेषज्ञ हैं। मां पद्मा भी डॉक्टर हैं। तेलुगु भाषी गुकेश के माता-पिता ने कम उम्र में ही उनकी शतरंज खेलने की प्रतिभा को पहचान लिया था और और उन्हें शतरंज खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। महज 7 साल की उम्र से उन्होंने शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। गुकेश बिना किसी बाधा के शतरंज खेल पाएं इसके लिए पिता रजनीकांत ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वे लगातार उन्हें दूसरे शहरों में शतरंज खेलने के लिए ले जाते रहते थे। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थितियां शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ाई लेकिन उनकी मां ने घर की हर तरह की जिम्मेदारी संभाली। गुकेश ने भी माता-पिता की मेहनत का मान रखा और जल्द ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। 2018 में विश्व अंडर-12 शतरंज चैंपियनशिप जीतकर पहली बार वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। सिर्फ 12 साल, 7 महीने और 17 दिन की उम्र में उन्होंने 2019 में ग्रैंडमास्टर का खिताब जीत लिया था। वे विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बने और भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। 2023 में गुकेश ने 2750 ईलओ रेटिंग को पार कर दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बनाई। वे विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को भी हरा चुके हैं। साल 2022 के शतरंज ओलंपियाड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और भारत की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल कर चुके गुकेश की ताकत उनकी एकाग्रता है।

गुकेश आक्रामक और रचनात्मक ढंग से खेलते हैं। यह उनकी विशिष्ट शैली है। 2022 में वे चेसेबल मास्टर्स और 2023 में फीडे वर्ल्डकप जीत चुके हैं। उनकी सफलता का सबसे अहम पड़ाव 2023 में विश्व चैंपियन बनने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। गुकेश के खेल में विश्वनाथन आनंद की झलक मिलती है। खासकर उनकी प्रतिभा, समर्पण और खेल भावना में। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे आनंद की नकल करते हैं। उनकी अपनी अनूठी शैली और दृष्टिकोण है, जिसके साथ वे भारतीय शतरंज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आनंद की तरह, गुकेश भी भारतीय शतरंज के दिग्गज बनने की राह पर हैं और उनकी मेहनत देखकर लगता है कि वे ही आनंद विरासत के सच्चे अधिकारी होंगे। वैसे भी विश्वनाथन आनंद और गुकेश के बीच गुरु-शिष्य का संबंध है। 2020 में, आनंद ने वेस्टब्रिज आनंद चेस अकादमी (डब्ल्यूएसीए) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारतीय युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करना है। गुकेश इस अकादमी के प्रमुख छात्रों में हैं। आनंद ने गुकेश के खेल को निखारने और उनकी मानसिक तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे न केवल गुकेश को तकनीकी सलाह देते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक दबाव झेलने और बड़े टूर्नामेंट में प्रदर्शन करने के गुर भी सिखाते हैं।

गुकेश अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार, कोच और कड़ी मेहनत को देते हैं। गुकेश की विश्व चैंपियन बनने की यात्रा किसी सपने से कम नहीं है। उनके माता-पिता ने उन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत की है। गुकेश की जीत के साथ कहा जा सकता है कि शतरंज में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। विश्वनाथन आनंद की विरासत संभालने के लिए डी. गुकेश के साथ प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगैसी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। गुकेश की उपलब्धि को किस तरह आंका जाए, शायद यह सवाल बहुतों को मथ रहा होगा। क्रिकेट को धर्म की तरह मानने वाले इस देश में दूसरे खेलों के साथ अक्सर यह संकट आता है। तो गुकेश ने जो मकाम हासिल किया है, उसकी चमक किसी विश्व कप या ओलिंपिक्स के किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं, बल्कि उससे अधिक ही आंकी जाएगी। पहली बार इतनी कम उम्र के किसी खिलाड़ी ने शतरंज पर इस तरह की महारथ हासिल की है। यह जादू इससे पहले गैरी कैस्परोव ने किया था, लेकिन तब वह 22 साल के थे।

● आशीष नेमा

कभी साइन करने के लिए लगती थी मेकर्स की लाइन... आज 1 फिल्म को तरस रहा ये सुपरस्टार

90 के दशक में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा मेकर्स की पहली पसंद हुआ करते थे। उन्होंने सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया है। अपने करियर में उन्होंने कई ऐसी ब्लॉकबस्टर हिट दी हैं जिन्हें लोग शायद ही कभी भुला पाए। लेकिन समय ने ऐसा करवट लिया कि वह आज फिल्मी दुनिया से दूर हैं।

गोविंदा ने अपने हर किरदार के साथ पूरी तरह न्याय किया है। इंडस्ट्री में उन्हें वो पहचान मिली जिसे पाना किसी भी एक्टर के लिए कोई आसान बात नहीं। अपने करियर में उन्हें जो काम मिला वह करते गए। गोविंदा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वह कभी आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें जो काम मिलता है, वह करते हैं। उन्हें सब करना अच्छा लगता है, वह कभी भविष्य की चिंता नहीं करते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। अपना आज अच्छे से जीना चाहिए।

कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए...

गोविंदा ने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अब तक के करियर में उन्होंने कई अहम रिकॉर्ड भी दर्ज किए। एक एक्ट्रेस के ही साथ उन्होंने तकरीबन 14 फिल्मों में काम किया था। वो थीं नीलम, जिनके साथ उनके अफेयर की भी खूब अफवाहें उड़ी थीं।

एक बार में साइन कर दी थीं 70 फिल्में...

गोविंदा से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वह एक बार में कितनी फिल्में साइन करते हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बार में 70 फिल्में साइन की थीं। लेकिन फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पाए तो उन्होंने कुछ फिल्में छोड़ भी दी थीं। ये वो दौर था जब मेकर्स गोविंदा को साइन करने के लिए लाइन में रहते थे। करियर की शुरुआत में तो वह हर तरह के किरदार निभा लिया करते थे। अपने एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मां कहती हैं जो काम मिल रहा है उसे करो। फिर आपको काम मिल रहा है इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। लेकिन शायद उनका यूं कल के बारे में ना सोचना ही गलत हुआ कि वह आज 1 फिल्म में काम करने को तरस रहे हैं।

डायरेक्टर बनकर दे डाली सुपरहिट फिल्म... एक्टिंग ने बर्बाद किया करियर

सोहेल खान ने अपने एक्टिंग करियर में ज्यादातर फ्लॉप फिल्मों में ही काम किया है। करियर की शुरुआत ही उनकी फ्लॉप फिल्म से हुई थी। करियर की कोई भी फिल्म उन्हें सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचा पाई। लेकिन बतौर डायरेक्टर वह सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं।

सोहेल खान ने साल 2002 में आई फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर सोहेल खान ही थे। लेकिन ये फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद भी सोहेल खान ने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन वह फ्लॉप की झड़ी लगाकर रह गए। अपने 17 साल के करियर में वह अपने दम पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाए। सोहेल खान एक्टिंग की दुनिया में भले नाम नहीं कमा पाए हों, लेकिन बतौर डायरेक्टर उन्होंने एक फिल्म से धमाल मचा दिया था। साल 1998 में उन्होंने धर्मेंद्र को कास्ट करते हुए एक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम प्यार किया तो डरना क्या है। फिल्म में सलमान खान, काजोल लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में अरबाज खान भी नजर आए थे। बता दें कि सोहेल खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। साल 1998 में उन्होंने घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई थी। लेकिन साल 2022 में दोनों ने तलाक की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया था। इस शादी से उनके दो बेटे निर्वाण और योहान खान हैं।

कभी स्कूल की फीस भरने के नहीं थे पैसे, बिस्किट खाकर भी गुजारी रातें

दे डाली 850 करोड़ कमाने वाली फिल्म

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने हमेशा अपने एक्टिंग टैलेंट से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। साल 2024 में तो उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 से फैंस को हैरान कर दिया था। लेकिन आज करोड़ों कमाने वाला राजकुमार राव ने कभी बिस्किट खाकर भी गुजारा किया था।

ट्रैप्ड, न्यूटन, शादी में जरूर आना या स्त्री 2 जैसी फिल्मों में अपने किरदार से दर्शकों के होश उड़ाने वाले राजकुमार राव आज मेकर्स की पहली पसंद हैं। उन्होंने अब तक कई यादगार किरदार निभाए हैं। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया है। आज राजकुमार राव बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले तो उन्होंने आर्थिक तंगी भी झेली है। राजकुमार राव ने साल 2010 में करियर की शुरुआत की थी। आज वह इंडस्ट्री में एक खास पहचान बना चुके हैं। लेकिन करियर की शुरुआत में उन्होंने कई फिल्मों में छोटे रोल या साइड रोल भी निभाने पड़े थे।

थूक...

हारकर 4 पंडे और आए और उसे जबरन घसीटकर मंदिर से बाहर ले गए। गुस्से में आगबबूला होकर पंडे उसे गालियां देने लगे। कुछ पंडे उस पर लातें चला रहे थे, तो कई घूंसे जमा रहे थे। थोड़ी देर बाद वह कोढ़ी लहूलुहान होकर सीढ़ी के किनारे आ बैठा। मैंने उसकी हालत देखकर कहा, अरे, यह क्या कर दिया?

केदारनाथ धाम में मुंबई के मेरे एक दोस्त पिछले दिनों केदारनाथ धाम आए थे। अपने आने की खबर उन्होंने मुझे पहले से दे दी थी। वे एक होटल में ठहरे थे। उनसे मुलाकात करके मैं वापस लौट रहा था। रास्ते में देखा कि एक कोढ़ी खस्ता हालत में शिवलिंग के दर्शन के लिए गुजरात से आया था।

वह कोढ़ी पूरी शिद्दत से मंदिर के अंदर चला गया। सब लोग लाइन में खड़े थे, तभी उस कोढ़ी के पास एक पंडा आया। उस कोढ़ी ने जेब से 500 रुपए निकालकर पंडे को दे दिए। पंडा उसे स्पेशल पूजा के रास्ते से मंदिर के भीतर ले गया।

पूजा के बाद पंडा तो खिसक गया, लेकिन उस कोढ़ी ने शिवलिंग को कस कर पकड़ते हुए कहा, महाराज, मैं गुजरात से आया हूं। न जाने मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था, जो मैं कोढ़ी हो गया।

वह कोढ़ी शिवलिंग पर ऐसे चिपटा हुआ था, मानो उसका कोढ़ गायब हो जाएगा। वह शिवलिंग को छोड़ने के मूड में नहीं था, तभी वहां तमाम भक्तों की भीड़ लग गई। सभी दर्शनों के लिए बेचैन थे। दूसरे पंडे उसे शिवलिंग को छोड़ने के लिए लगातार कह रहे थे, पर वह उनकी बात न सुनकर केवल रोए जा रहा था।

हारकर 4 पंडे और आए और उसे जबरन घसीटकर मंदिर से बाहर ले गए। गुस्से में आगबबूला होकर पंडे उसे गालियां देने लगे। कुछ पंडे उस पर लातें चला रहे थे, तो कई घूंसे जमा रहे थे। थोड़ी देर बाद वह कोढ़ी लहूलुहान होकर सीढ़ी के किनारे आ बैठा। मैंने उसकी हालत देखकर कहा, अरे, यह क्या कर दिया?

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुझे कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए नागपुर जाना था। मैंने स्टेशन पर पता किया कि नागपुर के लिए गाड़ी रात के 3 बजे मिलेगी। मैं रात के 12 बजे स्टेशन पहुंच गया। मैंने सोचा कि 3 घंटे टहलते-टहलते कट जाएंगे।

मैं प्लेटफार्म नंबर 5 पर आया और एक लोहे की बैंच पर बैठ गया। मेरे बगल वाली बैंच पर धोती-कुरता पहने एक साहब गहरी नींद में सोए हुए थे।

मेरी दाईं तरफ एक साहब व उनकी बीवी और 2 बच्चे एक बैंच पर बैठे थे। शायद वे भी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उनके बच्चे बहुत नटखट नजर आ रहे थे। उनकी मम्मी उन्हें बिट्टू व पिंटू नाम से पुकार रही थीं।

वे दोनों बच्चे मेरे बगल वाली बैंच पर सो रहे साहब को नाना पाटेकर कह रहे थे। एक भिखारी व एक भिखारिन को वे अनिल कपूर व जूही चावला कह रहे थे।

अचानक वे दोनों बच्चे मेरी बगल वाली बैंच पर सोए हुए साहब की बैंच पर बैठ गए और उन में से एक ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, हम नाना पाटेकर के साथ बैठे हैं। उनकी मम्मी मुस्कुराते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा करने लगीं।

वे दोनों बच्चे उन साहब के नीचे रखे जूतों को इस तरह देख रहे थे, मानो जूतों की तहकीकात कर रहे हों। फिर उन दोनों ने जूतों में पेशाब करना शुरू कर दिया। वे पेशाब की धार की गिनती गिनने लगे। बिट्टू ने 50 की गिनती तक जूता भरा, जबकि पिंटू ने 30 की गिनती में ही जूता भर दिया। इसके बाद वे दोनों अपनी मम्मी के पास चले गए।

तभी एक पुलिस वाला आया। उसने सोए हुए आदमी को डंडा चुभाकर कहा, अबे ओ घोंचू, घर में सोया है क्या? उन साहब की नींद खुली और वे जूता पहनने लगे कि जूतों में भरे पेशाब ने वहां का फर्श गीला कर दिया।

अरे, यह क्या किया। जूतों में पेशाब करके सो रहा था। प्रदूषण फैलाता है। तुझे सामने लिखा नहीं दिखाई दिया कि गंदगी फैलाने वाले से 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। चल थाने, कहकर पुलिस वाला उसे थाने ले जाने लगा।

वे साहब चलते-चलते गिड़गिड़ाने लगे, नहीं जनाब, मैंने पेशाब नहीं किया...।

पुलिस वाले ने उनकी एक न सुनी। वह उन्हें प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ ले गया।

मैंने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा। वे भी सारा माजरा समझ गए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, अभी तो फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर शुरू नहीं हुई।

मैं धीरे से कहने लगा, अरे, यह क्या कर दिया?

राजस्थान की बस में मैं अजमेर में एक अखबार में सहायक संपादक था। प्रधान संपादक ने मुझे निजी काम से दिल्ली भेजा था। मैं अजमेर से दिल्ली के लिए सुबह बस से चला था। जयपुर से आगे एक छोटे शहर में बस का टायर पंचर हो गया। सभी सवारियां समय बिताने व कुछ खाने-पीने के लिए आसपास की दुकानों में चली गईं।

मैं एक पेड़ की छाया में बैठ गया। बगल वाली गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी वहां से एक गधा गुजरा। गधे को देखकर बच्चों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। 3 बच्चे गधे पर सवार हो गए और 2 बच्चे डंडे से पीटते हुए उसे दौड़ाने लगे। गधा ढेंचू...ढेंचू... करता हुआ दौड़ता जा रहा था। सभी सवारियां यह तमाशा देख रही थीं। हमारी बस का ड्राइवर लंबी चोटी रखे हुए था। वे बच्चे ड्राइवर को चिढ़ाने लगे, चोटी वाला साबुन क्या भाव है?

ड्राइवर को गुस्सा आ गया। उसने सड़क के किनारे पड़ा एक पुराना सैल उठाया और बच्चों की तरफ फेंक दिया। सैल एक बच्चे की खोपड़ी में जोर से लगा और उसकी खोपड़ी से खून बहने लगा। बस का टायर बदला जा चुका था। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। सब सवारियां बस में बैठ गईं और बस दिल्ली की तरफ चल पड़ी। रेवाड़ी पहुंचते ही पुलिस ने बस को घेर लिया और ड्राइवर को हथकड़ी पहना दी।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

सौजन्य से:- आशुतोष व्यास फ्रेंड्स क्लब इंदौर (म.प्र.)

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687